

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 मार्च, 1977

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार 28 मार्च, 1977

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)1
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)10
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(7)22

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 28 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन,
सैक्टर-1, चंडीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह)
ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Sterilization cases

***1952 Chauhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Industries be please to state the district wise total number of persons who have been sterilized under the Family Planning Programme in the State during the calendar year 1975 and 1976, separately?

Industries Minister (Shri Harpal Singh):-

Number of persons sterilized district wise during the calendar years 1975 and 1976 in the State of Haryana is as follows:-

Sr. No.	District	1975	1976
1	Ambala	6655	27700

2	Bhiwani	3298	12004
3	Gurgaon	7324	49895
4	Hissar	6848	29582
5	Jind	4670	19733
6	Karnal	4290	19894
7	Kurukshetra	3399	17264
8	Mohindergarh	4508	20665
9	Rohtak	4831	14735
10	Sirsa	4155	10090
11	Sonepat	3971	10798
	Total	53949	232360

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंखी महोदय बताने की करेंगे कि 1976 का जो कोटा फिक्स हुआ था उससे ज्यादा केसिज स्टरलाइज हुए या कम हुए हैं?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, 52 हजार का कोटा फिक्स हुआ था उससे काफी ज्यादा हुए हैं।

चौधरी िव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किस किस महकमें ने कितने केसिज स्टरलाइज कराए हैं ? क्या वे ब्रेक अप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, इसमें तो सारी स्टेट की फिगर दिखाई है अलग अलग महकमे की बात नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके नोटिस में ऐसी कोई रिक्वायत आई है जहां पर जबरदस्ती की गई हो ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने फैमिली प्लानिंग पर आन दी फ्लोर आफ दी हाउस एक स्टेटमेंट दी थी और मैं समझता हूं कि उसके बाद उस पर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस के महकमे ने कितने नसबंदी कराई है, उनका खते पर कितनी फिगर लिखी हुई है ?

Mr. Speaker: Order please. The reply has already come कि अलग से किसी डिपार्टमेंट की फिगर नहीं है।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग खाता नहीं है?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, कोई खाता अलग नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि अगले साल का कोटा कितना फिक्स किया हुआ है ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, अगला साल भुरू होगा तो बात करेंगे ।

चौधरी पीर चंद: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो फिगर स्टरलाइजे ान की उन्होंने बताई है उनमे औरते कितनी है और आदमी कितने है ।

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, अगर अलग से नोटिस दे तो बता देंगे ।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि अगर जोर जबरदस्ती के केस उनके नोटिस मे लाएं तो क्या सरकार इंकवायरी करवाएगी ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदया ने पहले जैसे बताया है कि अगर उनके नोटिस मे ज्यादाती के केस जाएंगे तो इंकवायरी करायी जायेगी ।

चौधरी ि तव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय अपने रिकार्ड मे देखकर सारे सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट के खाते मे कितने केस लिखे हुए है ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, किसी डिपार्टमेंट का सैपरेट खाता नहीं लिखा हुआ है।

चौधरी पीर चंद: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के एक भी बच्चा नहीं था उनका भी जबरदस्ती आप्रेशन कर दिया गया, क्या उसको ठीक करवाया जाएगा ?

श्री हरपाल सिंह: हमारे नोटिस में तो कोई ऐसा केस है नहीं। अगर कोई नोटिस में इस तरह का केस लाया जाएगा तो उसको ठीक करवा देंगे।

श्री हरस्वरूप बूरा: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके नोटिस में कोई ऐसे केसिज है जिनमें आप्रेशन न करवाने के सिलसिले में लोगों की तनखाह रोकੀ गई ? क्या यह जबरदस्ती नहीं है ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, किसी की तनखाह नहीं रोकी गई, सबको तनखाह मिली है।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि नसबंदी का कोटा पूरा हो गया है या कुद बाकी रहता है ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब अब ये ऊपर से भुरु करेंगे तब फिर वैसे ही काम चलेगा।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि जो टोटल बताया गया था उनमें हरिजन कितने हैं ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, कम्युनिटी वाइज फिगरज इसमें नहीं है।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे केसिज भी नोटिस में हैं जो इलिजिवल नहीं हैं लेकिन पैसे लेने के लिए आप्रेशन करवा लिया है ?

श्री हरपाल सिंह: ऐसे केसिज नोटिस में नहीं हैं।

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि लगभग सभी महकमों में सर्विस रूलज में तबदीली करके कर्मचारियों को नसबंदी करवाने के लिए बाध्य किया गया है क्या इसको जबरदस्ती मानते हैं या रजामंदी गिनते ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, अब तो इस बारे में स्टेटमेंट दे दी गई है कि कोई जबरदस्ती नहीं होगी, परसूएशन से ही कोई बात होगी और किसी को डिसेन्सिटिव नहीं होगा।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी मुलाजिमों पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई थी कि जब तक आप्रेशन नहीं करवाएंगे उनको तनखाह नहीं मिलेगी ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी।

चौधरी देवी लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके नोटिस में यह चीज है कि महेन्द्रगढ़ जेल के तमाम बारडर्न की तनखाह बंद की गई और रणजीत सिंह बारडर को यह कहा गया कि जब तक आप्रें इन हनी कराओंगे तनखाह नहीं मिलेगी ? क्या हाउस में * * * बोलने की भी इजाजत है ?

Mr. Speaker: Order please. In Question Hour there can be no point of order. Only supplementary questions can be asked.

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): स्पीकर साहब, मेरी एक गुजारि है कि * * भाब्द अनपार्लियामेंटरी हे इसको एकसपंज किया जाये और दूसरी बात यह है कि चौधरी देवी लाल बहुत पुराने पार्लियामेंटरीयन है वह अपनी सीट से सप्लीमेंटरी क्वै न कर सकते है किसी दूसरी सीट से प्र न नहीं पूछ सकते।

Mr. Speaker: This is correct. अगर किसी मिनिस्टर को यह आनरेबल मँबर को यह कहा जाये कि झूठ बोल रहा है यह अनपार्लियामेंटरी है। It should not be said.

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात की जांच की जाएगी कि कई महकमों में

सरकारी मुलाजिमों की कइ कई माह तक तनखाह रोक़ी गई और उनसे कहा गया कि या तो नसबंदी कराओ वरना नौकरी से हटा दिए जाओगे ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टांस नोटिस मे लाएंगे तो इंकवायरी करा लेंगे ।

चौधरी पीर चंद: स्पीकर साहब, अभी फरमाया गया है कि इस प्रोग्राम को आगे भुरु करेंगे । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह टारगेट इन्होंने फिक्स किया था कि अपनी मर्जी से आप्रे न करतें रहे है ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया था ।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि नये माल यानी 1977 मे भी ये इस प्रोग्राम को भुरु करेंगे ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, नया साल 31 मार्च के बाद भुरु होता है ।

Procurement of Food Grains

***1764. Chaudhri Rizaq Ram:** Will the Minister for Excise & Taxation be pleased to state—

- (a) The quantity of wheat, paddy/rice and other food grains procured in the State through different agencies during the year 1976-77 (to-date) separately; and
- (b) The price at which the different food grains were procured during the period as referred to in part (a) above?

Excise & Taxation Minister (Shri Shyam Chand):

- (a) & (b) The information is laid on the table of the House.

Statement

- (a) (i) Wheat 9.07 lac tonnes upto 28-2-1977.
(ii) Rice 5.14 lac tonnes upto 1-3-1977.
(iii) Paddy is not procured by State procuring agencies. It is purchased by Rice Millers who sell rice to State Government under levy scheme. However, Food Corporation of India enters market to procure paddy if rates fall below the procurement price. Food Corporation of India have procured 0.69 lac tonnes of paddy this year and the rice Millers have purchased 0.14 lac tonnes
- (b) The procurement was made at the following procurement/support prices fixed by the Government of India:-

Wheat	
Grade-I	Rs. 105.00 per quintal
Grade-II	Rs. 104.00 per quintal
Grade-III	Rs. 103.00 per quintal
Grade-IV	Rs. 102.00 per quintal
Rice	
China, Taichung (Raw)	Rs. 126.00 per quintal
Begmi/IR8	Rs. 129.00 per quintal
Parmal/Hansraj/Mushkin/Ramjawain, Chohora (Raw) Ratna and RP-5-3 (Sona Raw)	Rs. 139.00 per quintal
Basmati Ordinary(Raw)	Rs. 150.00 per quintal
Superior Basmati (Grade-II) (Raw)	Rs. 172.00 per quintal
Superior Basmati (Grade-I) (Raw)	Rs. 175.00 per quintal

Note:-

Premium of five rupees per quintal is payable for parboiled rice over procurement price of raw price.

Paddy	
China/Taichung	Rs. 74.00 per quintal

IR8/Begmi	Rs. 76.00 per quintal
Parmal	Rs. 80.00 per quintal
Basmati	Rs. 85.00 per quintal
Maize	Rs. 74.00 per quintal
Barley	Rs. 65.00 per quintal

Surplus Agricultural Land

***1753. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the district-wise total acreage of Surplus Agricultural Land in possession of the Government in the State of Haryana as on 1-7-1975 and 31-12-1976, separately;

(b) the district-wise total acreage of Surplus Agricultural Land declared by the land owners after the enforcement of Land Ceiling Act during the years 1975-76 and 1976-77 to date, separately; and

(c) the district-wise total acreage of Surplus Agricultural Land distributed to the landless tenants, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes during the years 1975-76 to date, separately?

Revenue Minister (Sh. Maru Singh Malik):

(a), (b) & (c) : The requisite information in the enclosed statement.

STATEMENT

Sr	Name of District	Total Acreage of surplus land in possession of Govt. (in ord. acres)		Land declared surplus after the enforcement of Land Ceiling Act		Acres of Surplus Land (in ord. acres) distributed							
						Landless	tenants	Scheduled Castes		Scheduled Tribes		Backward Classes	
		as on 1-7-75	as on 31-12-76	during the year 1975-76	during the year 1976-77 (up to 15-1-77)	1975-76	1976-77 up to 15-1-77)	1975-76	1976-77	1975-76	1976-77	1975-76	1976-77
			(a)		(b)				(c)				
1	Sirsa				1179		689		889				229
2	Hissar						601		1643				422

3	Kuruks hetra						322		11 00				191
4	Ambala						220		42 0				152
5	Sonepat						845		13 39				745
6	Jind	21					760		21 24				430
7	Karnal						6008		14 87				783
8	Rohtak						864		69 2				172
9	Gurgao n						3902		78 7				83
1 0	Narnaul	50					14		36				

1	Bhiwan	877					409		10				98
1	i								23				
	Total	948			1179		1471		11				3305
							4s		50				

Note:- An Area 31833 acres of surplus land vested in the State under the New Ceiling Act, out of which an area of 29559 acres was distributed up to 15-1-1977 to various categories of eligible persons-----leaving a balance of 2274 acres for allotment.

Distribution of Food grains

***1765. Ch. Rizaq Ram:** Will the Minister for Excise & Taxation be pleased to state-

(a) the quantity of different Food grains and 'atta' distributed through the depots in the State during the year 1976-77 (to-date) separately; and

(b) the price at which the same was sold at the depots?

Excise & Taxation Minister: (Sh. Shyam Chand):

(a)

(i) Wheat (1-4-76 to 28-2-77) 14151 tonnes

(ii) Rice Do 5856 tonnes

(iii) Atta Do Nil

(b) Information laid on the Table of the House.

STATEMENT

Wheat	1.4-76 to date	Rs. 132.00
Rice Begmi	1.4-76 to 22.8-76	Rs. 174.00
	23.8-76 to date	Rs. 169.00
Rice Basmati Ordinary	1.4-76 to 22.8-76	Rs.210.00

	23.8-76 to date	Rs. 205.00
Rice superior Basmati	1.4-.76 to date	Rs. 257.00

चौधरी शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि यह जो उन्होंने आटे की बात बताई है, यह कहां पर बिकता है, इसका स्टॉक कहां पर है इस बात की पूरी जानकारी हाऊस को बताने की कृपा करेंगे ?

Shri Shyam Chand: There is free sale of atta now. There is no control.

Mr. Speaker: Question Hour is over.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Roads damaged due to floods in the State

588. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the minister for Revenue be pleased to state-

(a) the number of roads damaged in each district of the state due to floods and heavy rains during the period from 1-7-76 to date; and

(b) the steps taken to repair the Roads as referred to in part (a) above to make them fit for traffic and the amount spent in each case, separately?

Revenue minister (Sh. Maru SinghMalik):

(a) Statements showing the number and names of roads damaged in each district are placed on the table of the House.

(b) Necessary repairs are being carried out. The amount spent in each case up to 31-12-76 is also given in the statement

STATEMENTS

Sr.	Name of Road	Amount spent on restoration of damages up to 31-12-76
1	Jhajjar Subana Road	
2	Jhajjar Jhazgarh Chhuchakwas Dadri Boundry road	
3	Rohtak Jhajjar Road (Sec. Rohtak Jhajjar road Km. 29 to 34)	
4	Rohtak Jhajjar Road (Sec. Rohtak Rewari road Km. 33.70 to 59.11)	
5	Jhajjar Farukhnagar Road	
6	Jhajjar Dhaur Road	
7	Jhajjar Badli road	
8	Jhajjar talos road	

9	D.B.C road	
10	Chhuchwas Matenhail Jhorli Bahu Karoli road	
11	Matenhail Sahlawas Kasli road	
12	Dighal Kultana road	
13	Jhajjar Chhara road	
14	Chhara Dujana beri Kalanaur road	
15	Samaspur Majra Road	
16	Surathi approach road	
17	Dhakia approach road	
18	Jhajjar Chhuchakwas road	
19	Beri Dubaldhan road	
20	Metan Garhi road	
21	Rohad Badli road	
22	N/bye pass	
23	sampla Kultana road	
24	Nahra Bahadurgarh road	
25	Bahadurgarh Badlu road	
26	Bahadurgarh Jhajjar road	

27	Chhara Bahadurgarh road	
28	Rohtak Bhiwani road	
29	Rohtak Gohana panipat road	
30	Sonepat Kharkhoda Sampla Chhuchakwas Loharu Jhajjar road (Sec. Kharkhoda to Sampla)	
31	Sonepat Kharkhoda Sampla Chhuchakwas Loharu Jhajjar road (Sec. Sampla Chhara road)	
32	Rohtak Jind Road	
33	Gohana Lekan Majra Meham road	
34	Rohtak Kharkhoda Delhi Border road	
35	Beri Meham road	
36	Dobri to Ballab road	
37	Kahnaur to Chimni road	
38	Rohtak Sunari Kalan to Ritoli	
39	Madina to Gurawar road	
40	Madina to Ajiab road	
41	Madina to Bharan road	
42	Rohtak Jind road to Chirivia	

	Garauthi road	
43	Providing permanent remedial measures on D.H.S. road K.M. 93.5000 to 96.250 TA No. 96 H.R. 10	
44	Delhi Hissar Sulemanki road in K.M. 84, 85,96.400 to 97.400 T.A. 28 H.R. 10s	214200
45	Providing remedial measures on Delhi Hissar Sulemanki road in K.M. 88,8.650,85.000 to 87, 010, 620 to 21.700 T.A. 97 H.R. 10	152246
	Total	3093088

List of roads subjected to heavy damages due to floods of 1967 in Mohindergarh District

Sr.	Name of Road	Amount spent on restoration of damages up to 31-12-76
1	Rewari Jhajjar Rohtak road	20000
2	Rewari Pataudi road	20000
3	Rohtak Jhajjar road to Roharai Jatusana road (near Vill. Jatusana)	30000

4	Rohtak Jhajjar road to Village Khanaura Khanauri	35000
5	Rohtak Jhajjar road to Chandawas Ashiaka Ghorawas	14000
6	Delhi Jaipur road to Alimgirpur to village Khatawali	11000
7	Narnaul Madhana road	13000
8	Delhi Jaipur road to Khaliawas	2000
	Total	145000

**List of roads subjected to heavy damages due to floods of
1967 in Jind District**

Sr.	Name of Road	Amount spent on restoration of damages up to 31- 12-76
1	2	3
1	Narwana Kaithal road	367971
2	Narwana Bhupinder Sagar road	14125
3	Kalyat Baloo road	
4	Kalyat Datta Singh wala road	

5	Kurar Haripur	
6	Narwana Kaithal road to Kapil Muni Temple	
7	Jind Rohtak road	34248
8	Jind Gohana road	44405
9	Jind Safidon road	169279
10	Jind Asandh road	34452
11	Deoban Naguran road	37681
12	Tiloda Assan road Kalwa Morkhi road	2050
13	Kalwa Morkhi road	
14	Bhambawa Morkhi road	
15	Jind Safidon to village Khokheri	1803
16	Nidana Dhigana road	
17	Dhirtana Bharum Khera road	6392
18	Hatt Sarfabad road	
19	Assandh Rajond road	
	Total	713006

**List of roads subjected to heavy damages due to floods of
1967 in Sonapat District**

Sr.	Name of Road	Amount spent on restoration of damages up to 31-12-76
1	2	3
1	Gohana Safidon road	15453
2	Gohana Meham to Katura	
3	Gohana Jind road	5408
4	Gohana Sisana road	
5	Sonapat Kharkhoda road	
6	Gohana to Lakhan Majra road	1950
7	Links and approach road to Sonapat Kharkhoda road	
8	Chidana Samari road	
9	Chidana Jawra road	
10	R.G.P. road to Gillour Khurd road	
11	Kathura Kahlpa Chappra road	1000
	Total	23811

**List of roads subjected to heavy damages due to floods of
1967 in Karnal District**

Sr.	Name of Road	Amount spent on restoration of damages up to 31-12-76
1	2	3
1	Panipat Lohari Road	3768
2	Karnal Assandh road	
3	Assandh Bye-pass	
4	Providing additional waterways in Kms. 7 of Nilokheri Karsa Dhand road	
5	Links and approach Panipat Sanoli road providing additional waterways on Nanehra approach and Dadhola approach road	
	Total	3768

**List of roads subjected to heavy damages due to floods of
1967 in Kurukshetra District**

Sr.	Name of Road	Amount spent on restoration of damages up to 31-
-----	--------------	--

		12-76
1	2	3
1	Pundri Rajond road	50009
2	Karnal Kaithal road	5376
3	Kalsana Tagore to Mugal Majra Katwa road	798
4	Shahabad Ladwa road to Merchori	5342
5	Gumti approach road	1526
6	G.T. road to vill. Maobbrauli	380
7	By-pass road at Pehowa	10246
8	Kaithal Rajnod road	15600
9	Kaithal Patiala road	1406
10	Kaithal Khanauri road	
11	Guhla Bhatiana road	
12	Khanpur to Kheri Gulamali road	
13	Deodkheri approach road	
14	Jakhauli Balu road	
15	Partap gate approach road Kaithal	99
16	Dogra gate approach road at Kaithal	

17	Kaithal Bye-pas at Kaithal	
18	Kaithal Dhand road	7850
19	Guhla Kharak road	
	Total	98632

**List of roads subjected to heavy damages due to floods of
1967 in Hissar District**

Sr.	Name of Road	Amount spent on restoration of damages up to 31-12-76
1	2	3
1	Hansi Barwala road	31000
2	Hansi Sisai road	15000
3	Hansi Jind road	16201
4	Moth Lohari Ragho road	17214
5	Providing additional span of 150' on Ghaggar in Km. No. 20 Ratia Budhlada road	
6	Hissar Barwala Tohana road	
7	Tohana Bhuna road (sec. Tohana to	1892

	Chander)	
	Total	81307

**List of roads subjected to heavy damages due to floods of
1967 in Sirsa District**

Sr.	Name of Road	Amount spent on restoration of damages up to 31-12-76
1	2	3
Nil.		

**List of roads subjected to heavy damages due to floods of
1967 in Bhiwani District**

Sr.	Name of Road	Amount spent on restoration of damages up to 31-12-76
1	2	3
1	Dadri Chhuchakwas road	78722
2	Dadri Mohindergarh road	12382
3	Dadri Bond road	86408

4	Shamaspur Kaliawas to Sarupgarh road	
5	Loharwala to Jhinjjar road	
6	Dhani approach road	
7	Jaishri approach road	
8	Sajarwas Ranila road	9038
9	Achina approach road	34412
10	Bhiwani Chang road	1115
	Total	222027

List of roads subjected to heavy damages due to floods of 1967 in Ambala District

Sr.	Name of Road	Amount spent on restoration of damages up to 31-12-76
1	2	3
1	Jagadhri Ambala road	
2	Mustafabad Rly. Station to Chhapar	
3	Yamunanagar Jagadhri Chhachhrauli road	23932

4	Sadhaura Bilas pur road	19246
5	Jagadhri Ambala road	4580
6	Sadhaura Barara kaliamb road	99893
7	Harnaul Kheri Lakha Singh road	
8	Chachhraulli Kot road	
9	Jagadhri Bilaspur to Ramkheri	
10	Link road to Sabelpur Jattan	
11	Jagadhri Bari Pabni road	
12	Remodeling existing 2 span culvert in K.M. 6 to 5 span 10' each bridge on Jagadhri Ambala road	
13	Remodeling existing 2 metres span culvert to span 10 each in K.M. 7 of Jagadhri Ambala road	
14	Bilaspur Dhanaura road	
15	Harnaul jagoori road to Ismailpur	
16	Munda Majra to Gadhauali	14046
17	Akbarpur to Modli road	
18	New Haryana State Highway (Ambala Jagadhri road to G.T. road)	166000
19	Ambala Hissar road to Kalran	

	Barauli	
20	Ambala Baraula road	
21	Ambala Hissar road to Segta	4000
22	7 nos. links of State Highway Subga-pusiala/Harra Harri	
23	Shahbad Barara Kala Amb road to vill. Holi	
24	Shahabad Barara Amb road to vill. Budian	
25	Shahbad Barara Kala Amb road to Semla	
26	Durala samlkha road	
27	Ambala Jagadhri road to spara Shahpur	
28	Shahbad Barara Kala Amb road to village Sahila	
29	Ambala-A road to Kambas	
30	Jagadhri Ambala road	
31	Bassi Barwala Raipur Rani road to Nariangarh	
32	Link road to village Ganauli	

33	Ambala Kala Amb road to Ramgarh	
34	Bassi Barwal Raipur Rani road to Vill. Hangoli	
	Total	331697

**List of roads subjected to heavy damages due to floods of
1967 in Gurgaon District**

Sr.	Name of Road	Amount spent on restoration of damages up to 31-12-76
1	2	3
1	Rewari Pataudi road	
2	Delhi Mathura road to village Phulwari	
3	Delhi Mathura road to village Manpur via Seoli	
4	Badshahpur to vill. Dalelpur	
5	Ballabgarh to Vill. Fatehpur Biloch	
6	Gurgaon Alwar road	
7	Hodel Kot Nuh road	

8	Nuh Palwal road	
9	Pinhana Kot road	
10	Palwal Sohana Rewari road	
11	odel Puhana Nagina road	
12	Palwal Gohana Rewari Road	
13	Palwal Hathin Uttawar raod	
14	Bamnikhera Hassanpur road	
15	Sondh to Lohina road	
16	Palwal Ghori road	
17	Faridabad to Mangrola	
18	Badkhal pali road	
19	Ballabgarh Pali Dhauj Sohana road	
20	Ballabgarh Chhiansa Mohana road	
21	Chhiansa to Garaura road	
22	Fatehpur Biloch road to vill. Aterna	
23	Balabgarh to Fatehpur Biloch	
24	Palla to Basantpur road	
25	Rewari Pataudi road to Vill. rorai	
26	Lokhra to Mumtajpur road	

27	Pataudi Mumtajpur road	
28	Dhuneja Berka road	
29	Delhi Alwar road to Vill. Doha	
30	Punhana Dundal road	8000
31	Delhi Alwar road to Vill. Kherli Khurd	
32	Karhera to Vill. Shahdipur	
33	Mandikhera to Vill. Nangal Mubrakpur	
34	Sohalpur to Kogaon to Badopur	
35	Delhi Alwar road to Vill. Shkarpuri	
36	Herwari to Bamantheri	
37	Alipur road to vill. Habitka	
38	Allipur Habitka road to Padlashaspur road	
39	Sohalpur Kolgaon road	
40	Delhi Alwar Road to Vill. Punhana	
41	Ferozepur Jhirka Road	
	Total	8000

Construction of Roads in Karnal District

572. Ch. ram Lal Wadhwa: Will the minister for Revenue be pleased to state-

(a) the number and names of roads constructed in Karnal District out of those 132 incomplete roads as were stated in reply to Starred Question No. 1405 dated 15-1-76, during the period from 1st January, 1976 to 31st December, 1976 separately; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative the reasons thereof?

Revenue Minister (Sh. Maru SinghMalik): (a) A statements showing the number and names of roads constructed is laid on the table of the House.

(b) Does not arise.

STATEMENT

1	Umri Indri road to Bir majra
2	Thanesar Kirmach road
3	Kurukshetra Dhand road to Village Barwa.
4	Karnal Katchwa sambli road to Vill. Jalala jagir
5	Mahra road to Koer.
6	panipat Sanauli to Sanauli Kalan

7	Jamba approach road
8	Nimbri approach road
9	Puther approach road
10	Panipat Gohana road to Barhaman Majra road
11	Kakoda approach road.
12	Assandh Bye-pass.
13	Ahar to Kuran road
14	Bandh approach road
15	Risalwa approach road
16	Bhandari to Alupur road
17	Kheri Nangal approach road
18	Sewah approach road
19	G.T. road to vill. Kachrauli
20	G.T. road to Nizampur road
21	Bhuslana to Salwan road
22	Diwana to Phaladpur Khali road
23	Rear Kalan approach road
24	Kawi to Bhuslana road
25	Saunkhra to ramana Ramani

26	Alipur Viran to Badhanpur
27	Raipur Ladwa to Barsaulu with link to Lathron.
28	Ladwa Raipur to rampur
29	Umri Indri to Munak Majra
30	Raipur Ladwa to Machuri.
31	Approach road to samispur.
32	Ranwar to pipliwali.
33	Babail road to Vill. Mohali
34	Bhapoli to Goela Khurd.
35	Mormajra to vill. Geeli.
36	Mormajra road to Baljattan
37	Arianpur to Jamalpur
38	Gohana road to Vill. Chamrara

Sarpanches Removed from their Posts

573. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Agriculture be pleased to state the number of Sarpanches removed their office in the State by the Government during the years 1975-76 and 1976-77 to date on the charges of misconduct, corruption and mis-appropriations of funds?

Agriculture Minister (Col. Maha singh):-

(a) 1975-76	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sh. Tara Singh 2. Sh. Lakhi Singh 3. Sh. Maha Singh 4. Sh. Mahabir Singh 5. Sh. Shiv Ram 6. Sh. Risal Singh 7. Sh. sarup Singh 8. Sh. Ragubhir Singh 9. Sh. Sohan Lal 10. Sh. Suraj Bhan 11. Sh. Har Narian 12. Sh. Annant Ram
(b) 1976-77 to date	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sh. Sudhan Singh 2. Sh. Dharampal Singh 3. Sh. Jagvijay Singh 4. Sh. Almu Urf Ganu 5. Sh. Richhpal Singh 6. Sh. Kanshi ranm

		7. Sh. Safed Khan 8. Sh. Budh Ram 9. Sh. Kishore Singh
--	--	--

Trips allowed in Mutual Agreement to Haryana Roadways

***574. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Transport be pleased to state the number of trips with mileages allowed in mutual agreement to the Haryana Roadways by Jammu & Kashmir, Rajasthan, Punjab and Uttar Pradesh States and Union Territory of Delhi for plying Bus Services in their areas during the years 1975 and 1976, separately together with the dates of such agreements.

Transport Minister (Sh. K.L. Poswal): Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Sr	Name of reciprocating States	date of agreement	Return trips operated in reciprocating States by Haryana	Daily operation in reciprocating States by Haryana	Remarks
1	Haryana Rajasthan	11-11-	10	2170 in	Besides, 2714 KM operation in

	n	75		Rajasthan	Haryana territory was curtailed by Rajasthan to reduce the imbalance.
2	Haryana Uttar Pradesh	23- 24/9/7 5	12	In Uttar Pradesh 2372	Agreement has not been ratified by U.P. Government so far.
3	Haryana- Delhi	24-10- 75		In J & K 480	The sharing of traffic between Haryana & Delhi in the ration of 1:1.3 was agreed for the time being. The ration will however, be increased to 1:1.5 when 100% nationalization is achieved by Delhi on all joint routes between Haryana and Delhi.
4	Haryana Jammu & Kashmir	1-6-76	2	In Punjab 20000	Services stand suspended.
5	Haryana	7-9-76	264		It was agreed that bus services on

	Punjab				inter-state routes may be resumed by the two States immediately on the basis of operation of 20000 vehicles K.Ms. by each State in the territory of each other.
--	--------	--	--	--	---

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

Shri Gulab Singh Jain (Hissar): Sir , I beg to move—

That an Address be presented to the Governor in the following terms:-

“That the Members of the Haryana Vidhan Sabha Assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 23rd March, 1977.”

स्पीकर साहब, डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नर महोदय अपनी गवर्नमेंट की जो उस वक्त तक कार्यवाही हुई, पर अपने एड्रेस में रोनी डालते हैं और उनकी गवर्नमेंट के जो आगे प्रोग्राम हैं उसके बारे में हवाला देते हैं। हरियाणा स्टेट के बारे में मुझे इतना ही कहना कि पिछले सालों में जो तरक्की इस हरियाणा ने की है उसकी सराहना चारों तरफ है। हरियाणा स्टेट जिसको

हमारे सदन के सभी सदस्य जानते हैं एक एग्रीकलचरल स्टेट है जहां रूरल पापुलेशन है और लोगो का जिन्दगी का जरिया केवल एग्रीकलचर ही है। स्पीकर साहब, आप फिफथ फाइव ईयर प्लान को उठाकर देख ले या एनुएल बजट को उठा कर देख लें आपको पता लग जायेगा कि गवर्नमेंट ने सदा ही यह कोशिश की है कि हम किस तरीके के लिये दो तीन चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है। पहली यह कि जमींदार को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, उनकी जमीनें जो खराब हैं, उनको ठीक किया जाये, उनको बीज अच्छा मिले, उनको बढ़िया खाद मिले और उनको खेती के टैकनीक से वाकिफ करवाया जाये, यह सारी चीजे जमींदार के लिये बहुत जरूरी हैं। गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में चारों बातों की तरफ खास ध्यान दिया है और इससे पहले भी सरकार इन बातों की तरफ खास ध्यान देती आई है। और आगे के लिये भी इन बातों की ओर ध्यान रखने का पूरा पूरा प्रबंध किया गया है जिससे गरीब किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। स्पीकर साहब, इससे आगे एक और चीज की आवश्यकता है जोकि हमारी स्टेट की जान है, वह है बिजली। पहली बात तो यह है कि हमारी स्टेट के अन्दर कोई दरिया नहीं है। यमुना के पानी का बंटवारा हुआ और सरकार ने अपनी स्टेट के लिये पानी हासिल करने के लिये अपने हक में फैसला करवाया जोकि एक बड़ा सराहनीय कार्य है, इसके लिये मैं अपनी सरकार और खासतौर पर अपने मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। इसके इलावा स्पीकर साहब, पानी को प्राप्त करने के लिये जो कदम

उठाये जा सकते थे वह इस सरकार ने उठाये और इसके साथ साथ बिजली की कमी को पूरा करने के लिये भी हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाये वे बहुत ही सराहनीय है इससे पैदावार में बहुत बढ़ोतरी हुई है लेकिन जहां जमीन के नीचे पानी था उसको ट्यूबवैजल के जरिये किसानों को मुहैया किया गया। पानी मुहैया करने के लिये बिजली की पैदावार बड़ी जरूरी थी।

इसके इलावा स्पीकर साहब, अन एम्पलायमेंट को खत्म करने के लिये भी इस सरकार ने काफी ठोस कदम उठाये हैं। इसके साथ इंडस्ट्रीज के लिये पावर सबसे ज्यादा आवक है और जो पावर होती है वह है बिजली की वह भी बड़ी चीप रेट पर मुहैया की गई। इसके लिये सरकार ने जो कदम उठाये वे बड़े ही सराहनीय हैं। नापथा झाकड़ी परियोजना से पैदा की जाने वाली बिजली के 80 परसेंट भाग पर हरियाणा सरकार का अधिकार होगा। जो बिजली हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आयेगी और उस राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करने के बाद फालतू रहेगी, उसे पारस्परिक सहमती से निर्धारित मूल्य पर खरीदने का अधिकार पहले हरियाणा राज्य को होगा। इस परियोजना के अनुसार हरियाणा स्टेट के अंदर बिजली की कमी पूरी हो जाएगी और फिर हरियाणा स्टेट से बाहर जो हरियाणा के इंडस्ट्रीयलिस्ट्स हैं, उनको हरियाणा स्टेट के अंदर इंडस्ट्रीज लगाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके बाद स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ला एण्ड आर्डर की हमारी स्टेट में बड़ी जरूरत है आपको यह मानना पड़ेगा कि हरियाणा के अंदर ला एण्ड आर्डर की पोजीशन काफी अच्छी रही है। इंडस्ट्रीयल पीस भी बहुत ज्यादा रहा है और यहां पर इंडस्ट्रीज लगाने के बहुत चांसिज है। पिछले आंगड़े उठाकर अगर देखें तो पता चलेगा कि पिछले सालों में बिजली की कमी होते हुये भी हमारी स्टेट के अंदर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला है। यह सब चीजे साबित करती है कि हमारी हरियाणा स्टेट के अंदर कैसा पीसफुल वातावरण रहा है और डेडयूल्ड ट्राइवज और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को भी काफी ऊपर उठाया गया है और उनकी हर लिहाज से मदद की गयी है और आगे के लिये सरकार इस तरफ और ज्यादा ध्यान दे रही है।

स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं आपकी मारफत मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस में यह चीज लाना चाहता हूँ कि जैसे कांस्टीट्यूशन में पिछड़ी जातियों के लिये 50 परसेंट रिजर्वेशन है वैसे ही और बहुत छोटी छोटी जातियां हैं, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये क्योंकि कई ऐसे तबके हैं जो बैकवर्ड हैं उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान कम गया है, ऐसी मेरे ख्याल में 30-35 जमाते हैं, सरकार उनकी बेहतरी के लिये भी खास ध्यान दे और इसके साथ साथ वह प्रोवीजन होनी चाहिये कि उनको सर्विसिज में भी हिस्सा मिलना चाहिये। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े डिवेलपमेंट के काम हैं उनकी तरफ भी और छोटे छोटे

जो प्रोजेक्ट है उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो प्रोजेक्ट जल्दी व कम खर्च से हो सकते हों उनकी जरफ खास ध्यान देना चाहिये। बस स्पीकर साहब, मैं इन भाब्दों के साथर गवर्नर एड्रैस जोकि राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया, को कुमेंड करता हूं और यह प्रार्थना करता हू कि मो इन आफ थैंक्स पास करके उनको भेज दिया जाए।

चौधरी फूल चंद (मुलाना, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, श्री गुलाब सिंह जैन जी ने इस सदन के सामने जो प्रस्ताव रखा है:

“कि इस सत्र मे इकट्ठे हुये हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाशण के लिये राज्यपाल महोदय ने अत्यन्त कृतज्ञ है जो उन्होंने 23 मार्च, 1977 को सदन मे देने की कृपा की है।”

का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जब जब भी विधान सभा का बजट सै इन होता है तो सब से पहले राज्य के राज्यपाल महोदय इस सदन मे अपना अभिभाशण पढ़ते है और उसमे राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यों और किये जा रहे कार्यों की चर्चा भी होती है। 23 मार्च, 1977 को राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाशण दिया उस मे भी इस सरकार द्वारा की गई प्रगति की चर्चा की है और जो सरकार आगे के लिये करने जा रही है, उसकी चर्चा भी उन्होंने अपने अभिभाशण मे की है। स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय ने अपने इस राज्य की जनता के हित मे बहुत

से कार्य किये है। अपने अभिभाषण में हमारे राज्यपाल महोदय ने बड़े दुख के साथ हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति महोदय के निधन पर बहुत दुख प्रकट किया। हम भी सदन में एकत्रित हुए सभी लोग यह समझते हैं कि वे इस वक्त हमारे बीच में नहीं रहे जोकि हर वक्त दे आ के हित की बात करते थे और दे आ की धार्मिक एकता की बात करते थे। राज्यपाल महोदय ने ठीक समय पर अपने अभिभाषण में यह चर्चा की है। आगे राज्यपाल महोदय ने पिछले साल में हुए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत हरियाणा के उस वर्ग की भलाई की जोकि सदियों से दबा हुआ था जिक्र करते हुए तफसील में बताया है। इसके तहत सरकार ने वीकर सैक आन के लिये, गरीब लोगों के लिये जिनके पास अपने रिहायशी मकान नहीं थे या गांवों के अंदर जिनके पास मकान नहीं थे या गांवों के अन्दर जिनके पास मकान बनाने के लिये प्लॉट नहीं थे लाखों की ताद में लोगों को प्लॉट्स दिये गये। इसके अलावा हमारी सरकार ने मकान बनाने के लिये भी प्रबंध करवा रही है। सरकार उन लोगों को जिनके पास देहात के अन्दर एक सूई भर भी जगह नहीं होती थी जिसके ऊपर कि वे अपना मकान बना सकें उनको प्लॉट देकर बैंकों के जरिये पैसे दिलवा कर इस काबिल कर दिया है कि वे अपने रिहायशी आ के लिये प्रबंध कर सकें। राज्यपाल महोदय ने यह भी चर्चा की कि हरियाणा प्रांत में भूमि सुधार अच्छे ढंग से किया जाए। इस सुधार के तहत कई कानून भी बनाये गये जिनके अनुसार जो फालतू जमीन निकलेगी उसे गरीब हरिजनो को बांट दिया जायेगा और दूसरे प्रकट के तहत जो रकबा फालतू निकला

था वह डिजर्विंग कैटेगरी के लोगों में बांट दिया गया है। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है वह है देश के अन्दर और प्रांत के अंदर बढ़ती हुई कीमतों को रोकना। हमारे जो भाहरों में और देहातों में रहने वाले भाई हैं उनको पहले यह पता नहीं होता कि आज अगर कोई चीज की कीमत दो रुपये है कल को वह पांच रुपये की हो जाएगी या ज्यादा की। लेकिन इस थोड़े से अर्थ में हमारी सरकार ने कीमतों का उस स्तर पर ला दिया कि वे एक जगह टिकी रहे। खास तौर पर जो आम आदमी के रोज के काम में आने वाली चीजें थी उनके भावों को बढ़ाने से रोका गया इसके बाद स्पीकर साहब, रूरल आर्टिजंज के बारे में मैं चर्चा करना जरूरी समझा हूँ। राज्यपाल महोदय ने अपने ऐड्रेस में लिखा कि हमारा हरियाणा प्रान्त देहातों का प्रांत है। देहातों के अंदर भी सभी लोग जमींदार नहीं हैं। कुछ खेती करते हैं और कुछ खेती पर निर्भर करते हैं। कुछ लोग खेती निर्भर रह कर अपना छोटा मोटा खंघा करते हैं जैसे रूरल आर्टिजंज है। कोई हथकरघे का काम करता है, कोठ लोहार का काम करता है और बढ़ई का काम करता है। इन सबको माल की सप्लाई देने के लिये और फिर इनके तैयार भुदा माल को बेचने में सहायता करने के लिये कई प्रकार के प्रबंध इस बीस सूत्री कार्यक्रम में रखे गये। देहात के अंदर जो रूरल आर्टिजंज है वे सबसे ज्यादा जुलाहे का काम करते हैं उनके लिये हैंड लूम एंड हैंडी क्राफ्ट कार्पोरेशन का आयोजन किया। यह कार्पोरेशन जुलाहों को सूत और दूसरे साधन उपलब्ध कराने तथा

उनके तैयार भुदा माल को बेचने में सहायता करती हैं इसी तरह से जूता बनाने वाले के पास पहले चमड़ा खरीदने के लिये पैसे नहीं होते थे उनको भी इसी तरह सहायता दी जा रही है। इसके आगे राज्यपाल महोदय ने खेतीबाड़ी का जिक्र करते हुए कहा है कि पहले जहां हरियाणा अनाज के मामले में एक घाटे का प्रदे था अब वही हरियाणा अन्न बाहर भी भेजता है। पिछले वर्ष फलडूज काफी आए और उनको रोकने की हर संभव कोशिश की गई फिर भी उनके बावजूद भी आज खेती की दशा ऐसी है कि हमारे लिये अनाज काफी होगा। पैदावार को बढ़ाने के लिये आज हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है खेती के लिये बिजली और पानी की जरूरत होती है और इसके लिये हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उसने राबी ब्यास के पानी का फैसला करके उसमें से हमें 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी देने का फैसला किया लेकिन वह पानी असल प्रयोग में तब आ सकेगा जब हम वह नहर बना पाएंगे जिसके जरिये वह पानी आयेगा। उस पानी के आने से हमारे यहां नहरी पानी की कमी भी दूर होगी और साथ साथ बिजली की कमी भी दूर होगी। बिजली से हमारे किसान की मुश्किल भी हल होगी और दूसरी तरफ कारखानेदारों की मुश्किल भी हल होगी। इसके बाद कई इलाके ऐसे हैं जहां नहरी पानी बिल्कुल नहीं लगता जैसे हमारा मुलाना का इलाका है। इसके लिये एम.आई.टी.सी. के ट्यूबवैलज लगाए गये हैं। गरीब किसान जो लाखों रुपये ट्यूबवैलज को लगाने के लिये खर्च नहीं कर सकते थे उनकी सहायता हमारी इस ट्यूबवैल कार्पोरेशन ने

की है। मैं सरकार का आभारी हूँ कि हमारे अम्बाला जिला के इलाके को खासतौर से इन ट्यूबवैल्ज से फायदा हुआ है। लेकिन मैं सरकार से एक निवेदन जरूर करूंगा कि जितने ट्यूबवैल्ज लग चुके हैं उनके वाटर कोर्सिज पक्के कर दिये जाये क्योंकि वाटर कोर्सिस पक्के न होने की वजह से जिस किसान के खेत में ट्यूबवैल्ज लग जाता है वह तो उसका पूरा प्रयोग करता है और जो दूसरी जमीन वाले लोग हैं उनको पानी पूरा नहीं मिल पाता। दूसरी बात यह है कि इतने ही ट्यूबवैल्ज काफी नहीं हैं और ट्यूबवैल्ज लगाने का भी सरकार प्रबंध कर दे। खासतौर से मेरे हल्के के अंदर जहां पानी का और कोई साधान नहीं हैं इसके बाद स्पीकर सहाब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि बिजली के जो कनेक्शन इन ट्यूबवैल्ज को देने के लिये पैंडिंग पड़े हैं उनको जल्दी कनेक्शन दिये जाए। इसके बाद राज्यपाल महोदय ने हरिजनौ की भलाई के बारे में जिक्र किया। मैं हरिजन कल्याण निगम की चर्चा करते हुए यह कहूंगा कि बहुत से हरिजन जिनके पास पूंजी नहीं होती थी उनको अपना काम चलाने के लिये इस निगम ने बहुत सहायता दी है। उन्होंने इस निगम के जरिए पैसा लिया और अपने साधन उपलब्ध किये हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं लेकिन निगम अपने तौर पर एक कारखाना खोल दे, इससे हरिजन भाईयों को ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर कारखाना खोलना ही है तो उस के लिये हमारे पास इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के जरिए खोला जाना चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर सरकार ने

हरिजनो की हालत सही मायनों में सुधारनी है तो बेहतर यही होगा कि हरिजन लोग आपस में मिल कर कोई कारखाना खोले। अगर इकट्ठा नहीं मिलना है तो सीधा कर्जा लेकर, जिस प्रकार भी वह व्यक्ति काम करना चाहे करे, तभी इन गरीबों का कुछ न कुछ भला हो सकता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनमें संदेह की बात नहीं है। हरियाणा ने सारे हिन्दुस्तान के दूसरे प्रांतों के मुकाबले में बढ़ चढ़ कर तरक्की की है और सारे देश में हरियाणा प्रांत का मान है। गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में जो चर्चा किया है और जो प्रस्ताव श्री गुलाब सिंह जैन ने हाउस में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

Mr. Speaker: Motion moved—

That an address be presented to the Governor in the following terms—

“That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 23rd March, 1977.”

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में श्री गुलाब सिंह जैन ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उस पर यह चर्चा हो रहा है। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को बड़े गौर से पढ़ा है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों की काफी चर्चा की है मगर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस अभिभाषण में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं

जिन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। हम सभी जानते हैं कि हमारी संसद का यह इजलास लोग सभा के चुनाव के बाद हुआ। यह आवश्यक था कि राज्यपाल महोदय उस के बारे में कुछ चर्चा करते। जो परिणाम लोकसभा के चुनाव के हमारे सामने आये हैं, उससे हरियाणा की जनता और सरकार अलग-थलग नहीं रह सकते, इसका प्रभाव जनता पर आना लाजमी है और सरकार पर भी आना लाजमी है। इसलिये मैं महसूस करता हूँ कि इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने यह जिक्र न करके एक बड़ी कमी छोड़ी है। इसलिये मैं थोड़ा सा जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि जहाँ तक इस चुनाव का संबंध है, इसमें सरकार कर्मचारियों ने बिल्कुल निष्पक्षता से काम किया है, हालांकि कुछ अर्सा पहले सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से इस बात की मांग थी, बल्कि यह दबाव था कि जो सर्विसिज स्टेट्स में हैं यह सेंटर में हैं, वे कमिटीड होनी चाहियें कमिटीड भी विधान के लिए नहीं और न ही देना के लिए, बल्कि जो पार्टी सत्ता में हैं, इसके लिए वह वफादार हैं। इस चीज को हासिल करने के लिये हरियाणा सरकार ने जो प्रोफ़ेसिनल टैक्स खत्म किया, इलैक्शन के दौरान डीयरनेस अलाउंस की दो किस्में मंजूर की गईं, लेकिन मैं बड़े खुले भावों में यह बात कहूंगा कि इन सारी उपलब्धियों के बावजूद, कई प्रकार के दबावों के बावजूद, सरकारी कर्मचारी, सत्तारूढ़ पार्टी के वफादार ही नहीं रहे बल्कि सरकार कर्मचारियों ने चुनाव के दौरान निष्पक्षता से काम लिया और प्रजातंत्र की जो सही रवायत है, उनको मजबूत

करने में सरकारी कर्मचारियों का पूरा हाथ है, इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूँ। एक और बात इस सिलसिले में कहना मैं मुनासिब समझता हूँ और वह यह है कि मैं राज्य सरकार को भी चुनाव के संबंध में बधाई देना चाहता हूँ और ऐसा महसूस करता हूँ कि राज्य सरकार हिक्मत अमली से काम न लेती तो भायद चुनाव न होते। सभी सदस्यों को मालूम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद दे 1 में यह आवाज थी कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अस्तीफा दे। अस्तीफा दे या न दे, यह अलग सवाल है। इसी सिलसिले में दिल्ली में एक बड़ी भारी रैली हुई। आप जानते हैं, हरियाणा प्रदेश 1 दिल्ली के साथ लगता है। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जलसा हुआ, और स्पीकर साहब, हरियाणा की सारी बसें, सारी रोडवेजस, ट्रक्स, दिल्ली की डी.टी.यू. की बसें सब इस काम के लिये लगा ली कि लोगों को दिल्ली भेजा जाए रैली अटैंड करने के लिये। उस दिन, जितने कारखाने हरियाणा में थे, पानीपत में क्या, दूर दूर जगहों पर क्या, दूर दूर तक के कारखानों की बिजली के कुनैक इन बंद कर दिये और कारखानेदारों को मजबूर किया कि वे मजदूरों को दिल्ली भेजे। किस बात के लिये ? इस बात के लिये कि इंदिरा गांधी यह देखे कि दे 1 की जनता यह नहीं चाहती कि इंदिरा गांधी अस्तीफा दे, यह नहीं चाहती कि हाई कोर्ट के फैसले को मान्यता दे और अपने पद को खाली करे। जिस प्रकार से उन पर पर्दा डालने के लिये जो ढाँग रचने में सरकार ने काम किया वह पहली बिना थी जिस के ऊपर यह इलैक इन हुआ और जो परिणाम दे 1 के सामने

आया, वह इसका नतीज है। प्रधान मंत्री को झूठा विवास अगर लोगों की तरफ से न दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि वह हाई कोर्ट के फैसले के बाद त्याग पत्र दे देती और भायद यह दगा पैदा न होती। यही नहीं, उसके बाद चाहे रक्षा मंत्री का जलसा हो, चाहे मुख्य मंत्री का जलसा हो और चाहे संजय गांधी तररीफ लाएं, सारे ट्रक जो हरियाणा प्रदेश में थे या जो बसें मिल सकती थीं। उनको लगाकर लोगों को इन जलसों में ढो ढो के इकट्ठा कर लिया और लोगों की जो असली भावना भी उस पर पर्दा डालते हुये किसी को यह जानने नहीं दिया कि सरकार और लोगों में कितना फासला बन चुका है। वे सरकार से कितनी दूर जा चुके हैं। सरकार के प्रति लोगों को दिल में कितना प्यार है, लोगों का क्या प्रभाव है, इस पर पर्दा रखने के लिए सरकार ने डिप्टी कमीशनर को, एम.पी. को हिदायत दी कि सारे ट्रक इस काम के लिये इस्तेमाल किये जाये। सारे ट्रक रिक्विजिट किये गये। स्पीकर साहब, आपने भी देखा होगा, उज्जैनी में, चुनाव का एलान होने से थोड़ा अर्सा पहले श्री संजय गांधी तररीफ लाये करनाल जिले के जितने गांव और भाहर हैं वहां लोगों के घरों पर रंग करवा दिया गया, हर एक मकान को सजा दिया गया और तीन चार हतार ट्रक लगाकर 8-10 लाख आदमियों को इकट्ठा कर दिया गया और ऐसा दिखा दिया गया कि सारी जनता उनको मान्यता देती है, कबूल करती है और उनके आने की खुशी में सारे लोगों ने अपने अपने घरों पर रंग कर दिया है और घर सजा दिये गये हैं। यह जो फर्जी कारवाई हुई, फर्जी नुमायश की गई

है यह दिखाने के लिये कि लोगों के दिल सरकार के साथ है उनके नतीजे के तौर पर सरकार ने चुनाव करने का फैसला किया । वरना अगर असल हालात सामने होते तो स्पीकर साहब आप खुद ही अंजादा लागाए कि थोड़े दिन पहले जब लोक सभा की टर्म एक साल और बढ़ाई गई थी तो क्या वजह थी कि पंद्रह महीने पहले चुनाव का एलान कर दिया गया। इसका कारण यही था कि प्रधान मंत्री को, केंद्रीय सरकार को इन लोगों ने इतने धोखे में रखा कि उनको पता ही नहीं लगा कि लोगों के जजबात क्या है। उनकी भावनाओं का पता तो इस चुनाव में लगा जब चुनाव के परिणाम निकले और प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी तथा रक्षा मंत्री चौधरी बंसी लाल, जिनके बारे में यह सरकार कहती है और राज्यपाल महोदय ने भी अपने ऐड्रेस में बार बार कहा कि उन्होंने हरियाणा के बनाने में बड़ा भारी काम किया है, हार गए और हरियाणा के तीन चार कांग्रेसी उम्मीदवारों की जमानते जब्त हुईं। लोगों से सम्पर्क सरकार ने रखा नहीं बल्कि अफसरान की मारफात सारी कार्यवाही की और उनका नतीजा यह निकला कि इनको यह मालूम नहीं हुआ कि लोग कहां हैं और सरकार कहां खड़ी है। तो स्पीकर साहब, इस बात के लिये कि दे 1 में जो चुनाव हुए, चुनाव के परिणामस्वरूप जो सरकार केन्द्र में कांग्रेस की थी वह खत्म हुई और दूसरी सरकार आई और चुनाव जो हुए उनमें हरियाणा सरकार ने जो काम किया, जो कार्यवाही की, यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। अगर ये ऐसा न करते, इस तरह नुमाइ 1 न करते इस तरह का ढोंग न करते, लोगों को ढो ढो कर इकट्ठे ने

करते, ये देखते कि लोगो के असली जजबात क्या है, उनकी भावना क्या है। जो भायद परिणाम इस प्रकार का न होता। इन्होंने यह जो कार्य किया इसके लिए आज हरियाणा की जनता इनकी भुक्रगुजार है। अभी कितना जिक्र किया गया परिवार नियोजन का मैं ज्यादा उस पर चच्च हो चुकी है मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। बार बार मंत्री महोदय भी और मुख्य मंत्री जी भी इस बात पर बल देते है कि कोई केस उनके नोटिस मे आ जाये कि ज्यादाती हुई है तो वे कार्यवाही करेंगे। अगर इनको आज तक यह मालूम नही है कि हरियाणा मे परिवार नियोजन के कार्यक्रम मे ज्यादाती हुई है तो इससे ज्यादा अंधी सरकार कोई हो नही सकती। क्या इनको आज तक मालूम नही कि सरकारी अफसरान ने उनके हुक्म की ताबेदारी मे क्या क्या ज्यादाती की है ? पुलिस ने जाकर लोगो के घर घेरे है, बस के अड्डो पर पुलिस तैनात रही, स्टे ानों पर पुलिस तैनात नही, गांव गांव मे जाकर पुलिस ने घेरे दिए है और कचहरियो से लोगो को निकाल कर ले जाया गया है । जो गरीब पर आए हुए थे गवाह या मुकदमे वाले उनको पुलिस पकड़ पकड़ कर ले गई है। आज मुख्य मंत्री जी हड़ताल कर सकते है, हैल्थ मिनिस्टर साहब हड़ताल कर सकते है कि मिसलों पर क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा है कि सायल गैरहाजिर है क्योंकि उसे पुलिस अपरे ान के लिये ले गई है। फिर भी सरकार अगर कहती है कि केस नोटिस मे आ जाये तो तहकीकात करेंगे तो यह अंधी नही है तो और क्या है ? क्या इतनी ज्यादाती जो सारे हरियाणा मे हुई, अफसरान और पुलिस ने

मिलकर लोगो पर तजरूबे किये, सरकारी कर्मचारियों को थाने मे ले जाया गया और जो इंकार करते थे कि आपरे 1 नही कराना है उनको पुलिस ने लम्बा डालकर पीटा, ये सारी बाते आपके नोटिस मे नही है ? तो स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि यह सरकार जरा आंखें खोल कर देखे, खुद अंदाजा लगाए और जो बात असल हुई है उसको माने। इलैक 11न के दौरान तो मुख्य मंत्री जी भी और दूसरे मंत्रीगण भी कहते है कि ज्यादाती हुई है और हम आगे ऐसा नही करेंगे लेकिन आज सदन कहते है कि अगर कोई ज्यादाती हुई है और हम आगे ऐसा नही करेंगे। फिर स्पीकर साहब, मैं यह कहूंगा कि इसमे अगर किसी का दोश है तो वह सरकार का है। केन्द्रीय सरकार ने हिदायत दी कि आप परिवार नियोजन का प्रोग्राम बनाएं। सरकार ने लक्ष्य मुकर्रर किया। हरेक जिले के लिये टारगैट मुकर्रर किया गया। इन्होंने और सैक्रेटेरियेट के बड़े बड़े अफसरान ने सैक्रेटेरियेट मे बैठ कर बार बार डिप्टी कमी 11नर्ज की मीटिंग्ज की और उन पर दबाव दिया कि आप यह लक्ष्य पूर करने के लिये ज्यादाती की। असल मे दोशी कौन है ? असल मे दोशी वे है जिन्होंने बजाये इस बात के कि लोगो को समझाये कि इसका फायदा क्या है, नसबंदी क्यों दे 1 के लिये जरूरी है, बढ़ती हुई आबादी को राकने के लिय क्या कदम उठाने चाहिये, डंडे के जोर से परिवार नियोजन करना चाहा। इनके पास पब्लिक रिले 11ंज डिपार्टमेंट है, इतने अफसरान है। क्या इन्होंने पिछले 9-10 साल मे इस तरह का प्रोग्राम बनाया है, जिसके द्वारा लोगो को यह बताया गया हो कि परिवार नियोजन का काम हो है वह दे 1 की

भलाई के लिये लाजमी है ? इन्होंने तो सिर्फ संजय गांधी को खुद करना था। लेकिन इसमें भी मुझे दूसरे मंत्रीगण कदमबोस किया करते थे, उनका जाकर स्वागत करते थे। इस सरकारी ऐड्रेस में न तो उनका और न ही उनके पांच नुकाती प्रोग्राम का जिक्र है। बीस सूत्री प्रोग्राम का तो जिक्र है। सारी ऐमरजेंसी के दौरान पांच सूत्री प्रोग्राम का सबसे ज्यादा भाग था। कहते हैं कि यह देश को ऊंचा उठायेगा, इससे सारे देश का कल्याण होगा। लेकिन अब उसका जिक्र तक नहीं किया। सिर्फ बीस नुकाती प्रोग्राम पर ही संतोश कर लिया। क्या इतने जल्दी नापुके हो गये ? (विधन) तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ। कि अगर सरकार सही मायनों में यह यकीन करती थी कि संजय गांधी ने जो प्रोग्राम देश के सामने रखा वह सही था तो राज्यपाल के ऐड्रेस में उसका जिक्र आना लाजमी था। इन्हे इसमें लिखना चाहिए था कि देश के सामने उन्होंने यह प्रोग्राम रखा और उससे यह तरक्की हुई। खैर, मैं इस तरफ न जाते हुये यह कहूंगा कि यह कहते हैं कि लोगों ने अपनी मर्जी से आपसे इनकारवाया। नसबंदी के प्रोग्राम के बारे में हरेक माननीय सदस्य जो यहां मौजूद है जानता है और सरकार इसके लिये जिम्मेदार है लेकिन किसी ने नहीं माना कि हम ज्यादाती कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को भी गुमराह किया गया। बार बार यह बयाना दिया गया, जो टेलिविजन पर आया, सारी अखबारों में आया कि लोगों ने इस प्रोग्राम को विलिंगली अपनाया है, स्पॉनटेनियस रिसपॉस है लेकिन इस प्रोग्राम की नेचर क्या है उसका पता लगा

चुनाव मे जब ये मंत्रीगण लोगों के पास गये। जिस भी आदमी के पपास ये गये उसने कहा कि पांच केस दे दो और राय ले लो। इन्होंने हद ही कर रखी थी। अगर कोई रिबोलवर का लाईसैंस लेने गया, कोई रजिस्ट्री कराने गया, कोई जरूरी से जरूरी काम कराने गया तो पहले नसबंदी का केस मांगते थे बाद मे काम होता था। खैर, मैं एक बार फिर यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह सरकार केंद्रीय सरकार को और प्रधान मंत्री को गुमराह न करती तो यह चुनाव न होते। इसके लिये हम इसके आभारी है ओर जितनी भी बधाई इसको दे वह कम है क्योंकि वैसे वह ताना गही सरकार खत्म न होने मे न आती।

स्पीकर साहब, इस बारे मे ज्यादा चर्चा न करते हुए इस चुनाव के संबंध मे एक बात कहना चाहता हूं। आज सन् 1967 के चुनाव के पचास साल यह पहला मौका आया है जबकि केंद्र मे जनता पार्टी की सरकार आयी है और दूसरे सूबों मे और इस सूबे मे कांग्रेस पार्टी की सरकार है यानी केंद्र मे और कांग्रेस की सरकार थी और कुछ सूबों मे दूसरी पार्टियों की सरकारें थी। यहां पर एस.वी.डी. की सरकार थी जिसमे दौलता साहब भी मिनिस्टर होते थे और दूसरे हमारे साथी भी मिनिस्टर थे लेकिन वह सरकार या तो खुद के अपने नुकायस की वजह से या दूसरे कारणों से यहां चल सकी लेकिन उस हरियाणा सरकार के बारे मे आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि वह सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने तोड़ी थी।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): यह तो चौधरी देवी लाल ने तोड़ी थी। (हंसी)

चौधरी देवी लाल: वह तो बंसी लाल ने तोड़ी थी। मैं तो तुम्हारी भी तोड़ूंगा। (हंसी)

चौधरी रिजक राम: देवी लाल जी ने जब तोड़ी थी वह तो पुरानी बात हो ली। अब तो ताजा ही प्रोग्राम इनका है। अब तो निगाह इनकी इस सरकार पर है लेनिक मेरा कहने का मतलब यह है कि केन्द्र में जो सरकार बनी है वह बहुत भारी बहुमत के साथ जनता पार्टी की बनी है। दूसरी सभी पार्टियां कांग्रेस हारी है। तीन चार हलकों में तो कांग्रेस पार्टी के नुमाइन्दे की जमानत ही जब्त हुई। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा से केवल 17 परसेंट वोट मिले है। यह हालत आज कांग्रेस पार्टी की है। अब प्र न यह है कि वोटर के इस फैसले पर इस सरकार को क्या करना चाहिये ? श्री वी.वी. गिरी जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे उनका ब्यान अखबारों में आया है कि ये सभी सरकारें जो प्रान्तों में है तोड़ देनी चाहिये। जहां तक सरकार को तोड़ने का सवाल है इसमें दो राय हो सकती है क्योंकि जनता पार्टी की सरकार जो केन्द्र में है उसके लिये तोड़नी वाजिब है या नहीं ? अगर इस सरकार को गवर्नर साहब की रिपोर्ट ले कर तोड़े तो वही रास्ता होगा, वही तरीका होगा जो पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनाया हुआ था। अगर यहां के मुख्य मंत्री जी खुद ही लिख दे कि यह गवर्नमेंट तोड़ दे तो इसके टूटने में देर नहीं लगेगी। (हंसी) वैसे भोख अब्दुल्ला जी

ने तो लिख दिया तो अब ये भी खिल दे, दो मिनट लगेंगे, यर सरकार टूट जायेगी। दूसरा यह तरीका है कि आया इस सरकार को डिजोल्ड किया जाये या न किया जायें इस प्र न के बारे मे मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं। अगर केन्द्रीय सरकार गवर्नर साहब से रिपोर्ट हासिल करके तोड़े जिका यहां बहुमत है तो भी दूसरी बात है लेकिन आज जो जनता का वर्डिक्ट है, फैसला है उसको मान्यता देते हुए इस सरकार के लिये मुनासिब यही है कि यह सरकार खुद ही कुर्सी खाली कर दे। इलैव इन के मौके पर जनता ने यह दिखा दिया कि उनका जो भी कार्यक्रम, जो भी प्रोग्राम उन्होंने गवर्नर साहब को 20-25 सफे का बना कर दिया है, उसको उसने पढ़वाया है, इससे कोई तसल्ली नही, उसमे उनका वि वास नही है। तो मैं इस सरकार के लिये यही उचित समझता हूं कि ये जनता के फैसले का सम्मान करेंगे और जल्दी कल के सै इन से पहले ही अस्तीफा दे देंगे तो अच्छा ही होगा।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): आप यह फैसला भी तो कर ले कि आप मे से चीफ मिनिस्टर कौन होगा ?

चौधरी रिजक राम: चीफ मिनिस्टर की इतनी फिक्र नही है कि कौन होगा ? फिक्र तो इस बात का है कि आप कब जाये ? खैर इन बातों पर मैं ज्यादा नही बोलना चाहता लेकिन कुछ और बातें भी है, कुछ और पहलू भी है जिनके बारे मे मैं चर्चा करना चाहता हूं।

25-26 जून, 1975 की रात को एमरजेन्सी लागू हुई, आपातकालीन स्थिति की घोशणा की गई लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हरियाणा में तो बहुत पहले से ही आपात स्थिति लागू थी। यहां पर तो प्रजातंत्र का नाम एक भी नहीं था, यहां तो नाम मात्र को ही प्रजातंत्र कह सकते थे वरना यहां था नहीं। यह तो महत भासन के लिए कहते थे। अगर स्पीकर साहब हालात पर गौर फरमायें तो हरियाणा सरकार ने जो नीति अपनायी, उसमें प्रजातंत्र की जो बुनियाद थी वह सारी खत्म कर दी थी। हमारे संविधान में पंचायती, राज का जिक्र है संविधान में बल दिया है कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर राज का काम ठीक तरह से चलना चाहिए लेकिन हमने देखा कि हरियाणा में बजाए ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी लागू करने के यहां तो सदन में जो डेमोक्रेसी थी वह भी बिल्कुन खत्म हो गई थी।

स्पीकर साहब, हरियाणा में नौ म्युनिसिपल कमेटियां एक्लास हैं, 19 कमेटियां क्लास टू हैं और 44 नोटिफाइड ऐरिया कमेटियां हैं। क्या मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ सकता हूँ कि कितने दिनों से ये कमेटियां सुपरडीड की हुई हैं, कितने दिनों से म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव नहीं हुए और वहां पर एडिमिनिस्ट्रेटर लगाये हुए हैं ? क्या यही आपका प्रजातंत्र है? ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी तो पंचायतों से, म्युनिसिपल कमेटियों से और दूसरे अदारों से चलती है जिनके बारे में संविधान में बड़ा जोर दिया है। सभी भाहरों के अंदर या तो म्युनिसिपल कमेटियों को खत्म

कर दिया है या मौत्तिल करके वहां पर एडिमिनिस्ट्रेटर लगा रखे है जहां पर वे अफसरान मनमानी कर रहे है। ववहां से पब्लिक के नुमाइन्दों को खत्म कर दिया है, वे वहां से हटा दिये है या बरखास्त कर दिये गये है या मौत्तिल कर दिये है। ऐसा किए हुए भी पन्द्रह साल हो गये है लेकिन उनके चुनाव आज तक नहीं कराये। पंचायत राज के बारे मे हमारे विधान मे दिया हुआ है। आज उन पंचायतों के ऊपर बी.डी.ओ., जी.ए. तथा ए.जी. इंचार्ज बनाये हुए है, जिस पंचायत को चाहे वे सैस्पेंड कर दे। किसी वी. आई.पी. का दौरा हो तो उनसे हजार रूपये चंदा लिया जाता है औरन उनको कह देते है कि मिट्टी डलवाने पर खर्चा किया हुआ लिखा देना। बी.डी.ओ. को तो इतने अख्तियारात दिए हुए हे कि वह सरंपच को किसी भी रिपोर्ट के आधार पर मौत्तिल कर सकता है। आपने बी.डी.ओ. को नीचे के सारे अधिकार दिये हुए है। कहीं पर एडिमिनिस्ट्रेटर लगे हुए है, वे पंचायतों की प्रोपर्टी को बिल्कुल मुफ्त की समझ कर म्युनिस्पल कमेटियों को सौंप देते हैं पंचायतों को किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इन बातों की ओर तो मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायत राज या ग्रास रूटस डैमोक्रेसी जो होनी चाहिए वह आज इस सूबे से बिल्कुल खत्म है।

राज्यपाल महोदय ने सहकारी समितियों का जिक्र किया। उन्होंने इसमे कहा है कि राज्य सरकार ने बड़ा काम किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सहकारी समिति है क्या ? इन सब

का सहकारी समिति का एक महकमा भी बन चुका है । यह एक तहरीक आप भुरु से ही देख लें कैसी थी आप किसी मुल्क का इतिहास उठाकर देख ले । इस चीज के पीछे सिद्धांत रूप मे आज भी यह बात है, जो असूल है उनमे यह दिया गया है कि अगर सहकारी समितियों को चलाना है तो उस पर आफि टायल कंट्राल कम से कम होना चाहिये । स्पीकर साहब यह सिद्धांत सिर्फ हमारे दे ा मे ही नहीं दुनियां के सारे दूसरे दे ा मे भी माना गया है । मगर आप यहां पर देखे कि तीनों तरह की फ़ैडरे ान मे, स्टेट कोआप्रेटिव बैंक, मार्किटिंग फ़ैडरे ान और दूसरे कोआप्रेटिव के अदारों मे सरकारी तूती बोल रही है । सरकार के अपने नामजद गुदा प्रधान है, एडमिनिस्ट्रेटर है जोकि इन संस्थाओं का काम चला रहे है । कोई भी प्रधान अपनी मर्जी का आपने वहां जाने नहीं दिया । बे ाक मुख्य मंत्री जी दूसरे मेंबर्ज के सामने कोई भी बात कहे लेकिन असलियत यह है कि सरकार की तरफ से जो भी डायरैक् ान जाता है, जो कोई भी उनका उल्लंघन कर दे तो वह अपने सिर पर बिपता मोल लेता है । आपके यहां जो भी कोआप्रेटिव भूगर मिलज है, उनके चेयरमैन भी डिप्टी कमि ानर्ज है । जिनके भी कोआप्रेटिव भूगर मिलज है, उनके चेयरमैन भी डिप्टी कमि ानर्ज है । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस सिद्धांत के खिलाफ है कि तहरीक देखनी तो दूसरे दे ा मे जाकर देखे । मैंने कैंनेडा मे जो कोआप्रेटिव के बारे मे नीति है, वह पढ़ी है और देखी है । किसी दे ा मे या किसी भी प्रदे ा मे इतना आफि टायल कंट्रोल सहकारी समितियों पर नहीं है, जितना

चहां पर है। स्पीकर साहब, 1952-53 से पहले एस.डी.ओ. या डिप्टी कमि नर्ज चेयरमैन होते थे लेकिन उसके बाद कृषि मंत्रालय का यह आदे आ जिसमे उन्होंने यह कहा कि जो इलैक्टिड मैंबर्ज है, वह ऐसे कोआप्रेटिव इंस्टच्यू ान्ज के प्रधान बने। उसके बाद इस हिदायत के अनुसार सारे बाई लाज और एक्ट्स मे तरमीम की गई लेकिन यह हमारी ही सरकार है जिसके वह सारी तरमीम रद्द करके दोबारा आफि ायल कंट्रोल करने के लिये आफि ायल चेयरमैन बनाने की इजाजत दी। आज प्रजातंत्र की वह बुनियाद इस सरकार ने खत्म कर दी, इस बात मे कोई दो राय नही हो सकती। स्पीकर साहब, यहीं नहीं हम यह महसूस करते है और बिना किसी संकोच के मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, उसमे भावित एकमात्र मुख्य मंत्री के अपने हाथ मे है। बाकी चाहे वजीर साहेबान है या दूसरे नीचे के अफसरान है, उनके किसी के पास, डिप्टी कमि नर्ज है उनकी ताकत आज वजीर साहेबान से ज्यादा है। आजकल वजीर साहेबान इस जिक्र मे लगे रहते है कि वे डिप्टी कमि नर्ज से मुलाकात हासिल कर सकें और डिप्टी कमि नर्ज को सरकार की तरफ से यह हिदायत जारी है कि जब वजीर साहेबान जाये तो उन्हें मिले के लिये न जाये जब तक कि खासतौर पर उनको बुलाया न जाये। हमने कभी ऐसा नही देखा था कि वजीर जो अपने आपको सरकार कहते है को मिलने की भी डिप्टी कमि नर परवाह न करें। लेकिन मैं एक बात आज जानता हूं कि अगर वजीर साहब को, डिप्टी कमि नर परवाह न करे।

लेकिन मैं एक बात आज जानता हूँ कि अगर वजीर साहब को, डिप्टी कमि नर का एक चपड़ासी भी अगर उनसे हंस कर बोल ले तो वह फूले नहीं समाते। ऐसा तो प्रजातंत्री है जो इस प्रदे 1 में चल रहा है। स्पीकर साहब, आप सुनकर हैरान होंगे कि सोनीपत में कांग्रेस की मीटिंग थी, उसका जलूस निकला, हालांकि एमरजेंसी लग रही थी लेकिन वजीर साहब के खिलाफ डिप्टी कमि नर और पुलिस कप्तान की मौजूदगी में नारे लगे। वह वजीर ही नहीं उनके साथ एक और वजीर साहब भी थे। वे भाब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो वहां पर बोले गये लेकिन उन्होंने यह कहा कि लुच्चा, गुन्डा और बेईमान है। हैरानी की बात तो यह की बात तो यह है कि उन लोगों के खिलाफ कोई पत्ता तक नहीं हिला। उस वजीर की बेइज्जती करने के लिये आप देखें इस तरह के नारे लगाये गये। आप खुद ही देख सकते हैं कि उसकी क्या पोजी 1न हो सकती है ? तो आप देखिये ऐसी तो हालत हरियाणा के अंदर प्रजातंत्र की है। सरकार ने प्रजातंत्री का गला घोंटकर उसे समाप्त कर दिया है। मैं यह चाहता हूँ कि जनता ने जो रास्ता दिखाया है उसको देखते हुए मुख्य मंत्री जी इस बात की ओर ध्यान देकर प्रजातंत्र की रवायात के जो सिद्धांत हैं उनको कुछ थोड़ा बहुत यहां पर चलने देंगे।

इसके अलावा स्पीकर साहब, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ कि यहां हरियाणा प्रांत में पक्षपात का राज है। न्यायसंगत राज नहीं है। कोई भी अदारा सरकार का ऐसा नहीं है,

जिसमे जनता का विवास हो। विधान मे पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना के लिये प्रावधान है। पब्लिक सर्विस कमीशन इसलिए बनाया गया ताकि लोगों का विवास के लिये प्रावधान है। पब्लिक सर्विस कमीशन इसलिए बनाया गया ताकि लोगों का विवास रहे कि जो भी मुलाजिम या जो भी कर्मचारी छांटे जाते है वह मैरिट्स के ऊपर आते है और वह सरकार से दब कर काम न करे। वह आजादाना तौर पर काम कर सके। इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गयी है। लेकिन हरियाणा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मैबर तो दो दफा तो पानीपत मे मुख्य मंत्री जी की पोलिटिकल कांफ्रेंस मे भाषण देता रहा। यही नही टोहाने मे भी जब मुख्य मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी वहां आये तो वहां पर भी पोलिटिकल कांफ्रेंस मे वह पब्लिक सर्विस कमीशन का मैबर ऐसे ही नही भागमिल हुआ बल्कि सरकार की तारीफ भी करता रहा। हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है, उनको तो प्रोवाइस चांसलर कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी का लगाया गया था लेकिन अब रोहतक यूनिवर्सिटी का वासय चांसलर लगाया गया है। क्या आप सोच सकते है कि जनता का विवास ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन मे हो सकता है कि जिनके मैबर पोलिटिकल मीटिंग मे हिस्सा ले कि जिसके चेयरमैन को उसकी सर्विसिज का बदला देने के लिये दो साल की एक्सटेंशन दी जाये आज जनता का कोई विवास यहां के पब्लिक सर्विस कमीशन ने नही रहा और ऐसा सरकार की अपनी गलत नीति की वजह से है। सरकार ने जो छांटी की, उसकी वजह से जनता का

वि वास इन पर से उठ चुका है। सरकार जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमी इन के द्वारा पिछले 2-4 सालों में जो सिलेब इन हुए है, आप उनकी लिस्ट निकलवा कर देखले तो आपको पता चल जायेगा कि कितनी हैराफेरी हुई है।

स्पीकर साहब, जो सिलेब इन हुए है ये कहीं भी बता दें अगर ठीक हुए हो। एक दो हल्के के ही आदमी या उनके रि तेदार लिए गए है। मेरा कहना यही है कि पब्लिक सर्विस कमी इन ने सिर्फ एक या दो इलाकों के आदमी लिए है और हरियाणा के किसी इलाके के नहीं लिए है। जो भी इम्तहान लिए जाते है वे बरायेनाम लिए जाते है। पिछले दिनों कंडकटर्ज के इंटरव्यूज और सिलेब इन हुए। उसमें हमारे इलाके के ग्रेजुएटस लड़के जो पास थे उनको नहीं लिया गया और दूसरे इलाके के मैट्रिक थर्ड डिविजन लड़के ले लिए गए। हरियाणा में दो सर्विस सिलेब इन बोर्ड है हमने एम.ए. पास लड़कों को रिजैक्ट कर दिया और एक दो हल्को के मैट्रिक थर्ड डिविजन ले लिए। फिर आपकी बिजली बोर्ड की सिलेब इन कमेटी है। पिछले नौ साल से एक आदमी वहां का मुख्तियार बन बैठा है। देवी प्रान्ना तो बराएनाम है। एक आदमी मैट्रिक पास भी नहीं लेकिन एस.डी.ओ. की भर्ती वह करता है, इंजीरियर्स की भर्ती वह करता है, अगर डिविजन क्लर्क वगैरह सब की भर्ती वह करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा में यही इंसाफ है। क्या यह सरकार रिक्रूटमेंट में हरियाणा के लड़कों के साथ ऐसा ही इंसाफ करती है। मेरा कहना

तो यह है कि उन लड़कों को ले जो मैरिट पर हो, सही लड़कों को आप लीजिए। मैं स्पीकर साहब, बिना संकोच के कह सकता हूँ कि बिजली बोर्ड में और एस.एस. बोर्ड में वह लिस्ट फाईल होती है जो सरकार की तरफ से जाती है। सारे टैस्ट सिर्फ बराबरे नाम लिये जाते हैं और लोगों को धोखे में डाल कर लाखों रूपया दरखास्तों के साथ लेते हैं। मेरा कहना यह है कि यह कोई इंसाफ की बात नहीं है ये पढ़े लिखे नौजवान इस सब अन्याय को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। मुख्य मंत्री महोदय स्वयं स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हम उनसे तवकों करते हैं कि हरियाणा की जनता के साथ इंसाफ करे। डिवेलपमेंट के बारे में बड़ी चर्चा की जाती है कि हमने बैकवर्ड एरियाज को ऊपर उठाना है, हमने उन पिछड़े हुए इलाकों को दूसरों के बराबर लाना है। स्पीकर साहब, इस बारे में कोई दो रायें नहीं हैं। भिवानी का इलाका, महेन्द्रगढ़ का इलाका, मैं यह मानता हूँ कि वे इलाके पिछड़े रहे हैं और वे लोग अकाल से भी दुखी रहे हैं। उनके फायदे के लिए उनकी तरक्की के लिये सरकार कोई कदम उठाए, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। मेरे पास भी इरीगेशन का महकमा कुछ दिन रहा है। तो राम के इलाके में एक प्रोजेक्ट लगाया और वहां देखने की कोशिश की कि किस ढंग से उन पिछड़े हुए इलाकों को सहूलियत दे सकते हैं। एक साल के एक करोड़ रूपया वहां पर पानी के लिये दिया और आठ चैनल्स की मंजूरी दी थी। उसे बाद जूई कैनल, इंदिरा गांधी कैनल, जवाहर लाल नेहरू कैनल आदि का काम चालू है। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अच्छी

बात है उन इलाकों को पानी दिया जाये। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि सरकार जो नीति अपना रही है वह गलत है। इस तरह से जो दूसरा इलाका है, भायद सरकार को मलूम नहीं है, वह बरबाद होने लग रहा है। यहां एक माननीय सदस्य जो कांग्रेसी है और जो बड़ी साफगोई से बात करते हैं, हमने उसने कहा कि भिवानी और दूसरे इलाको को आप पानी पहुंचा रहे हो लेकिन दूसरे इलाको को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिलता। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि कोई पक्षपात न हो। उन्होंने कहा कि रोहतक, जींद और दूसरे इलाकों को तो हमने अपने हिसाब में से राइट आफ कर दिया है। यह आपके एक बहुत ही विवसनीय साथी है। यह उनका विचार है। आज सरकार पक्षपात की नीति अपना रही है। सब जानते हैं कि हाई इंड्रिडिंग वैराइटीज के लिये जो खाद गवर्नमेंट दे रही कोई भी स्पेसिफिस्ट इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि गेहूँ का जो बीज हम बोते हैं और फिर यूरिया खाद डालते हैं। अगर पांच छह बार फसल को पानी न मिले तो वह पक नहीं सकती लेकिन आप पड़ताल करके देख लें वैस्टर्न जमुना ट्रेक में जितनी नहर और जितनी डिस्ट्रीब्यूटरी है उनसे गेहूँ बोने के बाद डेढ़ माह तक पानी का एक हस्सा नहीं दिया और उस पानी को उन नहरों में डाल रहे हैं जहां इतना फायदा नहीं पहुंचता। आपने जुई कैनल पैरेनियल बना दी। आप यह कहते हैं कि व्यास का पानी आने के बाद सिवानी तथा दूसरी नहरों को पैरेनियल बना देंगे। आप जरूर इनको पैरेनियल कीजिए लेकिन पहले आप यह अंदाजा लगाएं कि

यह जो व्यास के पानी के लिए लाइनिंग है उस पर कब से बैटरमेंट लैवी ले रहे है। आप यह बैटरमेंट लैवी 1958 से ले रहे है और इसी बात के लिये ले रहे है कि इनको पानी मिलेगा लेकिन जब पानी बढ़ा तो दूसरी तरफ डावर्ट कर रहे है और उस पानी के डाइवर इन से उस इलाके को कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह रेत के इलाके को एक हफते में पानी नहीं दे सकते और दे वरना आप देखेंगे कि वह सारे इलाके जहां पहले से पानी मिलता है वे तबाह हो जाएंगे और दूसरे इलाके को भी फायदा नहीं होगा।

स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में अगली बात वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में कही और बताया कि 924 गांवों को पानी दे चुके है। स्पीकर साहब, हरियाणा में 6667 या 6670 गांव है जिनमें साढ़े तीन हजार देहात ऐसे है जिनमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है। पानी खारा है। यह बात मैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कह रहा हूं। आज यह सरकार दावा करती है कि उसने 924 गांवों को पानी सप्लाई किया है। स्पीकर साहब, इनमें 12 फीसदी गांव जिनको पानी दिया है वह 9 डिस्ट्रिक्ट्स के है और बाकी गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट के है। इन्होंने और कहीं पैसा खर्च नहीं किया है। आप इंसाफ करे। जनता इस बात को पसन्द नहीं करती जो आप कर रहे है। जनता तो चाहती है कि हरियाणा के लोगों को आप एकसां समझे। सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। पर अब जो बेइन्साफी लोगों के साथ की है उसका

बदला आपको जनता ने दिया है और उन इलाकों में चुनावों का परिणाम आपने देखा कि जनता ने किस तरह से अपना बदला लिया और उसी इलाके को आप कहते हैं कि मैं इसको आकाश में ले जाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के साथ यकसां व्यवहार करते, बेइन्साफी न करते तो जो पोजीशन आपकी आज हुई है, वह न होती, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी के साथ यकसां व्यवहार करो।

स्पीकर साहब, एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह भी इस लिये कि इन माननीय सदस्यों को इस बात का पता लग सके कि सरकार कितने पक्षपात से काम कर रही है। हमारे पास सरकार का दिया हुआ एक उत्तर है जोकि 8 जनवरी सन् 1975 को उसने इस सदन में दिया, उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि सन् 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75 में लगभग 17 ऐसे हस्पताल हैं जो बनाये जा रहे हैं, यह स्टेटमेंट हमारे सामने है, स्पीकर साहब आप देखें कि उन्होंने कहा है नारायणगढ़ में 50 बैडज का, फिरोजपुर झिरका में 25 बैडज का, तोशाम में 25 बैडज का, सोनीपत में 50 बैडज का और भिवानी में 500 बैडज का हस्पताल बनाया जा रहा है। स्पीकर साहब सोनीपत एक इंडस्ट्रियल ऐरिया है, दिल्ली के नजदीक है, उसकी आबादी लगभग 70/80 हजार के करीब है और वहाँ पर 80 बैडज का हस्पताल और सारे हरियाणा में भिवानी के इलाके में जोकि खुद एक इलाका है, जहाँ पर बीमारी भी बहुत कम है, वहाँ

500 बैडज का हस्पताल बनाया गया है, क्या यह सारे हरियाणा से, हिसार से भी जरूरी है लेकिन मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि भिवानी मे ऐसी कौन सी बात है कि वहां पर 500 बैडज का हस्पताल बनाया गया है, क्या यह सारे हरियाणा से, हिसार से भी जरूरी है लेकिन मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि भिवानी मे ऐसी कौन सी बात है कि वहां पर 500 बैडज का हस्पताल बनाया है। फिर कालिज आफ एजुके ान है, अलग लाईब्रेरी है, एसे नाम से यह सारा पैसा खर्च किये जाओ, आपको अख्तियार है मैं रोक नहीं सकता लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सारी जनता के साथ यकसां व्यवहार न किया तो आप ने अभी देखा जो व्यवहार आपके साथ जनता ने अब किया है वह आगे के लिये कोई भी ज्यादाती बर्दा त नहीं करेगी। स्पीकर साहब, इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी भजन लाल (आदमपुर): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और इस संबंध मे मैं अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय का बड़ा आदर व सम्मान करता हूं। राज्यपाल महोदय को चाहिये कि यह था कि यह अपना अभिभाषण पढ़ने की बजाये इस सरकार को कहते कि आप को घर जाना चाहिये और इस लिये जाना चाहिये कि इस प्रांत की जनता ने आपके खिलाफ फैसला दिया है। जिस सरकार पर जनता का

वि वास न हो, उसे सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदया आपको मालूम है कि हमारे प्रांत में असेम्बली के कोई लगभग 90 हल्के हैं, उन में मुक्ति कल से तीन चार हल्के ही ऐसे हैं जहां पर थोड़े से वोटों से इनकी जीत हुई हो भोश 86-87 हल्कों में जनता की तरफ से उनको बुर तरह से हराया गया हो उन्हें सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि जनता का उन से वि वास उठा चुका है। अध्यक्ष महोदय, गुप्ता साहब ने भुक्रवार को बोलते हुये यह कहा कि विधान ने हमें इजाजत दी है कि हम 6 साल तक या इससे ज्यादा राज करें लेकिन इस विधान को जनता ने किस तरह से ठुकराया, वह आप सब के सामने है, इस में कोई छिपी हुई बात नहीं है। आप किसी आदमी से यह कहकर बोट मांगे कि हमें 5 साल के लिये वोट देकर चुनिये, अगर हमारा इस पांच साल के अर्से में काम ठीक न हो, हमारे में कोई छिपी हुए बात नहीं है। आप किसी आदमी से यह कहकर वोट मांगे कि हमें 5 साल के लिये वोट देकर चुनिये, अगर हमारा इस पांच साल के अर्से में काम ठीक न हो, हमारे में कोई कमी आये तो आपको पूरा अधिकार है कि आपा हमें पांच साल के बाद हटा सकते हैं। जहां लोगों ने आपको 5 साल के लिये भेजा हो, और वह सत्ता में होने की वजह से 5 साल की बजाये 6 साल कर लें या 10 साल कर ले यह यह कोई लोकतंत्र का तरीका नहीं है। (हंसी)

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अगर आप छः साल नहीं मानते तो अस्तीफा दे दे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय गुप्ता जी ने अभी कहा कि अस्तीफा दे दो। मैं अस्तीफा देता हूँ गुप्ता जी भी दे दे।

श्री बनारसी दास गुप्त: मैं क्यों दूँ, आप दे दो।

चौधरी भजन लाल: हम सारे के सारे इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं, जनता का फैसला है, इसको मानना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, प्रजा के फैसले को न मानना प्रजातंत्र का गला घोटने वाली बात है लेकिन जनता इनको बख्भोगी नहीं। उन्होंने विधान को जिस तरीके से तोड़ा है कि विधान की धज्जियां उड़ा रख रख दी है (इस समय श्री के.एन.गुलाटी की तरफ से विधन).....

लाला रूलिया राम: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन है कि यह (श्री गुलाटी की तरफ इतारा करते हुए) कभी किसी के साथ लड़ता है, कभी किसी के साथ लड़ता है इसको यहां से उठाकर इधर बिठा दिया जाये (हंसी)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय यहां पर परिवार नियोजन के बारे में काफी चर्चा हुई जहां तक परिवार नियोजन का ताल्लुक है, इनको आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि लोगों के साथ कितनी ज्यादातियां की गई है। अभी गुप्ता जी ने कहा कि कैसे हमारे नोटिस में लाए जहां पर ज्यादातियां हुई हैं अध्यक्ष महोदय, एक दो ज्यादातियां हुई हो तो हम नोटिस में लाए पर

जहां पर ज्यादातियां ही ज्यादातियां हुई हो.....जिस तरह से अत्याचार हुये हो.....विघ्न....

श्री बनारसी दास गुप्ता: आपके इस्तीफा देने के बाद कोइ अत्याचार नहीं हुआ। आपके आगे हुआ।

चौधरी भजन लाल: जनता के साथ जो अन्याया हुआ वह कोई छिपा हुआ नहीं है। एस.डी.ओ., बी.डी.ओ. तहसीलदार पुलिस को साथ लेकर लोगो को पकड़ने जाते और फिर लोग वहां से सारे के सारे बागी हो जाते जैसे उन्होंने कार्ड चोरी की की हुई हो या डकैती की हुई हो। एक नौजवान लड़की अपने बापू से कहती कि तू भाज जा ये काटेंगे इन्होंने इस किस्म से मर्यादा को भंग किया है जिसकी मिसाल कही और नहीं मिल सकती। सिनेमा से लोग जब बाहर जाते थे तो एक गाड़ी बाहर खड़ी होती थीं सारे के सारे लोगो को गाड़ी में भर कर ले जाते थे चाहे उनमें कोई बुढ़ा हो और चाहे कोई नौजवान हो। स्पीकर साहब यही नहीं आप की इंतजार बस में जा रहे हैं तो आप को पकड़ कर ले गए और बेटी बेचारी अपने बाप की इंतजार बस में कर रही है। भाई और बहन बस में जा रहे हैं तो भाई को पकड़ कर नसबंदी के लिये ले गये और बहन बेचारी अकेली भाई का इंतजार बस में बैठी कर रही है और फिर स्पीकर साहब, आपने रेडियो पर सुना होगा और अखबर भी पढ़ें होंगे मैं प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बहुत इज्जत करता हूँ इनसे यह कहलवा दिया जाए कि फैमिली प्लानिंग में कहीं पर जोर जबरदस्ती नहीं हुई। तो आप

अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना गुमराह करने की बात है और कितना ज्यादाती की बात है फिर यह कहते हैं कि हमारे नोटिस में कोई ऐसा केस नहीं है। नोटिस में तो तब हो अगर एक केस हो। मैं एक केस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हिसार में एक भूतन गांव है जहां चौधरी बंसी लाल जी के ससुराल है। वहां का एक लड़का बलदेव था जोकि कंवारा था उसका आप्रे ान कर दिया गया। चौधरी देवी लाल जी एक जगह मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में उस लड़के ने यह बात बतलाई। यह लड़का जगात गांव का है, इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगा लेकतंत्र के बारे में, हिसार में राम जी लाल चेयरमैन है। उसको यह सरकार बदलना चाहती थी। प्रजातंत्र का यह तरीका है कि वोट से सरकार बदली जाती है, वोट से सरपंच बदला जाता है और वोट से ही चेयरमैन को बदला जा सकता है। इन्होंने भी वोट से सरपंच बदला जाता है और वोट से वह बदला नहीं जा सका तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन रात को एक बजे सभी मंत्रियों के घर पर पुलिस ने रेड किया। यह गलत बात नहीं है। मैं गंगा जल हाथ पर रख कर कह सकता हूँ कि यह सच्ची बात है। सब मंत्रियों को पुलिस पकड़ कर ले गई और वे सारी रात थाने में रहें सबको डरा धमका कर एक ही राम में उस चेयरमैन को हटवाने के भी दस्तखत करवा लिये और नया चेयरमैन बनाने के दस्तखत भी करवा लिये और नोटिस बगैरह सब कुछ एक ही रात में किया गया यह मामला राज्यपाल महोदय के भी नोटिस में लाया गया और इसको हम हाई कोर्ट में भी लेकर

गए। स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने लोकतंत्र की कि तरह से धज्जियां उड़ाई है। अगर यह बात गलत हो तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूँ। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी ने फाजिल्का अबोहर का जिक्र किया और बाद में यह कहा कि हमें रावी और ब्यास का पानी नहीं मिलेगा। तो फाजिल्का अबोहर के फैसले को हुए साढ़े आठ साल हो गये और इस अर्से में चौधरी बंसी लाल जी भी ताकत में रहे और गुप्ता जी भी ताकत में रहे इस अरसे में फाजिल्का और अबोहर दिला नहीं पाए फिर इतनी देर बाद इनको याद क्यों आया ? दूसरे इन्होंने कहा कि अकाली हमें रावी ब्यास का पानी नहीं देंगे क्योंकि इन्हें उन पर विवास नहीं रहा। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से विवास लेना चाहिये। मैं आपकी मार्फत एक बात सदन को बता दूँ कि आज सरदाद प्रकाश सिंह बाद सेंटर में इरीगेशन तथा एग्रीकल्चर मंत्री हैं। वह पंजाब की अकाली पार्टी के हैं। वह बहुत ऊंचे इखलाक के आदमी हैं। स्पीकर साहब, यदि हम किसी ऐसे आदमी पर ऐसा फैसला छोड़ दें तो वह अपने हक में कम लेगा और दूसरे को ज्यादा देने की कोशिश करेगा। यह फैसला बाबू जगजीवन राम जी की कलम से हुआ है और उनकी पोजीशन पहले से ज्यादा ऊंची है। इन्होंने जलसों में जाकर कहा कि अगर अकालियों की या जनता की सरकार बन गई तो वह हमें पानी नहीं देंगे (विघ्न)।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): मैंने नहीं कहा, यह अकालियों ने कहा था आप उनका मैनिफैक्टो देख ले।

चौधरी भजन लाल: हरियाणा के हिस्से का अगर एक बूंद भी पानी काटा गया तो हम इधर के सारे मੈंबर इस्तीफा दे देंगे (तालियां) (विघ्न) स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं आपके नोटिस में एक और सीरियस बात लाना चाहता हूँ। अभी जब 16.3.1977 को चुनाव हो रहे थे तो भिवानी पार्लियामेंटरी कांस्टीच्यूएंसी में एक कोहली गांव है वहां पर फायरिंग हुई, तीन आदमी जख्मी हुए और वे अभी भी हस्पताल में मरने वाले पड़े हैं। इसके अलावा एक खालिया गांव में फायरिंग हुई कोहली गांव में फाइरिंग मनी राम गोदारा ऐक्स एम.पी. ने की और उसने खुद तीन आदमियों को गोली मार कर जख्मी किया है और उनके साथ चार आदमी और भी थे जिन्होंने लाठियां वगैरह से हमला किया मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। किसी भी बाहर के व्यक्ति का जिक्र इस सदन में नहीं किया जा सकता और न ही उस पर इलजाम लगाया जा सकता है। यह हमारे लोकतंत्र की परम्परा है

चौधरी भजन लाल: यह इलजाम नहीं है, यह हकीकत है।

Mr. Speaker: Order please.

शिक्षा मंत्री (पंडित चिरंजी लाल भार्मा): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है, मैं अर्ज करूंगा कि हकीकत क्या है ? Since that is a matter, which is sub-judice because the case has been registered, I would very humbly request my hon. friend not to talk about the facts or merits and demerits of that matter.

Mr. Speaker: This is correct. मैटर सब जुडिस है तो उसके मैरिट्स को आप डिस्कस न करे ।।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि केस कोर्ट में चल रहा हो तब तो उसकी बहस यहां नहीं हो सकती लेकिन केस अभी पुलिस की तफती में है और पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है.....भाोर.

Mr. Speaker: Order please.

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन यह है Once the case is registered with the police and is under investigation, that becomes sub-judice.

चौधरी भजन लाल: यह कैसे हो सकता है, यह बिल्कुल नहीं हो सकता (विघ्न) ।

Chaudhri Partap Singh Daulta: Mr. Speaker I want your ruling on this point. Does sub-judice mean that his august House has not authority to refer to the accident itself ? Merit apart, what the hon. Member is referring to is the accident and as not finding fault with one party or the other.

श्री बनारसी दास गुप्त: Accident can be referred. लेकिन यह नाम नहीं ले सकते हैं कि फलां आदमी ने गोली चलाई। इन्होंने खासतौर से कहा है कि फलां आदमी ने गोली चलाई। यह नहीं कह सकते.....भाोर....

श्री अध्यक्ष: Order please. सब—जुडिस मैटर में केस को इम्पीकेट करना ठीक नहीं है। यह एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है। मैटर अगर सब जडिस है तो कोर्ट फैसला करेगा। उसकी मैरिट्स और डिमैरिट्स में यहां न जाया जाये तो अच्छा रहेगा.....भाोर.....

चौधरी भजन लाल: कोर्ट में जाने दे तब तो बात है। इधर से मुख्य मंत्री जी का टैलीफोन चला गया और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है.....भाोर.....

Mr. Speaker: Order please..

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात भापथ के साथ कहता हूं कि या तो भजन लाल जी इस्तीफा दे दें या मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर कोई टैलीफोन मेरी तरफ से पुलिस को गया हो। क्या गलत बातें हाउस के अंदर बैठ कर कह सकते हैं ?.....भाोर.....

चौधरी देवी लाल: वजह क्या है जब वह हस्पताल के अंदर है। उसके अपने लाइसेंस के रिवालवर से गोली चली है और उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वह इलैक इन में

काउंटिंग एजेंट है और अभी तक बाहर फिर रहा है, यह ला एंड आर्डर है.....भाोर.....

Mr. Speaker: Order please. Order please.

चौधरी देवी लाल: कल को आपके ऊपर चल जाए तो जान बचानी मुि कल हो जायेगी.....भाोर.....

श्री बनारसी दास गुप्त: केस हर एक के खिलाफ दर्ज किया हुआ है.....भाोर.....

चौधरी देवी लाल: केस को यह दबा रहे है और चौधरी बंसी लाल दबा रहे है.....भाोर.....

श्री बनारसी दास गुप्त: बिल्कुल गलत बात है.....भाोर....

..

Mr. Speaker: Order please.

श्री बनारसी दास गुप्त: बिल्कुल गलत बात है.....भाोर....

..

Mr. Speaker: Order please.

श्री बनारसी दास गुप्त: क्या ज्यादा जोर से बोलने से बात सच्ची हो जायेगी ? लंबाई आपकी ज्यादा है, आवाज मेरी ऊंची है.....भाोर.....

चौधरी देवी लाल: जनता मे आओंगे तो पता लगेगा.....
.भाोर.....

Mr. Speaker: Order please.

श्री बनारसी दास गुप्त: इतना जोर से बोल कर डराने
की कोर्िा मत करो.....भाोर.....

Mr. Speaker: Order please. We should be cool.
Please take your seat. No interruptions.

चौधरी देवी लाल: * * * * भाोर *

श्री बनारसी दास गुप्त: * * * भाोर *

चौधरी देवी लाल: * * * * भाोर *

श्री बनारसी दास गुप्त: * * * भाोर *

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी देवी लाल: * * * * भाोर *

श्री बनारसी दास गुप्त: * * * भाोर *

चौधरी देवी लाल: * * * * भाोर *

चौधरी भजन लाल: *भाोर * * भाोर *

श्री बनारसी दास गुप्त: * * * भाोर *

Mr. Speaker: Order please. Please take your seats. All these remarks are expunged. When the Hon. Minister has stated that a case has been registered and when the hon. Member while speaking alleges that this is a firing case and that a case has been registered then he should not persist on merits and demerits of the case.

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, उनका नाम तो एफ. आई.आर. मे है, मैं रैफर कर सकता हूँ.....(व्यवधान)

Mr. Speaker: Order please. No interruptions please.

(Interruption).

चौधरी भजन लाल: ठीक है जी, हम आगे इस प्वायंअ को टच नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जहां इस किस्म के अत्याचार हों और उन अत्याचारों के खिलाफ कोई कार्यवाही न हो, वहां न्याय की बात क्या हो सकती है....(व्यवधान) इसकी इन्क्वायरी थोड़ी होगी, कोर्ट मे तब केस जाएगा जब ये भेजेंगे कोर्ट में। जाने से पहले उसको ह अप करना चाहते है।

Mr. Speaker: I have give a ruling and there should be no further mention of that case.

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसी तरह पीपली का केस है.....

श्री अध्यक्ष: बगैर नाम लिये you can refer to any incident but without naming somebody.

चौधरी भजन लाल: नाम के बगैर कैसे पता चलेगा कि किस जगह की बात कह रहा हूँ.....(व्यवधान) वहाँ नौजवान आदमी मरा, औरत मरी, पुलिस ने दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया। जिन लोगों ने प्रोटैक इन में कुछ किया है उन के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया है। जिन लोगों के साथ ज्यादाती हुई, जुल्म हुए है, इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इसके खिलाफ तो जुडिीयल इन्क्वायरी बैठाएं और उस इलाके के लोगों के साथ इंसाफ करें ताकि हरियाणा का नाम ऊंचा हो और जनता में विश्वास पैदा हो। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एच.सी.एस. के ग्रेड बढ़ा दिए हैं। एक आदमी के लिये जो कुछ इन्होंने किया, अब अगर मैं नाम लूंगा तो ये कहेंगे कि नाम क्यों लिया। सब समझते होंगे। वे हैं * * * एच.सी.एस. में है और उसी केडर के जुडिीयल साइड में और लोग भी हैं, उन को यह ग्रेड नहीं मिला। इससे ज्यादा अन्याय की बात और क्या होगी...

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, ये नाम जो इन्होंने बोले हैं, इनको एकसपंज करने की मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। (व्यवधान)

Mr. Speaker: Yes.

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जो आदमी हाउस का मेंबर नहीं है, चौधरी बंसी लाल इस हाउस के मेंबर नहीं है, उनका नाम कैसे रैफर हो जाता है..... (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, सिलैव इन बोर्ड के बारे में, जैसा कि चौधरी रिजक राम जी कह कर गये हैं, लेकिन थोड़ी सी दबी जबान से कहा है.....

श्री अध्यक्ष: अगर आनरेबल मेंबर साहब किसी गवर्नमेंट मुलाजम का नाम लेकर कुछ कहेंगे तो ठीक नहीं है। क्योंकि वे अपने आपको डिफेंड नहीं कर सकते।

चौधरी भजन लाल: आगे नहीं लूंगा। मैं बता रहा था कि सिलैव इन का तरीका हमारी स्टेट में क्या है ? एक पब्लिक सर्विस कमी इन है, एक एस.एस.एस. बोर्ड है। तीसरा बिजली बोर्ड है। मैं बिजल बोर्ड के चेयरमैन साहब के बारे में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन वहां जो सिलैव इन करते हैं, वे देवी प्रसन्ना हैं और नौ साल से चले आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे, किसी भी इलाके का कैंडीडेट चाहे वह मैट्रिक पढ़ा भी हो, आपको बिजली बोर्ड में नहीं मिलेगा, बाकी देख ले सर्वे करके भिवानी तहसील के कितने हैं ? सारी स्टेट से इंफर्में इन मंगा कर देख लें, भिवानी के ही लड़के मिलेंगे। बिजली बोर्ड अकेला भिवानी तहसील का नहीं है, हर आदमी का उस पर हक है लेकिन सर्विसिज कनि को मिली है ? अगर मैं साफ साफ कहूंगा तो फिर ये कहेंगे कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। इसके बाद एस.एस.एस. बोर्ड है, पब्लिक सर्विस कमी इन है, इन में मैरिट पर फ़ैसला होना चाहिए। असल बात क्या है ? इन्टरव्यू हो गया, लिस्ट बनाकर दिल्ली से आती है। मुख्य मंत्री जी को भायद इस बात का पता नहीं होगा, दिल्ली से

लिस्ट बन कर आती है। तब फाइनल होती है। जो लिस्ट बनाकर भेजते थे, चाहे एच.सी.एस. की हो, चाहे क्लास वन हो, चाहे क्लास टू की हो सारी लिस्टे दिल्ली से बन कर आती थी अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की यह हालत हो जाये तो आप अंदाजा लगाएं कि प्रांत का क्या हाल होगा। इसी तरह एस.एस.एस. बोर्ड में होता है। सारी लिस्ट बनकर जाती है। अगर टोटल जगहें 60 आदमियों की हैं तो 60 का नाम नहीं जायेगा, 60 की बजाए 61 का जायेगा, ऐ दो आदमी वेटिंग लिस्ट में होंगे।

श्री गिरी । चंद्र जो शि: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इन बेंचिज पर मैनबर भी रह चुके हैं। जो वाक्यात इन्होंने अब बताएं हैं, क्या उस वक्त इनको बोलने का हक नहीं था या इन्हें इन वाक्यात का पता नहीं था ?

चौधरी भजन लाल: पिछले 19-20 महीने, एमरजेंसी के दौरान खूब बोला हूँ और वह खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है। मेरी बूआ का बेटा, जो सगे भाई से ज्यादा प्यारा है, उसको मीसा के अन्दर दे दिया। अगर वह 20 प्वायंट या 5 प्वायंट प्रोग्राम की तारीफ करता तो बिल्कुल न देतेकृ

श्री बनारसी दास गुप्त: कभी बोला भी ?

चौधरी भजन लाल: जहां बोलना चाहिये वहां बोला हूँ। 19 महीनों में सारे देश को अमरजेंसी के दौरान जेल की भावना में बदल कर रख दिया। इस किस्म का अन्याय और जुल्म अंग्रेज

के जमाने मे भी नही होता था। अंग्रेज के जमाने मे बोलने पर पाबंदी नही होती थी। अगर अंग्रेज के जमाने मे ऐसा होता तो दे । कभी आजाद न होता। जनता तक बात पहुंचाने के दो रास्ते होते है, एक रास्ता है जलसा जलूस करके लोगो तक बात पहुंचाई जाये। दूसरा रास्ता था रेडियो और अखबार । जब इन पर पाबंदी लग जाये, यही नही, जबान पर पाबंदी लग जाये, दो सगे भाई बस मे जाते हुए आपस मे बात नही कर सकते थे पता नही अगर कोई सुन ले तो क्या हाल होगा, जेल मे जायेंगे या और कही। इतना डर लोगो के दिलो दिमाग पर रहता था जिसकी मिसाल नही मिलेगी। इस तरीके का हाल, अगर उस वक्त अंग्रेज कर देता तो दे । आजाद कभी नही हो पता। स्पीकर साहब, दे । भक्त फांसी के तख्ते चुमते थे अगर उन की बात अखबारो के जरिये, जलसा जलूस के जरिये जनता तक न पहुंचती तो दे । का नक । आज कुछ और ही होता। दे । आजाद कैसे होता.....

श्री ओम प्रका । गर्गः हम तो सारा कुछ भजनलाल के जरिये करवाते थे.....(व्यवधान)

चौधरी भजन लालः मैं ठीक कह रहा हूं । (व्यवधान)
चमचागिरी क्यों करता है.....ये नंबर ऐसे नही देते (व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्तः इसे मालूम है नंबर कैसे दिये जाते है ?

Mr. Speaker: Order please. No interruptions like this. While one hon. Member is speaking you cannot continue like this. You can rise on a point of Order.

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि एमरजेंसी के दौरान जितने जुल्म हुए हैं, इनकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। यह कहना कि पहले क्यों नहीं बोलते, ठीक नहीं, मैं बोल सकता था लेकिन जलसा जसूल नहीं कर सकते थे, रेडियो खबरें नहीं दे सकता था, अखबार खबरें नहीं छाप सकती थी। हमने जो कदम उठाया है, वह कुर्सी के लिए नहीं उठाया, टिकट के लिये नहीं उठाया, हमने जुल्म के खिलाफ पड़ने के लिए, देश की बेहतरी के लिए कदम उठाया। उस वक्त कौन जानता था कि जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमने एक जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिये कदम उठाया आज ये बात कहते हैं कि पता नहीं किस लिए कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि भिवानी में दो नहरें बनवाई गई थी। एक थी जुई और दूसरी थी लोहारू। जब ये नहरें बनाई गई थी उस समय यह फैसला किया गया था कि उनमें तीन महीने फलड का पानी चलेगा। हमने इस बात को माना था क्योंकि फलड का पानी उस इलाके को नुकसान करता था। अगले साल कहने लगे कि ये नहरें बारहमासी होंगी। अध्यक्ष महोदय बारहमासी होने के बाद रिजल्ट क्या हुआ ? दूसरे इलाकों को जो नुकसान हुआ वह आपके सामने है। भाखड़ा का पानी उस इलाके में ले गये, जमुना का पानी उस इलाके में ले गये। उस एरिया में जहां एक एकड़ में 50 मन गेहूं

होता था वहां 25 मन भी नहीं हुआ। प्रोडक्शन काफी घटी और बड़ा भारी नुकसान उस इलाके में हुआ जहां से पानी ले गये। फिर इन्होंने डीप ट्यूबवैल्ज लगाए। आप करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और जींद में जाकर देखें। जहां पहले बीस फुट की ऊंचाई पर पानी होता था वहां 100 फुट की गहराई पर पानी चला गया। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपका भुक्ति अदा करता हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया और अपना स्थान लेता हूँ।

श्री गौरी भांकर (नरवाना): आदरणीय स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा कुछेक बातें इस सदन में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कहता हूँ। जो एच.सी.एस. का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वह ठीक नहीं है। अगर उन्हीं लड़के लड़कियाँ की किसी और बोर्ड के द्वारा सिलैक्ट करवाई जाये तो पता लगेगा कि कितने लड़के और लड़कियाँ सही तरीके से सिलैक्ट हुए हैं। यहां तो न कोई इंटरव्यू की बात थी और न ही कोई सिलैक्टशन की बात थी। जो दिल्ली से लिस्ट आती थी वही सिलैक्ट हो जाते थे। यही नहीं, जो पर्चे थे वे भी पहले आउट करवाए गए।

स्पीकर साहब, हमारे हरियाणा में बहुत सी कानें हैं गुड़गांव में और पंचकुला में। उनकी अलॉटमेंट जिस आदमी को हुई है उसको हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते थे लेकिन इनको मजबूरी से उस आदमी के नाम अलॉटमेंट

करनी पड़ी। उस आदमी को एक लाख रूपये डेली फायदा होता था जिसकी वजह से स्टेअ को चार करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। इसी तरह से एक वजरपुर की कान है। उससे दस हजार रूपये रोज की आमदनी होती है। यह भी दिल्ली की सरकार के प्रै र से अलाट की गई। अगर इसकी इंक्वायरी करवाई जाये तो चार करोड़ रूपये साल की बेईमानी निकल सकती है।

स्पीकर साहब, ये कहते है कि भाराब के ठेके बंद कर देंगे। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि इसके इलावा, स्पीकर साहब एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। कोयले के जो रैक हरियाणा के हिस्से मे आते थे उनके बारे मे सारे के सारे डी.एफ. सी. से लिखवा लिया गया कि हमे कोयले की जरूरत नही है और एक आदमी को अलाट करके दे दिये। यह सारा कोयला गुडगांव और दूसरी जगहों पर बेचा गया।

स्पीकर साहब, इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आपको पता होगा कि एक स्टैनो होता था। उसकी अगर इंक्वायरी कराई जाये तो उसके पास करोड़ रूपये मिलेंगे और अगर उसके मालिक की इंक्वायरी कराई जाये तो उसके पास 40-50 करोड़ रूपये निकलेंगे। कहते है कि हरियाणा की बड़ी तरक्की की गई है लेकिन मैं कहता हूं कि हरियाणा की नही बल्कि अपनी तरक्की की गई है। जहां एक लाख रूपया खर्च होता था वहां पचास हजार रूपया जेबों मे डाला जाता था। यही नही, पोलो मे 32 रूपये, 40 रूपये फी पोल के हिसाब से लिए जाते थे। अगर

इन सब बातों की इंकवायरी कराई जाये तो पता लगेगा कि हरियाणा में इतना पैसा खर्च नहीं हुआ जितना बेईमानी करके जेलों में चला गया । इन भावों के साथ आपका भुक्ति अदा करते हुए आपके द्वारा स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि इन बातों की अवय इंकवायरी करवाई जाये ।

चौधरी मेहर चंद (बडौपल): स्पीकर साहब, गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर चर्चा हो रही है । इसके बारे में मैं भी कुछ कहूँगा । पहले तो जो दो चार बातें मेरे मोहतरिम दोस्तों ने कही हैं उनके मुताल्लिक मैं चर्चा करूँगा । एक बात तो चौधरी रिजक राम जी ने फरमाई । उन्होंने बड़ा जोर देकर यह कहा कि सरकार को तोड़ेंगे । इसके मुताल्लिक मैं कुछ नहीं कहूँगा । इसके बारे में तो बेहतर यही होगा कि मुख्य मंत्री जी जवाब दें । चौधरी रिजक राम ने दूसरी बात यह कही कि एम.एल.ए. बनने की निस्बत डी.सी. बनना अच्छा है । इस बात की ऐसप नि बतौर एम.एल.ए. चूंकि मुझ पर है इसलिये मैं इस बारे में कुछ अर्ज करूँगा । बजिरों की बाबत जो कहा गया है उसकी वे जाने । (विधन) इसका जवाब तो वे देंगे मेहरचंद नहीं देगा । मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जनरल ऐसप नि नहीं होनी चाहिये थी ।

चौधरी भजनलाल जी ने भी सरकार को तोड़ने की बात की । इसका जवाब तो जैसा मैंने पहले कहा मुख्य मंत्री जी देंगे लेकिन अगर उनमें दम है तो वे अजमा लें क्योंकि एज एम.एल.ए. यह उनका हक है । यह एक बेसिक बात है । उन्होंने पांच छः साल

की टर्म का भी चर्चा किया है। ठीक है। जो भाई यह महसूस करते हैं कि एम.एल.एज. की टर्म पांच साल है छ.साल नहीं है उनको इस्तीफा देने में पहल करनी चाहिए। (विघ्न) 6 साल से पहले मैं। तो इस्तीफा दूंगा नहीं। (हंसी)

स्पीकर साहब, मिस्टर गौरी भांकर जी ने भी एक बात कह दी जो फेयरनेस पर बेस्ड नहीं थी। इन्होंने एच.सी.एस. की अप्वायंटमेंट को चैलेंज कर दिया। अगर इस तरह की कोई बात थी तो वे मुख्य मंत्री जी को लिखकर देते क्योंकि अगर सिलैक इन गलत थी तो गवर्नमेंट को पावर है कि यह उनसे डिफर करें और हाउस के सामने रीजन दे कि पब्लिक सर्विस कमी इन की रिकोमेंडे इन को ऐक्सैप्ट क्यों नहीं किया गया। स्पीकर साहब, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि—

जो चाहे कहत रहे कहने वाले

हम नहीं खिजां से डरने वाले।

यह मैं मानता हूं कि खिजां आई हुई है लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। (विघ्न)

गवर्नर साहब के ऐड्रेस से मुझे तो ऐसा मालूम देता है स्पीकर साहब कि उनकी सरकार ने दो एक पक्के इरादे कर रखे हैं। वे इरादे क्या हैं ? इस ऐड्रेस से साफ जाहिर है—

वतन में समाजवाद लाकर ही दम लेंगे,

अमीर गरीब का फर्क मिटा कर ही दम लेंगे।

उनकी सरकार यह महसूस करती है—

वही नब्ज है जिन्दगी का निगां

तडपती रहे जो वतन के लिए।

मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर यह हरियाणा सरकार सन् 1968 में यह महसूस न करती कि—

न हो जिस चमन में बहार कभी आयी

है उससे खुशतर किसी सैहरा की तनहाई

अगर हरियाणा सरकार में यह जजबा नहीं होता तो हरियाणा में इतनी तरक्की नहीं हो सकती थी। आप इस तरक्की को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप यह क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं कि वहाँ से नहर निकालना गलत था लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस सरकार में तरक्की जजबा था। जहाँ तरक्की हुई है उसको मानना चाहिए।

राज्यपाल महोदय के एड्रेस से यह जाहिर है कि अब तक जो विकास के काम हुए हैं वे काबले तारीफ हैं। जहाँ तारीफ के काबिल बातें नहीं होंगी उनके बारे में भी मैं कहूँगा।

एक मँबर: पहले उनको कह लो जो तारीफ के काबिल नहीं है।

चौधरी मेहर चंद: पहले तो तारीफ के काबिल बात करनी है बाद में दूसरी कहूंगा क्योंकि अभी मैं अपोजी उन में नहीं हूँ।.....विघ्न

Mr. Speaker: No interruptions please.

चौधरी मेहर चंद: स्पीकर साहब, जब मुझे बीच में टोकते हैं तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस गवर्नर ऐड्रेस में जो विकास के काम मैं उन किये गये हैं उनके बारे में तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हुई है, इसमें दो रायें नहीं हो सकती। मैं तो यह भी कहने के लिए तैयार हूँ कि सूखे के अन्दर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बढ़ी है। वह क्यों बढ़ी? वह इसलिये बढ़ी कि सरकार ने साधन पैदा किये महज प्रोडक्ट्स में बारिश की वजह से नहीं बढ़ी, कुछ बारिश से बढ़ी है, कुदरत ने भी साथ दिया लेकिन इरीगेशन फ़ैसिलिटीज में जरूर इजाफा हुआ इसमें दो रायें नहीं हो सकती। इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ में इजाफा हुआ है लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ देहातों की तरफ कम हुई है। उसकी तरफ सरकार का कोई खास ध्यान नहीं हुआ। अगर इस बारे में मैं नहीं कहता हूँ तो यह गलत बात है। मैं आपके साथ पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि देहातों के अंदर इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ नहीं हुआ।

हरियाणा सरकार ने मैडिकल फ़ैसिलिटीज प्रोवाइड की है। आपने हस्पतालों का जिक्र किया कि वहाँ तो इतने करोड़ रुपया खर्च कर दिया, वहाँ पर इतने बैडज का हस्पताल बना दिया

इस बात का जवाब तो महकमे के मिनिस्टर साहब देंगे या चीफ मिनिस्टर साहब देंगे लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि सरकार ने मैडिकल फैमिलिटिज प्रोवाइड की है। पहले जहां 1975-76 में 99 पैसे का कैपिटा एक्सपेंडीचर दवाइयों पर होता था अब 1976-77 में 148 पैसे कर दिया गया है। देहातों में जो फैमिलिटिज नहीं दी गई है उनका मैंने जरूर क्रिटिसिज्म किया लेकिन असम बात यह है और मैं यह महसूस कर रहा हूँ.....

म गीरे तामीर है बहुत कम।

जिसे भी देखो वह नुक्ताचीनी है।।

Mr. Speaker: No. direct talk please. No interruptions.

चौधरी मेहर चंद: यह बात गलत है। उनको नुक्ताचीनी का हक है लेकिन उसमें सुझाव भी दीजिये। स्पीकर साहब सप्लाइ आफ ड्रिंकिंग वाटर काफी बेहतर है लेकिन एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई। इस बात में मैं अपोजी उन वालों के साथ हूँ। जितनी यह वाटर सप्लाइ की गई है यह बहुत नहीं है, यह इसलिये भी कम है कि हरियाणा के पास फाइनेन्स की कमी है। अगर पैसे को इधर ही डायवर्ट कर दे तो फिर खेतों की इरीगे उन नहीं हो सकती। इरीगे उन नहीं होगी तो लोग भूख से मरेंगे। इस सरकार ने जो आखिरी बात की है—

“A Scheme has also been forwarded to the Central Government for world Bank assistance for water supply schemes in the State. The proposal contemplates the extension of these facilities to 3213 villages at a cost of Rs. 138.16 crores”

जहां जहां खारी पानी है उन गांवों को मीठा पानी देंगे। सभी को तो नहीं दे सकते लेकिन तीन हजार के करीब गांवो है उनके लिये खास स्कीम बनायी है।

इसके इलावा फर्टिलाइजर की बता है। गवर्नर साहब के ऐड्रेस मे एक बात आयी है। उन्होंने कहा है:-

“A sizable amount of subsidy continued to be made available on the consumption of fertilizers and the expenditure incurred by the state on this subsidy rose from 56.09 lakh in 1975-76 to Rs. 82.69 lakh in the current year.”

जो 31 मार्च को खत्म होता है। मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह अमाउंट कम है। इस तरफ ध्यान दे। मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिये सब सिडी फर्टिलाइजर मे दी है लेकिन यह बहुत कम है नेगलीजिबल है।

इसके अलावा फ्यूचर पालिसी के बारे मे भी गवर्नर साहब के ऐड्रेस मे काफी कुछ दिया हुआ है। मैं गवर्नर साहब का भुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फ्यूचर पालिसी और प्रोग्राम का जिक्र किया है। इन दोनों चीजों के बारे मे मैं यह साबित करूंगा

कि किस तरह से संतोशजनक है। उन्होंने अपने एड्रेस में कहा है कि उत्पादन बिजली का बढ़ाया जायेगा। यह बात साफ है इस बात के लिये सरकार को क्रेडिट देना चाहिये और कंड़ैम करने वाली बात हो उसको कंड़ैम करना चाहिये। सरकार ने स्कीम बतायी। इस स्कीम के तहत सरकार हिमाचल प्रदेश से बिजली ले रही है। 605 मैगावाट बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इस 605 मैगावाट में से 80 परसेंट बिजली हरियाणा को मिलेगी। क्या यह कम बिजली है, क्या यह आग के लिये बेहतर स्कीम नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि इससे बेहतर स्कीम और कोई बन नहीं सकती। मैं सरकार को इस बात के लिये दाद देता हूँ कि कम से कम सरकार ने बिजली के साधन और बढ़ाये हैं। कई बातों के बारे में रेपिटिशन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बजट पर बोलते हुए मैंने विस्तार से सारी बातें बतायी हैं।

इसके अलावा स्पीकर साहब नान पैरीनियल कैनाल्ज को पैरीनियल भी बनाया जायेगा इसमें भी कहीं किसी को आपत्ति की बात है। चौधरी रिजक राम जी और चौधरी भजन लाल जी कहा कि नान पैरीनियल कैनाल्ज को पैरीनियर कैनाल्ज बनाते वक्त दूसरी तरफ जो मौजूदा वाटर सप्लाई है उसकी तरफ भी ध्यान रखा जाये यानी उस एरिया का पानी न लिया जाये जहाँ पर आलरेडी पैरीनियल कैनाल्ज हो चुकी है।

गवर्नर साहब के एड्रेस में एक बात और आयी है जो कि उनके नोटिस में नहीं आयी है या तो साथियों ने एड्रेस को

पढ़ा नी या वैसे ही कह रहे है। गवर्नर साहब ने फरमाया है कि वाटर अलाउंस बढ़ेगा। अगर नोन पैरीनियल से पैरीनियल कैनाल्ज नहीं बनेंगी तो मैं इस सरकार को दाद कैसे दूंगा। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो वाटर अलाउंस मैं जान किया है वह भी बढ़ना चाहिये। The Governor's Address in a way is a commitment of the Haryana Government. मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि जो इन्होंने कुमिटमेंट की है, उसमे कोई भाबासी की बात नहीं, उसको हमने पहले भी आनर किया है और यह सरकार अब भी आनर करेगी।

इसके अलावा जहां टयूबवैल्ज का संबंध है वह नंबर और भी ज्यादा इंक्रीज होगा और वैसे तो मैं कहूंगा कि जितना टयूबवैल्ज का नंबर हरियाणा मे बढ़ा है इसकी कोई स्वप्न मे भी आना नहीं कर सकता था। हरियाणा मे दो लाख टयूबवैल्ज लग चुक और भी ज्यादा लगने की आशा है।

बिजली बोर्ड मे हजारों नुक्स होंगे। रिक्रूटमेंट मे गड़बड़ होगी। मैं यह मानता हूँ कि गड़बड़ होगी लेकिन बिजली बोर्ड ने जो काम किया है टयूबवैल्ज को अनर्जाइज करने के लिये उसके लिये तो सरकार को तारीफ करनी चाहिये। पहले हरियाणा का चार लाख एकड़ एरिया इरीगेट होता था आज टयूबवैल्ज से 15 लाख एकड़ एरिया इरीगेट होता है। यह बिजली बोर्ड का बड़ा भारी कंट्रीव्यू जान है। किसी इंडीविजुअल मे नुक्स है, किसी ने रिक्रूटमेंट मे गड़बड़ी की है तो दूसरी बात है लेकिन इस बात को

ईमानदारी से मानना पड़ेगा कि हरियाणा बिजली बोर्ड का हरियाणा के विकास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोडक्टिविटी के बारे में भी वही लिखा है कि ज्यादा की जायेगी। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई क्रिटीसिजम बेतक कर लो लेकिन जहां कुछ कान्ट्रीब्यूशन हो, लैकूना न हो, वहां उसकी तारीफ भी करे। अगर तो लैकूना है कहीं पर कान्ट्रीब्यूशन में तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे प्वायंट आउट करे। बतौर एम.एल.ए. हमारा यह फर्ज बनता है कि हमें यहां पर एजीटेड करना चाहिये। डर किस बात का है ? हमें जनता ने चुनकर भेजा है। उनके हम रिप्रेजेंटेटिव है। हमें साफ बात कहने में कोई डर नहीं होना चाहिये। लेकिन साफ बोलने में हमें ईमानदार आवाज होना चाहिये। जहां गवर्नमेंट की सराहना करनी हो, जहां आफिसर्स की सराहना करनी हो, वहां हमें वह विदहोल्ड नहीं करनी चाहिये। लेकिन जहां आफिसर्स की सराहना करनी हो, वहां हमें वह विदहोल्ड नहीं करनी चाहिये। लेकिन जहां पर कुछ गड़बड़ की बात हो, वहां हमें ईमानदारी से जरूर कहनी चाहिये। स्पीकर साहब, मैं तो आखिरी लफज थोड़े से और कहना चाहता हूँ फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। बाबू जी ने जो मोशन आफ थैंकस मूव किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। एक बात और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि मैं तो यहां पर यह महसूस करता हूँ और आपकी फीलिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि—

“वतन की बहार तो असली बहार है यारो

मुझे मो इसकी खिजां से भी प्यार है यारो”

अगर यह चीज आपके हरियाणा के अंदर आ जाये तो हरियाण तरक्की करता जायेगा यह मेरी आवाज है। धन्यवाद।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए उन प्वायंट्स पर ही बोलूंगा जिन पर मैं नहीं बोला हूं क्योंकि मैं बजट पर अपने काफी प्वायंट्स पर बोल चुका हूं। मैं उनको रिपीट करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरी पहली अर्ज यह है कि यह जो डाकुमेंट हमारे पास यहां पर गवर्नर एड्रेस के नाम से आयी है, यह कोई गवर्नर एड्रेस नहीं है। आनरेबल गुलाब सिंह जी ने वोट आफ थैंकस मूव करते हुये कहा कि गवर्नर एड्रेस मे दो चीजे होनी चाहिये एक तो जो कार्यवाही पिछले साल वह कर चुके और दूसरे फ्यूचर पालिसी। मैं आनरेबल गुलाब सिंह जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो कुछ पीछे हो चुका वह तो ठीक है लेकिन वह मुझे बताये कि इसमे फ्यूचर पालिसी का कौन सा चैप्टर हैं यह किताबचा तो उसी लैवल का एक किताबचा है जिस लैवल का किताबचा पब्लिक रिले ान्ज वाले छापते रहते है जो अंग्रेजी के वक्त मे छापते रहते थे इसमे, पालिसी मेंटर की कौन सी बात हैं इसमे तीन ओमी ांज जो इसमे होनी चाहिये थी, वह इसमे नहीं है। उन ओमी ान्ज का जिक्र मैं इस समय करना चाहता हूं। हमने 5-6 एड्रेस गवर्नमेंट के लिखे हुए यहां पर देखें है हम यह चाहते है कि गवर्नमेंट अपनी पालिसी वाजह करे कि हरियाणा की कैपिटल के बारे मे गवर्नमेंट की क्या

पालिसी है। उस के बारे में इस एड्रेस में एक लफ्ज नहीं। इतना इम्पोर्टेंट है कि इस स्टेट की कैपिटल कहां होगी, अपनी बनानी है, या नहीं लेकिन उसका इसमें कोई जिक्र नहीं। इस चंडीगढ़ का फ्यूचर क्या होगा, न उसका हमें जवाब ही मिला और न ही उसका इस एड्रेस में कहीं जिक्र आया। (व्यवधान) हर सूरत में 6 साल बात तो आप पूरी कर ले लेकिन मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जनता को धोखे में न रखा जाये कि गवर्नमेंट की कैपिटल के बारे में क्या पालिसी है। नंबर दो है चंडीगढ़ के बारे में सौदां मुझे यह मालूम हो रहा है मैं आपकी इजाजत से मुख्य मंत्री गुप्ता जी को यह कह दूँ क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो भुरू से हरियाणा बनाने के लिये पार्लियामेंट में लड़ते थे। मुझे एक बात का डर है। चंडीगढ़ यूनियन टैरिटरी है। यूनियन टैरिटरी को गवर्नमेंट किसी समय पंजाब की टैरिटरीज है और पंजाब की टैरिटरीज को पार्लियामेंट एक्ट के सिवाय हरियाणा को ट्रांसफर नहीं कर सकती और उसके लिये कांस्टीच्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा आधी से ज्यादा स्टेट्स से रैटीफिकेशन करानी पड़ेगी जोकि एक बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसेजन है। लेकिन आपको पता है अभी तक इस गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से या अपोजीशन की लापरवाही की वजह से इस मामले में कुछ नहीं हुआ। हम तो आपको पता है सवाल ही उठा सकते थे। हम रोज उनके नोटिस में यह बात लाते रहे। हमने एक बहुत अच्छी अपौरचुनिटी खो दी। प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड है। वह अब किस पर बाइंडिंग है जब कि इंदिरा ही यहां पर प्राइम मिनिस्टर

नहीं रही । जो नई सरकार आयी है, इसकी अपनी पोलिसी होगी ।
In the absence of Indria how will they secure Abohar and
Fazilka for us. अब यह कहते हैं कि गवर्नमेंट आपकी सैंटर में है
तो क्या आप हमें यह विवास दिलाते हो कि यह कह दोगे, यह
हमारे से पूछते हैं । हम इनसे अब यह पूछते हैं कि आपकी सरकार
पिछले 5 साल सैंटर में रही है तब आप कुछ नहीं कर पाये अब
हम से क्यों पूछते हो ?

दूसरी बात मैं पालिसी आफ रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट
सर्विस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । स्पीकर साहब, सब आदमी
जो भी सरकारी मुलाजमत में है, वे मेरे लिये काबिले इज्जत हैं ।
स्पीकर महोदय, जब हरियाणा बना तो हरियाणा के निवासियों का
सबसे पहला ग्राउज यह था कि हरियाणा के आदमी सरकारी
मुलाजमत में नहीं हैं । जो सन आफ दी सायल हैं, जो हरियाणा से
इमो नली इंवाल्ड हैं, वह हरियाणा की मुलाजमत में नहीं हैं ।
जो टा कैडर है आई.ए.एस. का वह तो कम्पीटीटिव ऐग्जामिनेशन
से आता है इस रिक्रूटमेंट की पालिसी के बारे में श्री गुलाब सिंह
जैन जी ने बहुत अच्छे लफ्जों में जिक्र किया था 50 प्रतिशत तक
रिजर्वेशन तो हम कर सकते हैं । लेकिन इस 50 प्रतिशत में वह
मार्जिनल फारमर्ज होने चाहिये जिनको हम बैकवर्ड क्लासिफिकेशन में
गिना जाये । गवर्नमेंट चाहे तो इस बारे में अपनी पालिसी डिक्लेयर
कर सकती है । कैपिटल और रिक्रूटमेंट पालिसी के बाद जो इस
एड्रेस में ओमिशन है, वह भी एक इम्पोर्टन्ट ओमिशन है । This
address does not take account of a happening namely the

elections to Parliament and its consequence on the present administration. मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूँ, हीट जनरेट करने की कोई बात नहीं है कि पार्लियामेंट का इलैक्शन जो हुआ, यह कोई पार्लियामेंट का ही इलैक्शन नहीं है पार्लियामेंट मियाद 6 साल तक थी। अगर नौर्मल हालात में इलैक्शन होते तो भी 6 साल के बाद होने थे। पार्लियामेंट के इलैक्शन तकरीबन 11 महीने पहले हो गये। मैं इस बारे में कभी अपोलोजेटिक नहीं हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का बड़ा एडमायरेर हूँ। अगर उस इन्दिरा को, जो एक डेमोक्रेट बाप की एक डेमोक्रेट बेटी थी, को यह कोकस मिस गार्ड नहीं करता तो आज हिन्दुस्तान की हालत ही डिफरेंट होती। मुझे दुख हुआ कि यह तो इलैक्शन हुए यह इलैक्शन नहीं थे यह तो कांस्टीच्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी, उसपर रैफरेंडम था। इस इलैक्शन का इस एड्रेस में कोई नोट नहीं लिया गया अगर हमारे गवर्नर साहब उस का नोट लेते तो वह यह कह सकते थे— I will not read your Address. Why? It is not the ideology of the Congress which stands rejected because so far as ideologies are concerned all the three parties have the same manifesto. What the people have rejected is not Indira's leadership but the State administration of which they were tired of. They have rejected and punished those who were there. इसलिये इस हालत में यह कहना कि यह पार्लियामेंट का इलैक्शन था, इसका स्टेटस से कोई संबंध नहीं है, ठीक नहीं है। इसका स्टेटस से संबंध था। इन्दिरा गांधी कभी नहीं हारती अगर उसको ठीक इन्फर्मेशन में ये

लोग पहुंचने देते। ये लोग तो उसके कानों तक सही खबरे पहुंचने ही नहीं देते थे। ये लोग उसको बेचारी को सही चीज अपनी आंखों से देखने भी नहीं देते थे। ये लोग उसको बेचारी को सही चीज अपनी आंखों से देखने भी नहीं देते थे। अगर ये लोग उसे मिस गाइड न करते तो वे न हारती। वे लो गजिन लोगो ने उनके कानों तक सही खबर नहीं पहुंचने दी, उन लोगो के बारे में जनता ने यह कहा कि we are tired of you. इस रैफरेंडम में इन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। इसलिये स्पीकर साहब, इस इ.यू. पर हीट जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता कि आप चौधरी रिजक राम की बात सुनो, मैं यह नहीं कहता कि आप चौधरी भजनलाल की बात सुनो, मैं यह नहीं कहता कि आप चौधरी देवी लाल की बात सुनो, मैं यह कहता हूँ कि आप दिनेश सिंह की ही बात सुन लो जिसने कहा कि जिन स्टेट्स में कांग्रेस की हार हुई है, वहां की सरकारों को चला जाना चाहिये। जिन स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक रिजेक्ट कर चुकी है, उन सरकारों को त्यागपत्र दे देना चाहिये।

आप लोग गिरी की बात न सुनें लेकिन सबका फायदा इसी में है कि पब्लिक ने इस सरकार को रिजेक्ट किया है उस पर ध्यान दिया जाये। गवर्नर एड्रेस में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि इस चीज की जिम्मेदारी किस पर है। यह नहीं बताया गया कि स्टेट की क्या जिम्मेदारी है। स्पीकर साहब, मैं बिना संकोच के साथ कह सकता हूँ और मुझे फक्र है कि पिछले पांच साल में

हमारी स्टेट की बहुत अचीवमेंटस है। हमारे रूरल सैक्टर मे जो इरीगे इन है उस पर काफी पैसा खर्च किया गया और सैक्टर मे जो कुछ भी तरक्की हुई है उसका सारा क्रेडिट चौधरी भजन लाल को जाता है। इस महकमे की फाउंटे इन बहुत मजबूत है इस तित को कहने मे मुझे जरा भी संकोच नही है। इरीगे इन के लिये बिजली देने के बारे मे गुप्ता जी की पालिसी रही है कि सीमेंट मिले या न मिले कोई और चीज मिले या न हमले लेकिन बिजली जरूर मिलेगी। लेकिन अच्छे एडमिनिस्ट्रै इन के साथ जनता अपने पालिटीक्ल और सो ाल राइटस जो हमने दो सो साल तक अंग्रेजों के साथ लड़ने के बाद हासिल किये थे जनता उनकी प्रोटेक् इन चाहती है। यह गवर्नमेंट उनकी सिविल राइटस, सिविल लिबरीटी के देने मे नाकामयाब रही है। गवर्नमेंट को इसका नोट लेना चाहिये।

पब्लिक हैल्थ के बारे मे मैं ज्यादा नही कहना चाहता। फ़ैमिली प्लानिंग के बारे मे मुझे यह सुनकर दुख होता है कि गवर्नमेंट यह कहे कि हमारे नोटिस मे नही आया। इस तरह की बात कहना लैफ्ट हैंडिड कम्पलीमेंट है सी.आई.डी. हरियाणा के ऊपर। हरियाणा की सी.आई.डी. को यहां तक मालूम नही है कि चौधरी भजन लाल के घर मे क्या सब्जी बनी है और उसको यह भी मालूम है कि चिरंजी लाल घर मे है या घर के बाहर है। ये सारी चीजे न सिर्फ हरियाणा की गवर्नमेंट को मालूम है बल्कि दिल्ली भी ये सारी चीजे जाती है जिसका इन सब चीजो का

ताल्लुक ही नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यहां की सी.आई.डी. इतनी फ़ैल्योर थी कि वह मिनिस्ट्री को न बता सकी कि देहात में क्या हो रहा है। स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बात कहकर कि हमारे नोटिस में यह बात नहीं थी इन पढ़े लिखे नौजवानों का मजाक न करे। मैं कहता हूँ कि इनके नोटिस में हर चीज आती है और न सिर्फ़ इनके नोटिस में बल्कि दिल्ली तक ये सब चीजे जाती है। जो कुछ फ़ैमिली प्लानिंग में हुआ उसके बारे में मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन गलतियों को सुधारने का एक ही तरीका है कि जो केसिज लोगों के खिलाफ़ है उनको विदड्रा करे। जब जार्ज फर्नाडिज के खिलाफ़ केस वापिस हो सकता है तो ये केस भी वापिस हो सकता है। मुझे खुशी है कि मद्रास के एक जज ने कहा है कि अगर जार्ज फर्नाडिज के खिलाफ़ झूठा होने के नाते उसको विदड्रा किया जा रहा है तो इंदिरा गांधी और ओम मेहता के खिलाफ़ केस रजिस्टर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, जार्ज फर्नाडिज के केस का हरियाणा के गवर्नर के एड्रेस के साथ कोई वास्ता नहीं है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मैं केस के विदड्रा के बारे में बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, मैंने इस हद तक जाने की इजाजत दी है इसके बारे में रूल यह कहता है कि जो एड्रेस के अन्दर है वही डिस्कस हो सकता है। अमेंडमेंट किसी आनरेबल मेंबर ने दी नहीं है। अगर कोई अमेंडमेंट भी देता तो वह अमेंडमेंट भी डिस्कस हो सकती थी लेकिन इससे बाहर का मैटर डिस्कस करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, मैं उसे छोड़ता हूँ जो प्राईसिज का पैराग्राफ पांच है उसके बारे में मैं कह देता हूँ लेकिन मेरी यह सजैव है कि जार्ज फर्नाडिज का केस विदड्रा हो सकता है तो यह भी केसिज वापिस हो सकते हैं।

स्पीकर साहब, प्राईसिज के बारे में पैराग्राफ पांच में लिखा है कि प्राईसिज कंट्राल में रही है। स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि प्राईस इंडेक्स फिर ऊपर जा रहा है। स्पीकर साहब, प्राईस का तो यह हाल है कि जब जमींदार के घर में चीज रहती है जब तक तो मंदा रहता है और उसके घर से निकलते ही चीजों के भाव चढ़ने भुरू हो जाते हैं। गुड़ जब तक जमींदार के घर में रहा उस वक्त तो मंदा रहा और उसके घर से निकलते ही गुड़ का भाव ऊपर उठ गया। प्राईसिज की पालिसी गवर्नमेंट की बिल्कुल फेलुयर रही है। जमींदार के घर में जब तक फसल रहती है तो कीमते कम रहती हैं और उसके घर से निकलते ही कीमते चढ़ जाती हैं। इस मामले में मैं गवर्नमेंट को कम्प्लीमेंट पे नहीं करता। इसके बाद लैंड सीलिंग की बात आई है। स्पीकर साहब,

काफी सीलिंग हो गई है अब तो बंद करो। पैराग्राफ छह में पटवारी से जमीन के डिटेल्स लेने जाता है तो उसको सौ रूपया खर्च करना पड़ता है। कोई वकील अदालत में पे 1 नहीं हो सकता। यह हर तीसरे दिन उससे डिटेल्स मांगना उस जमींदार का कचूमर निकालना है। यह सीलिंग वाली बात अब खत्म होनी चाहिये। मैं सी.एम. साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा में एक लैंड रिकार्ड कमेटी बनी थी। उस लैंड रिकार्ड कमेटी ने रिपोर्ट की थी। उस कमेटी की ड्राफ्टिंग में मैं भी एसोसिएटिड था। उसमें कहा गया था—

Time has come when absentee landlordship should go. One who tills the land should own it and one who owns it should till it.

और लैंड सीलिंग की डेफ़ीनेशन रिटेदार यानी कजन तक डिफ़ाइन करने के बाद बाकी गिरदावरी का कालम जो टैनेन्सी आफ लैंड लाज के तमाम डिस्पूयट होते हैं, खत्म करना चाहिये मैं और राव निहाल सिंह जी वगैरह हम लोग केरल गये थे, वहां पर यह गिरदावरी का कालम खत्म कर दिया है, करनाटक में भी यह कालम खत्म कर दिया है। यहां पर यह कालम रखा हुआ है इससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोअर लेवल के पर्सोनल को फायदा पहुंचाने के लिये रखा है। मेरी मुख्य मंत्री महोदय से दरखास्त है कि वे इस गिरदावरी के कालम को ऐबोलिश करें तो अच्छा होगा।

स्पीकर साहब, अब मैं फ्लड के बारे में कहना चाहता हूँ। फ्लड डिपार्टमेंट बहुत बड़ा करण्डान का सोर्स बन गया है। ये लोग फ्लड रोकने के लिए कुछ इस तरह का इन्तजाम करते हैं कि अगले साल जो कुछ बनाया होता है वह टूट जाएं। हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। सारा एडमिनिस्ट्रेटन पैरेलाइज हो जाता है। यह डिपार्टमेंट मुंह मांगा बजट मन्जूर करवा लेता है। फ्लड रोजगार का पैसा कमाने का एक सिलसिला बना हुआ है इस सिलसिले को बन्द किया जाए और फ्लड का कोई ऐसा परमानेन्ट इन्तजाम किया जाये जिससे लोगों को फायदा हो।

कालम 13 में इरीगेटन के बारे में कहा गया है। इसमें बताया गया है कि रावी-व्यास का कितना पानी हरियाणा को मिलेगा और कितना पंजाब को मिलेगा। मैं निहयत जिम्मेदारी के साथ इस तरफ बैठे हुये भाइयों की तरफ से कहता हूँ कि अकालियों के साथ किसी किस्म का समझौता हरियाणा के पानी का सरन्डर करने का नहीं किया और किसी किस्म की अन्डरटेकिंग जनात पार्टी या सी.एफ.डी. ने अकालियों को नहीं दी कि इलैक्शन के बाद यह मामला फिर रिवाइव होगा। स्पीकर साहब, रिवाइव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीकर साहब कैबिनेट लैवल पर यह फैसला हुआ है। यह कोई चन्डीगढ़ या फाजिल्का के बारे में फैसला नहीं है। यह बाबू जगजीवन राम का फैसला है। इसको रिवाइव करने की किसी की मजाल नहीं है ओर हम इतने कमजोर नहीं हैं कि जहां से दस-दस मैम्बर भेजे गये

हो वहां के बारे में एक बार किया हुआ फैसला रिवाइव हो।
स्पीकर साहब, हरियाणा और पंजाब का पानी का केस ऐसे प्रेजेन्ट
किया जा रहा है जैसे एक तरफ देवी लाल अपने कंधे पर कुल्हाड़ा
लेकर खड़ा हो और दूसरी तरफ प्रकाश सिंह बादल खड़ा हो
स्पीकर साहब, इस किस्म की कोई बात नहीं है। यह अलग बात है
कि अकाली लीडर तलवन्डी ने कोई बयान दे दिया हो और वह
बयान 21 तारीख के पेपर में छप गया हो और आप उसको
एक्सप्लायट कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है।
That is no ground to make such a serious allegation as the
Leader of the House, the Chief Minister, made a serious
allegation against the opposition. उनको हक था अपने वोट लेने
के लिये कुछ भी कहते फिरें और आपको क था कि आप जनता
पार्टी के खिलाफ एक्सप्लायट करें, पर हाउस में इतनी सीरियस
स्टेटमेंट न देते। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस
हाउस में कितने गैर जिम्मेदाराना एलीगेशन लगाये गये हैं।
स्पीकर साहब, इससे आगे इरीगेशन के बाद आपका ज्यादा समय
न लेते हुये ला एण्ड आर्डर और एमरजेन्सी के बारे में थोड़ा सा
कहना चाहता हूँ। ला एण्ड आर्डर के बारे में मेरी अर्ज यह है कि
ला एण्ड आर्डर में लेजिसलेचर भी आती है, चूंकि मेरी पर्सनल राय
है, टिकट देने का तो मेरा काम नहीं है मैं समझता हूँ कि मेरा
Chief Minister is a gentle Chief Minister मेरी कोई नयी
ओपीनीयन नहीं है, मैं उन से रिवैस्ट करूंगा कि इस लेजिसलेचर
का स्टेटस बढ़ायें। मेरे एक आनरेबल मेम्बर साथी ने जिनको

यहां बोलने की इजाजत नहीं है, उन्होंने अपना ट्रिब्यून में बयान दिया है जोकि मुझे बहुत पसन्द आया जैसा कि मिसाल के तौर पर हमने ऐंजीटे इन करनी है, गुप्ता जी हम नहीं छिपाते। अगर हाउस से इन में होता था तो जो इम्पोर्टेन्ट ब्यान होता था वह पहले हाउस में आता था। स्पीकर साहब, हमारे हाउस की इतनी इम्पोर्टन्स होती थी। अगर पार्लियामेंट से इन में हो और प्राइमिनिस्टर अगर कोई इम्पोर्टेन्ट ब्यान बाहर देता है तो गले पड़ जाते थे कि हाउस को पहले कन्फीडेन्स में क्यों नहीं लिया और यही अपोजी इन की जिम्मेवारी है। अगर अपोजी इन ने भी कोई खास पालिसी डिकलेयर करनी हो तो भी यह है कि जब से इन हो तो वह हाउस में करे। स्पीकर साहब, हम डिफेक् इन के हम में नहीं है लेकिन जहां जनता ने जिस सरकार को 70 प्रतिशत वोटों से रिजेक्ट कर दिया हो और साढ़े 17 परसेन्ट वोट सिर्फ उनको दिये हो वह यह कहें कि यह रेफरेन्डम नहीं है, हमें जनता के पास जाने का हक है और जनता हमको कहे हम उस रास्ते पर जाने को तैयार है यह मेरा एलाना है। हम देखेंगे कि जनता के फैसले की तोहीन कैसे की जायेगी और गर्वनर ने इस ऐड्रेस को पढ़ने की जुरत कैसे की है, यह मेरा यहां से एलान है। आपका एलान है कि अगले इलैक् इन तक हम ठाठ, से राज करेंगे। मेरी दिली ख्वाइश है कि हमारा चीफ मिनिस्टर की तो ठाठ से हकूमत करता लेकिन यहां तो हकूमत ऐसे आदमी की रही है जिसका इस हाउस से कोई सरोकार ही नहीं है। ठाठ से कभी भी नहीं हुई और अब क्या होनी है खैर जनात ने आपको ठाठ से

हकमत करने का मौका दिया है। आपका हक है कि आप यह बात कहें। हमारा हक है जो हम हाउस में कह रहे हैं कि अगर जनता की ओपनीनियन की रिसपैक्ट न की गई तो जो जनता चाहेगी हम अपोजी उन वाले उसके साथ होंगे। इससे आगे स्पीकर साहब, मैं एक बात और आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जैसे मेरे एक साथी चौधरी हरजक राम ने कहा था और जिसको मेरे एक और मैम्बर गलती से कुछ और ही समझ बैठे कि एम0एल0ए0 का स्टेट्स डी0सी0 से माड़ा है उनका कहने का मतलब यह था कि जो मैंने सबसे पहले 1972 में यहां कहा था इसके लिये गुप्ता जी जिम्मेवार नहीं है। न ही मेरे दोस्त दूसरे जो बैठे हैं, वे जिम्मेवार हैं यह तो हिस्टरी है सरदार प्रताप सिंह के वक्त से ही लेजिस्लेचर को अन्डर माइन करने की, थोड़े से दिनों में से उन करके भाग जाने की ताकि मैम्बर तंग न करें। एक्जेकटिव की यह टेडेन्सी रही है कि हाउस कम से कम मीट करे, यह मैम्बर के प्रिवलिज की एनकोचमेन्ट है, एक एक दिन में दो दो सिटिंगज हों जल्दी से खत्म हो ओर हम रास्ता पकड़े और एक्जेकटिव अपने दफतरों में जा बैठे, मेरी अर्ज यह है कि लैजिस्लेचर का स्टेट्स हमें इम्प्रूव करना चाहियें क्योंकि जनता ने हमारी आसानी कर दी है और वह जो एक्सट्रा कांस्टीच्यु इनल पावर थी, वह बेचारी अब संभल कर एक तरफ बैठेगी। हम आराम से बैठे और सै उन लम्बा हो आगर आपने एक साल और रहना है Democracy is a Government run through discussions. अगर डिसक उन हाउस में न हो तो डेमोक्रेसी क्या है फिर तो वह एक

रबड़ की मोहर है कि जो हमारी एकजेटिव फैसला कर दे हम उस पर मोहर लगा दें ओर छुट्टी करके भाग जायें। तो मेरी यह अर्ज है कि लेजस्लेचर का सै इन लम्बे से लम्बा होना चाहिये ओर सिर्फ छः महीने की जो कांस्टीच्यु इनल प्रोवीजन है, को पूरा करने के लिये हमें मजबूरी से सै इन नहीं बुलाना चाहिये ओर जल्दी जल्दी दो दो तीन तीन महीनों के अन्दर सै इन बुलाना चाहिये। अपनी इम्पोर्टैन्ट बात ये कह दें और अपनी इम्पोर्टैन्ट बात हम कह दें। मिनिस्टर्ज और एम.एल.एज. के बारे में मेरी अर्ज यह है कि सबका रूतबा चाहता हूं बड़े और Cabinet system was a failure. वह कम्पलीटली फेलुयर था। कैबनिट सिस्टम का मतलब है Chief Minister or Prime Minister is number one among equals. लेकिन 5 सालों में जो स्टेट्स मिनिस्टर्ज का रहा है जिन लोगों ने यह स्टेट्स रिड्यूस किया हुआ है हम तो उस वक्त मेंबर नहीं थे अफसोस है कि ये मिनिस्टर्ज अपना स्टेटस कायम न रख सके और They were reduced to a position by a system which has been rejected by Northern India altogether. Time has come when centralisation of power in one hand and ignoring the Legislators and Cabinet Ministers and Chief Minister becoming a Subedar in a State and the Prime Minister, a Subedar in the Centre, should be given up. एल0एल0एज0 के बारे में चुनी हुई एकजेटिव से यह कहूंगा। मैंने एक बात कही थी। चुनी हुई एकजेटिव हमको जवाबदेह है। मैं आपसे अदब से कहता हूं कि आज आप किसी भी बाहर के आदमी को जवाबदेह नहीं है अगर किसी हाउस का चीफ मिनिस्टर यह

कहे कि साहब मैं तो इस आदमी से पावर ड्रा करता है तो यह गलत बात है। मेरा चीफ मिनिस्टर हम से पावर ड्रा करता है और वह हमसब के जिम्मेदार है और किसी दूसरे आदमी के लिये जिम्मेदार नहीं है। अगर अखबारों में यह खबर निकलती है कि हमारा चीफ मिनिस्टर तो मुनीम से ज्यादा 50 रूपये से ज्यादा न खर्च सके, तो भागेभादेय बात नहीं है, हमारा सबका स्टेटस हाउस का मैम्बरज का, कैबिनेट का खत्म हो जाता है तो मैं अदब से कहूंगा, अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि जनता ने आपकी बड़ी मदद की है जनता आपके रिस्क्यु को आयी है और अब कम से कम अगर आपने यह 6 महीनों का समय या 8 महीने का समय निकालना है तो आराम से निकालो

Kindly act as our leader, as our Chief Minister and not subordinate to any person outside the House.

इससे आगे स्पीकर साहब, मैं सी.आई.डी. और पुलिस के महकमों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, इसके सिवायें और कुछ नहीं कहूंगा कि पुलिस के हाल पर हमें रहम करना चाहिये पुलिस थानों में लिस काम के लिये लगाई जाती है उन से वही काम लिया जाना चाहिये, चोर पकड़े, डाकू पकड़े मगर यह पुलिस का काम नहीं है कि कोई सेन्टर से बड़ा मिनिस्टर आ रहा है ओर फिर वे बेचारे ट्रकों वालों के पीछे पड़े और लोगों को इक्ठठा करे या रेवेन्यु वालों के साथ जा के या हैल्थ डिपार्टमेन्ट वालों के पास जाकर दिन में जनता की नसें काटें और जब रात को वापिस

आएं तो उनको भी पता लगे कि उनके लिये भी कैम्प लगा हुआ है। स्पीकर साहब, पुलिस जुल्म नहीं करती यह तो गरीब और छोटे आदमियों का महकमा है जिन बेचारों को कहीं और जगह नहीं मिलती वे बेचारे इस कम्बख्त महकमे में भर्ती हो जाते हैं। हम तो पुलिस को उनके काम के लिये पे करते हैं मगर उन से काम लेते हैं जलसे जलूसों में हाजरी इक्ठ्ठी करवाने का, नसें कटवाने का, मुलाजमों पर झुठे मुकदमें बनाने का और लोगों को यूं ही फंसाने का, इन कामों के लिये हम उनको पे नहीं करते। पुलिस की यह एक्सप्लायटे इन बन्द होनी चाहिये। We politicians have no business to exploit these poor persons. स्पीकर साहब, बातें तो और भी बहुतेरी करने वाली हैं और दूसरे मैम्बरों ने भी बोलना है और उनका हक भी है कि वे बोलें, कल का दिन सै इन है, मेरी मोनोपली तो नहीं है इन्ही अल्फाज के साथ स्पीकर साहब, अब वक्त आ गया है —

Mr. Speaker: It is very good that you have realised yourself.

Chaudhri Partap Singh Daulata: I have realised, Mr. Speaker, Sir.

So I will take my seat with a last request to the Chief Minister, through you, sir, that let there be a healthy tradition. Let him ask the Governor with this motion that this House be dissolved.

हम मैनोरिटी वाले हकूमत नहीं बना सकते। हम जिम्मेवारी से ब्यान दे रहे हैं कि हम कोई डिफेक्शन नहीं करवाना चाहते यह बुरी चीज है। अगर किसी ने आना था तो वह इलैक्शन से पहले आ जाता, आजादी के युद्ध में हिस्सा लिया होता अब कोई आयेगा तो अपने रिसक पर आयेगा, अपनी जिम्मेवारी से आयेगा उसके साथ ही यह बात है कि हम अपोजीशन वाले अपनी जिम्मेवारी में फेल होंगे जिन को कि 70 फीसदी वोट मिले है अगर 18 फीसदी वालों को हम यहां बैठने दें हमारा जो काम होगा डेमोक्रेटिक तरीके से, हम एजीटेडशन तक जाएंगे लेकिन इस गवर्नमेंट को बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री के०एन०गुलाटी(फरीदाबाद): स्पीकर साहब, गवर्नर साहब का ऐड्रेस बड़ी भुद्ध भावना से और बड़ी नेकनियती से लिखा गया और पढ़ा गया। स्पीकर साहब, मुझे अपने अपोजीशन के भाईयों की कुछ बातों को सुन कर बड़ा दुख हुआ। वे बजाये इसके कि जायज नुक्ताचीनी करें और हरियाणा की जितनी तरक्की हुई है उसका भी कुछ वर्णन करें, गलत बातें कहते रहे। अभी से इनको इतना घंमड हो गया है। दस दिन की आरजी जीत हुई है और पता नहीं 6 महीने के बाद क्या होगा। ये तो दस दिन के बाद ही खाने को पड़ रहे हैं। अभी अभी मेरे एक भाई ने जिक्र किया कि कांग्रेस(ओ) दूसरी सी०एफ०डी० तीसरी जनसंघ, चौथी सो।लिस्ट, पांचवी बी०एल०डी० और छठी अकाली। तो 70 प्रतिशत वोटों को अगर इन छः में बांटा जाए तो पौने बारह

प्रति 17 वोट एक पार्टी के बनते हैं जबकि कांग्रेस के 17 प्रति 17 है। हम जीते हैं या ये जीते हैं? मैं इनको यह भी बता देना चाहता हूँ कि ये तो पार्लियामेंट के इलैक्ट्रान थे और अब स्टेट असेम्बलीज के इलैक्ट्रान भी आ रहे हैं। तो इन इलैक्ट्रानों में इन 6 पार्टियों को 17 प्रति 17 वोट मिलेंगे और कांग्रेस को 70 प्रति 17 मिलेंगे। इसके बाद स्पीकर साहब, एक साथी ने अंग्रेजी राज ओर इस वक्त की जेल की तुलना की। इनको पता होना चाहिये कि अंग्रेजी राज में कितने जुल्म थे। उस वक्त मैंने लाठियां खाईं, गुप्ता जी के पैरों में बेड़ियां पड़ीं और प्यारा सिंह ने भी जेल काटी। एक ही कमरे में इतने लोगों को रखा जाता था और वहीं पर टट्टी पे गाब होता था। आज हमारी जेलों में बिजली के पंखे लगे हुये हैं, फ्लोर सिस्टम लगा हुआ है, अखबार पढ़ने को मिलते हैं और टैलीविजन और रेडियों की सहूलियत है। लाखों रूपये इन पर खर्च किये गये फिर कहते हैं कि इससे तो अंग्रेजों का राज अच्छा था। देश को आजाद तो हमने करवाया और बोलते हैं जनसंघ वाले। स्पीकर साहब, एक साथी ने कहा कि एम0एल0ए0 और मिनिस्टर, डी0सी0 से कम है। कितना गलत बोलते हैं। एक चुने नुमायंदे को गलत नहीं बोलना चाहिये। मैं भी फरीदाबाद से चुन कर आया हूँ। जब कभी भी चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर वहां आए हैं तो डी0सी0 हाजिर रहा है, एस0पी0 हाजिर रहा है, एस0डी0एम0 हाजिर रहा है और डी0एस0पी0 हाजिर रहा है। पता नहीं ये किस टाइम की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें करके ये सारे हाउस को गुमराह कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री

के बारे जोकि अब चली गई है ऐसे अनपार्लियामैटरी भाब्द बोलते है जिनको की कार्यवाही से काट देना चाहिये । स्पीकर साहब, भाई गौरी भांकर जी बोले में उनसे पूछना चाहता हूं कि फरीदाबाद में उनकी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री किस तरह से आगे बढ़ी है? कितनी गलतियां उन्होंने की है, जब कांग्रेस में थे तब तो बोलते नहीं थे (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी मनफूल सिंह पदासीन हुए) इसी तरह से चेयरमैन साहब, ये जितने भी मैम्बर उपोजी न में बैठे है इनमें दो को छोड़ कर सब कांग्रेस में रहे है । एम0एल0ए0 भी रहे है और मिनिस्टर भी रहे है । उस वक्त की तो कोई बात नहीं कहते और आज क्किटिसिजम करते है क्योंकि इस दिन से जनता पार्टी की जीत हुई है । तो चेयरमैन साहब, मैं यह कहूंगा कि यह हाउस बड़ा सुप्रीम हाउस है, पब्लिक हमें यहां चुन कर भेजती है । हर एम0एल0ए0 को मीठी आवाज से और नम्रता से अपने ख्यालात रखनेचाहिये । जायज नुक्ताचीनी करो, जो अच्छी बातें है उनको बताओ और कानून का एतराम करो । कानून बन गया है कि पार्लियामैट और असैम्बलीज की लाइफ छः साल हो गई है लेकिन फिर भी अगर इनको दर्द हे तो ये 10 अपनी सीटें छोड कर कर चले जाएं, हम तो 58 है । कानून के हिसाब से हमारी लाइफ छः साल है और हम पूरी टर्म गुजार कर जाएंगे । तो चेयरमैन साहब इन भाब्दों के साथ मैं गवर्नर ऐड्स की तारीफ करता हूं और निवेदन करता हूं कि यह मो न आफ किंस यूनानिमसली पास किया जाये ।

चौधीर हर स्वरूप बूरा (महम): मान योग्य चेयरमैन साहब, हमारे सामने यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उसके उपर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको भारीक करते हुये दो चार बातें कहना चाहता हूं । अभिभाषण के अन्दर अनु ासन के बारे में खास तौर से एक बात कही गई है । मैं यह समझता हूं मैं ही नहीं बल्कि सभी यह चाहते है कि किसी समाज के अन्दर अनु ासन बहुत जरूरी चीज है । लेकिन जिस ढब से इस अभिभाषण के अन्दर अनु ासन का वर्णन किया गया हे वह असलियत में अनु ासन नहीं था। मुल्क के अन्दर पिछले 19 महीनों में जो कुछ हुआ है अगर उसको अनु ासन का नाम देना है तो वह अनु ासन नहीं है बल्कि मुल्क को भाम ान बना कर रख दिया था। इसके बारे में मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि –

सितम का हद से बढ़ जाना, तबाही की नि ानी है,

बदलते है सबके दिन, पुरानी यह कहानी है ।

इसके बाद मैं भूमि सुधार के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। अभिभाषण के अन्दर इसकी बड़े जोरों से चर्चा की गई है लेकिन असलियत को वहां भी छिपा कर रखा गया है । भूमि सुधार कहने से ही भूमि सुधार नहीं होता। जब सेराज्य के अन्दर कंसोलीडे ान चला है तब से जैसे लकड़ी को घुन लग जाता है उसी तरह से किसान के लिये कंसोलीडे ान घुन का काम कर

रहा है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह दर्खास्त करता हूँ कि यह कंसोलीडे इन का मामला बहुत भीघ्र ठीक होना चाहिये और इसको ओर लम्बा नहीं होने देना चाहिये। इसके बाद चेयरमैन साहब, मैं थोड़ा सा एजुके इन पर भी बोलना चाहता हूँ। जहाँ तक रोहतक यूनिवर्सिटी का सवाल है मैं रिक्रूटमेंट के संबंध में आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरे विचार संकीर्ण नहीं, मैं चाहता हूँ कि वहाँ भारत के व्यक्तियों की और हरियाणा के व्यक्तियों की रिक्रूटमेंट हो लेकिन जब एक रीजनल यूनिवर्सिटी से योग्य व्यक्ति मिलते हो तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। दूसरी बात मैं स्टाफ के क्वार्टर्ज के बारे में कहना चाहता हूँ। जब टीचर्ज की ट्रांसफर होती है तो उनको निवास की बड़ी दिक्कत पैदा होती है इसलिये हर स्कूल के साथ यदि स्टाफ क्वार्टर्ज बन जाएं तो उन लोगों की यह दिक्कत दूर हो सकती है।

तीसरी बात रिडक् इन की है। डी0ए0 कट करने की बात हरियाणा में खासतौर पर होती हैं बहुत पहले से आज तक अध्यापको का डी0ए0 कट चला आ रहा है, लेकिन इस पर सरकार ने अभी तक गौर नहीं किया है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इस डी0ए0 को बहाल किया जाये।

चौथी बात मैं विक्टेमाइजे इन के बारे में कहना चाहता हूँ। एजूके इन डिपार्टमेंट में पिछले पांच छः सालों से विक्टेमाइजे इन बड़ी जोरों से हो रही है। मैं , चेयरमैन साहब,

आपके द्वारा सरकार से दुर्खास्त करूंगा कि इस पर गौर फरमाया जाये ।

टूरीजम का जहां तक ताल्लूक है, हरियाणा में टूरीजम पर कितना काम हुआ है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे समाज के अन्दर हरिजन बस्तियां इतनी गन्दी है जो कि समाज के माथे पर एक कंलक है । टूरीजम का महत्व तभी होगा जब हरिजन बस्तियों से यह गन्दगी खत्म हो, हर गली में ट्यूबलाइट हो, हर प्रकार की सुविधा हो जो दूसरो को उपलब्ध है । अगर हरिजन बस्तियों से बदबू आती है और सरकार हरियाणा के अन्दर टूरीजम खोलती जाए तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये फख की बात नहीं है लानत की बात है । सब से पहले इन बस्तियों को सुधारा जाना चाहिये तथी टूरीजम का महत्व है ।

अगली बात मैं परिवार नियोजन के बारे में कहूंगा । वैसे तो फैमिली प्लानिंग की बात करके लोगों की भावनाओं को दोबारा उकसाना नहीं चाहता लेकिन एक बात कहूंगा कि परिवार नियोजन होना चाहिए । फैमिली प्लानिंग होनी चाहिये लेकिन नसबन्दी नहीं होनी चाहिये । इस बारे में मैं खुले विचार रखता हूं और जाति तौर पर कह रहा हूं कि परिवार नियोजन इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये दे । के लिए बहुत जरूरी है लेकिन नसबन्दी ही इसका इलाज नहीं है । यह जरूरी नहीं है कि नसबन्दी से ही परिवार नियोजन हो सकता है, और भी उपाय है । मैं अपने

साथियों की तरफ से विवास दिलाता हूँ कि नसबन्दी की बजाये दूसरे मैथड अपनाए जायें, तभी इसमें कामयाबी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि परिवार नियोजन सारा मुल्क चाहता है, लेकिन नसबन्दी न हो, दूसरे मैथड अपनाये जाये।

चेयरमैन साहब, कानून के बारे में अभिभाषण में जिक्र है। मैं चाहता तो नहीं था कि इस पर बोलूँ, लेकिन तबीयत करती है कहने के लिए। हरियाणा में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी एमरजेंसी के दौरान। मैं डायरेक्टर आफ कंसोलिडे एन की कोर्ट से पकड़ लिया गया, मैंने कोई जुल्म नहीं किया था, न ही कोई भाषण ही किया था। मैं डायरेक्टर आफ कंसोलिडे एन की कोर्ट में केस पलीड कर रहा था, वहां से मुझे अरैस्ट किया गया। दोबारा जब मुझे रिलीज किया, ज्यों ही मैं बाहर निकला तो मुझे दफा 107, 151 के तहत बस में बैठाकर जेल में ले गए ओर डी0आई0आर0 लगा दी। मेरे जैसे आदमी को इस तरह से परे गान किया जाता है। हरियाणा के अन्दर तो कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। चेयरमैन साहब, यहां पर गरीबों के नाम की बड़ी चर्चा होती है। मैं सरकार से दर्खास्त करूंगा कि जो लोग, सड़कों पर सुबह से भाम तक रोड़िया कूट-कूट कर हाथ तोड़ते हैं, उनकी मजदूरी 4रूपये 30 पैसे है। चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ, सबमि एन भी करता हूँ कि उनकी मजदूरी कम से कम 6 रूपये करदी जाये। इन भाब्डों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री अमर सिंह(बवानीखेड़ा ऐस0सी): माननीय चेयरमैन साहब, सदन में राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है और उस पर श्री गुलाब सिंह जैन की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने अभिभाषण पर कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि जो नुक्ताचीनी की है, वह अभिभाषण से बाहर जा कर की है जिसका मुझे खेद है। हाउस के आनरेबल मेम्बर चौधरी रिजकराम जी, जब रिसोसिर्ज कमेटी के चेयरमैन थे और इसी बेंच पर बैठते थे तो हरियाणा का विकास ऊंचे स्तर का था और आज हरियाणा में विकास नहीं। ये हरियाणा के विकास के नाम पर चार चांद लगाते रहे, लेकिन आज इनकी जबान से ये भाब्द सुनकर मुझे खेद होता है। इसी तरह से हमारे साथी चौधरी भजनलाल जी है जो इन बेंचों पर इसी सदन में बैठते थे। वे आनरेबल मिनिस्टर रहे हैं, हाउस के आनरेबल मैम्बर भी रहें। जब ये कांग्रेस के इन बेंचों पर बैठते थे तो कहा करते थे कि सब कुछ ठीक है। आज ताज्जुब की बात है इन्होंने अभिभाषण को चैलेंज किया कि गवर्नर महोदय को इस हाउस में एड्रैस पेश करने का अधिकार नहीं था क्योंकि हाउस की लिमिट 5 साल की थी। जब रैटिफिकेशन के लिए कांस्टीच्युशनल अमेंडमेंट हाउस के सामने आई तो चेयरमैन साहब, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इन्होंने रैटिफिकेशन में बीट दिया था, इन्होंने इन्कार भी नहीं किया था ओर वोट में भागमिल थे। मुझे चौधरी प्रताप सिंह दौलता को सुनकर ताज्जुब होता है, वे हाउस के पुराने पार्लियामेंटेरियन

हैं, वकील भी हैं, वे हाउस में एक बात कह कर गये है। यह ठीक है, नसबन्दी का सरकार को एक इन का री-एक इन मिला है, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। लेकिन उनका इस बात पर गर्व करना और गलत ढंग से बात करना, हाउस में अपाबद्ध इस्तेमाल करना, कानून की मर्यादा के अन्दर न रहना, यह जाहिर करता है कि ये वही हालात पैदा करना चाहते हैं जिन का 25 जून, 1975 को, रामलीला ग्राउंड में श्री जय प्रकाश नारायण ने एलान किया था और कहा था कि बगावत करो, फौज को हुक्म नहीं मानना चाहिये, पुलिस को हुक्म नहीं मानना चाहिये। आज दौलता साहब, चाहते हैं कि अगर वे कानून की हालत खराब कर देंगे, इसी तरह के हालात पैदा करेंगे जो पहले थे तो गवर्नर साहब एलान कर देंगे कि ला-एंड-आर्डर की सिंचुए इन ठीक नहीं है। चेयरमैन साहब, यह ठीक है कि इलैक्ट्रान में कांग्रेस पार्टी को नौर्दन जोन में हार हुई है, हम इसे तसलीम करते हैं, जनता का वर्डिक्ट है, जमहूरियत में जनता जनार्दन है लेकिन जब 30 साल के पुराने भासन को जनता अगर गिरा सकती है तो इस 10 दिन की हकूमत को इनको भी जनता उखाड़ सकती है अगर ये कानून को कानून न समझेंगे। अगर इसी तरह कानून का गला घोंटना भुरु कर दिया जिससे जनता को घृणा पैदा हो तो क्या यह उचित होगा। एक साथी ऐसी बात कह गये है जो खुद ही भी े के मकान में बैठे हैं और दूसरों पर पत्थर फेंकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन लेना पड़ रहा है, वे गौरी भांकर नरवाना के रहने वाले हैं। इन्होंने जींद में फलौर मिल लगाया और ऐसे

एरिये में लगाया जहां लगाने की इजाजत नहीं मिल सकती थी और जो इजाजत देने वाले हैं उन्हीं के खिलाफ वे बोल कर गए हैं। उस वक्त तो इन का गला सूखता था जब हरियाणा की प्रगति को देख कर कहा करते थे कि ऐसा हरियाणा का निर्माता पैदा नहीं हुआ है। चेयरमैन साहब, आप डिबेट निकलवाकर देख लें, ये भाब्द मिलेंगे। मैं कह रहा था कि हरियाणा में देहात में 82 प्रतिशत आबादी है। इससे पहली बात भायद, चेयरमैन साहब, आपको याद होगा, चौधरी रिजकराम ज्वांयट पंजाब में इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर होते थे। मैं भी उस समय 1962 से 1967 तक एम0एल0ए0 रहा हूँ। हमें पता है कि उस समय हमारी मर्यादा क्या थी। हम (17.00 बजे) क्या कर सकते थे हरियाणावासी जो उस समय ज्वांयट पंजाब में भागमिल थे लैप्स होता था हमारा बजट 31 मार्च को और उसके बाद उसे पंजाबी रीजन में खर्च किया जाता था। पंजाब में हम तरसते थे एक एक बिजली के लट्टू को, एक एक स्कूल की अपग्रेडिंग के लिए और एक एक किलोमीटर सड़क के लिए। हम वे दिन बिल्कुल भूल गये। मैं तो कहा करता हूँ कि देहात आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और हरियाणा आजाद हुआ 1 नवम्बर 1966 को। हम सैकिन्ड रेट सिटिजन गिने जाते थे। हमें कोई आजादी नहीं थी। हमें आजादी का जो हिस्सा मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता था। चेयरमैन साहब, अभी अभी मैंने कहा कि हम 1 नवम्बर 1966 को आजाद हुये और मई 1968 में जब चौधरी बंसी लाल मुख्य मंत्री बने उन्होंने विकास की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने फैसला किया कि

हरियाणा का विकास किस तरह हो सकता है। हरियाणा देहात का प्रदे 1 है। देहात में लोग ऐग्रीकल्चर पर डिपैन्ड करते हैं। ऐग्रीकल्चर को पानी की सुविधा न मिले तो फार्मर उभर नहीं सकता। अगर फार्मर नहीं उभरेगा तो उससे लगी हुई दूसरी बिरादरियां, खाती, लोहार और चमार आदि, भी नैचुरैली नहीं उभरेगी। इस नतीजे पर पहुंच कर चौधरी बंसी लाल ने इन्फास्ट्रक्चर तैयार किया और विकास के काम जोर भाोर से भुरु किए। कौन कहता है कि हमारा विकास नहीं हुआ? हम माइनस जीरो बेस से उपर उठे है। जिस समय हरियाणा बना हम अनाज बाहर से लेते थे। हम तनख्वाह नहीं दे सकते थे कर्मचारियों को। पंजाब के भाई हमारा मजाक उड़ाते थे। वे कहा करते थे कि हरियाणा चूंकि वायेबल यूनिट नहीं है इसलिये इसको पंजाब में ही भाामिल कर लो। आज हरियाणा की क्या स्थिति है? यह ठीक है कि एक पार्टी जो रूल करती थी वह चुनाव में हार गई लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विकास नहीं हुआ। यह ठीक बात है कि किसी वजह से जनता नाराज थी या हम यह समझते है कि एक इन का रीऐक् इन इनके हाथ लग गया या यों कहें कि लोग इस बात से अंसतुष्ट थे कि फैमिली प्लानिंग में उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं हुआ। इसके बातजूद भी अगर हम एक बात को इग्नोर करके चले तो यह कोई कंस्ट्रक्टिव क्तिडिसिज्म नहीं है। अगर हम असल को न पहचाने और असल को भूलकर एक ऐसे रास्ते को अपना ले जिसमें हरियाणा का जो विकास हुआ है उसमें भी धोखा

लगे और आगे भी अपने विकास से हट जाएं तो चेयरमैन साहब कोई अच्छी बात नहीं होगी।

चेयरमैन साहब, भिवानी के बारे में यहां एक बात आई। मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी से ताल्लूक रखता हूं। बवानी खेड़ा मेरी कांस्टिचुऐंसी है जो टेल पर है। यहां यह बात आई कि जुई, लोहारू और बीरेन्द्रनारायण चक्रवर्ती कैनल में सारी पानी रोहतक का ले गये, भाखड़ा का ले गये और वैस्टर्न जमुना कैनल का ले गये। यह गलत ब्यानी है। आपको पता है कि करनाल में डीप ट्यूबवैल लगे हैं जिनका पानी जुई कैनल में ले जाया जाता है न बीरेन्द्रनारायण चक्रवर्ती कैनल का पानी भाखड़ा से ले जाते हैं और न वैस्टर्न जमुना कैनल का पानी जुई में जाता है। आज तो बवानी खेड़ा कांस्टिचुऐंसी की हालत यह है कि वहां लोगों की प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी बढ़ सकती है अगर उसे पानी मिले। आज वहां पानी जरूरत के मुताबिक न मिलने की वजह से किसान की हालत कमजोर है। इसलिये यह बात बिल्कुल निराधार है यदि कोई यह कहे कि किसी का पानी काट कर वहां ले गये है।(विघन)।

चेयरमैन साहब, ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने में आज दे 1 में हरियाणा का नाम दूसरे नम्बर पर है। सारे दे 1 में ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने में पंजाब टाप पर है। इसी तरह से जहां तक सैन्ट्रल पूल में अनाज देने की बात है इसमें भी पंजाब पहले नम्बर पर है और हरियाणा दूसरे नम्बर पर है। चेयरमैन

साहब, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये दो ही चीजें अत्यन्त आवश्यक हैं इलेक्ट्रिसिटी और पानी और इन दोनों साधनों पर, चौधरी रिजकराम जी भी मानेंगे, सारे बजट का 72 परसेंट रूपया आज तक खर्च होता रहा है। यही नहीं इस गवर्नर साहब के अभिभाषण में भी 80 प्रतिशत राशि इरीगेशन पर खर्च करने की व्यवस्था रखी गई है। (विधन) यह सारा पैसा हरियाणा में ही खर्च हो रहा है पाकिस्तान में खर्च नहीं हो रहा। अगर आप भिवानी और महेन्द्रगढ़ आदि इलाकों को हरियाणा न समझें तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वे हरियाणा का ही पार्ट हैं। ड्रेन नं० 8 रोहतक को तबाह करती थी। उस ड्रेन को कंवर्ट करके आबपाणी के लिये इस्तेमाल किया गया। जिस ड्रेन के बारे में चौधरी रिजकराम जी कहा करते थे कि वह सांप का काम करती है उसी ड्रेन को चौधरी बंसी लाल ने कंवर्ट करके आबपाणी के लिए इस्तेमाल किया है ताकि हजारों किसानों का उत्पादन बढ़े और लाखों लोगों को रोजी मिले।

चेयरमैन साहब, जहां तक सड़कों का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि हमारे 70 परसेंट गांव सड़कों से जुड़े हुये हैं और गांव को भी सड़कों से जोड़ने के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील है। गवर्नर साहब ने भी अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है कि इस मद पर और अधिक पैसा खर्च किया जायेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा गांव सड़कों से जुड़ जायें। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुईं)

जहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम का सवाल है 2,14753 हरिजनों को और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को रिहायगी प्लॉट देने की योजना बनाई गई थी और आपको जानकर खुशी होगी कि 213377 हरिजनों को और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को प्लॉट मिल गए हैं और उन पर 25000 मकान बनाने की व्यवस्था है। चेयरमैन साहब, मैंने ऐसा समय भी देखा है जब बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद रिक्का वाले का पैसा मिला है, गरीब लोगों को भैंस खरीदने के लिये पैसा मिला है, इतना ही नहीं हरिजनों को टाईम बाउन्ड पीरियड में 25000 रिहायगी मकान बनाने के लिए चार परसेंट ब्याज पर पैसा दिया गया है। साढ़े तीन हजार रूपये उन्हें मकान को पक्का बनाने के लिये भी दिये गये हैं। यहीं नहीं तीन हजार रूपये और अपनी इच्छा के अनुसार भैंस खरीदने के लिए या जुती बनाने का काम करने के लिये या खड्डी आदि का काम करने के लिये दिए गए हैं। यह सब 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हुआ है। इससे हजारों आदमियों को जो भाहरों में रहते थे फायदा पहुंचा है। हो सकता है चौधरी रिजकराम जी को सोनीपत में कभी इस बात को देखने का मौका मिला हो। काफी गहराई से देखने के बाद यह पता चलेगा कि एक एक आदमी दस-बारह रिक्का रखता था और वह रिक्का चलाने वाले से 60 रूपये महीना मुफ्त में लेता था और वह बेचारा मुकिल से पांच रूपये रोज कमाता था। वह बेचारा गीरब अपने खून-पसीने को बहा कर मुकिल से चार-पांच कमाता था। इन बैंको के खुलने से काफी गरीब लोगों ने नयी रिक्का खरीदी। लोगों को बैल खरीदने के

लिए, भैस खरीदने के लिए, ऊंट गाड़ी खरीदने के लिये बैंकों ने पैसा दिया।

इसी प्रकार 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के तहत नये आऊट-लैटस दिये गये, नयी नयी माइनर्ज बनायी गई, कुछ में आलट्रे इन की गई, नयी एक्सटैन् इन भी की गई। इस प्रकार से 20 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत काफी लोगों को फायदा हुआ।

हरियाणा में हैंडलूम एन्ड हैंडी क्राफ्ट कारपोरे इन बनायी गई है। जो गरीब आदमी अपने हाथ से काम करने वाले है, वे सड़क पर बैठ कर काम करने की बजाये स्थायी रूप से अपने घर पर काम कर सकते है। उनको सरकार की और से लोन दिया गया है। दो करोड रूपये से यह हैंडलूम एन्ड हैंडी क्राफ्ट कारपोरे इन बनायी है। इस कारपोरे इन से 1838 वीवर्ज को फायदा पहुंचा है। जनवरी से अब तक इतने लोग इस कारपोरे इन से फायदा उठा चुके है और अब उसका काम जारी है।

अब डिप्टी स्पीकर साहिबा, सड़क और ट्रांसपोर्ट का सवाल है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में इस ऐंज्रैस में यह कह दिया है— This department has been catering to the needs of about 511000 passengers daily and its buses have been covering about 440000 Kilometers every day. The fleet strength which was 1680 buses at the end of the financial year 1975-76 now it has been raised to 2100 buses by the end of the current financial year.

डिप्टी स्पीकर साहिबा जहां तक बसों का सवाल है, यह ठीक है कि बहुत सारी बसों के ब्रेक डाउन होते हैं लेकिन दूसरी पड़ोसी स्टेट्स की बसों में सफर करके देखो तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा में कितनी एफिं येन्ट सर्विस है। ट्रांसपोर्ट में हमारी नुमाया तरक्की हुई है।

गवर्नर साहब ने अपने एड्रैस में पिछले साल का खुलासा दिया है और आगे आने वाले साल के बारे में रावी ब्यास के पानी के विशय में बताया है कि 16 करोड़ रूपये की राशि खर्च किये जाने की आशा है। इस कैरियर को बना कर ज्यादा पानी की व्यवस्था की जायेगी। मैं तो यह कहता हूँ कि चाहे कोई कांग्रेस में बैठता हो चाहे कोई अपोजीशन में बैठता है अगर वह हरियाणा के हित को इग्नोर करता है तो उसको जनता बरदास्त नहीं करेगी। अब जो हमें नया पानी मिलेगा वह 17 लाख एकड़ के लिए मिलेगा। हमारे लीडर आफ दी हाउस ने इस बात पर बल दिया है कि यह जल्दी से जल्दी बनायी जायेगी। सैन्टर में हमारे इरीगेशन एन्ड एग्रीकलचर के नये मिनिस्टर श्री प्रकाश सिंह बादल आये हैं। अब तो हमें और भी ज्यादा आसानी हो जायेगी। पंजाब रीजन में जो कैरियर बनना है उसको जल्दी से जल्दी बनवायेंगे ताकि टाईम बाउन्ड प्रोग्राम के अनुसार यह काम पूरा हो जायेगा। ऐसा होने से हरियाणा में खुशहाली बढ़ेगी। जो वाटर अलाउन्स बढ़ा है उससे हमारी आनेवाली नसल खुशहाल होगी। उनकी खुशहाली नहर के पानी पर ही डिपैन्ड करती है।

इन भावों के साथ, बाबू गुलाब सिंह जी ने जो मोराना आफ थैक्स मूव किया है, उसका समर्थन करता हूँ और गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण दिया है उसकी ताइद करते हूये अपना स्थान लेता हूँ।

श्री रामधारी गौड़ (गोहाना): आदरणीय मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार चल रहा है। आप जानती है कि जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है वह सरकार की नीतियों, उसके कामों का चाहे वे विकास के काम है, चाहे जनता के हित के काम है उसका आइना होता है। इस गवर्नर एड्रेस को पढ़ने से यह पता चलता है कि यह बिल्कुल धुंधला है, इस एड्रेस के अन्दर कोई साफ चीज दिखायी नहीं देती है। जो आइना आज से पांच साल पहले का था वहीं आज है। इसमें कोई नयी बात दिखायी नहीं देती है।

मैं मानता हूँ कि पानी के बारे में, बिजली के बारे में हरियाणा में बहुत ज्यादा काम हुआ है। इस बात को तमाम देखा मानता है बल्कि दुनियां मानती है कि हरियाणा में इन दोनों क्षेत्रों में काम हुआ है लेकिन वह काम आज से पांच साल पहले आरम्भ हुआ था, बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रहा है।

आप जानती है कि ब्यास का पानी हमारे लिये कितना महत्व रखता है। उस पानी के लिये जैसे पपीहा एक पानी की बूंद के लिये चीखता रहता है इसी प्रकार से हरियाणा का किसान भी

पिछले साल से आ आ लगाये बैठा है। हमारे वजीर खजाने ने अपने एड्रैस में यह कहा है कि हमें कुछ पैसे की बचत इस तरीके से हो जायेगी कि जो सतलुज यमुना लिंक है वह भायद तेजी से नहीं बनेगा और उसका पैसा बच जायेगा। मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पैसे को मत बचाइयें, मैं तो कहूँगा कि बे तक दूसरे कामों को बन्द कर दें लेकिन सतलुज यमुना लिंक है इस पर जोरों से काम चलाया जाये। यह हरियाणा की लाइफ लाइन है। जैसे जीवन में लाइफ लाइन काम करती है इसी प्रकार से ब्यास का पानी हमारे लिये जीवन है। इस काम पर सुस्ती करना और बचत करना अपने आपके साथ धोखा करना है।

गुप्ता जी ने मेरे विशय में अपनी स्पीच में एक बात कही कि मैंने 20 सूत्री प्रोग्राम का विरोध किया। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने बीस सूत्री प्रोग्राम के बारे में यह कहा कि हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने जो बीस सूत्री प्रोग्राम बनाया है वह हमारी आ आओं से बाबस्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी लोगों ने इसे पसन्द किया है, लोगों ने आ आ लगायी कि इससे दे आ की जनता का भला होगा, जनसाधारण का भला होगा, कीमतों के भाव नीचे आयेगें, दे आ में प्रोडक्शन बढेगी, गरीब आदमी की गरीबी मिटेगी। यह हमारा बहुत बड़ा स्वप्न था। मैंने अपनी स्पीच में यह जिक्र किया था कि जब इलैक्शन के सिलसिले में हम देहातों में गये तो हमें एक सूत्र दिखायी दिया

बाकी नजर नहीं आया। वह एक सूत्र था नसबन्दी का। अगर गरीब आदमी की दगा ठीक हुई होती जैसी कि बीस सूत्री प्रोग्राम में आया थी, यह मैं नहीं कहता कि बिल्कुल काम नहीं हुआ लेकिन जो उम्मीद थी उसमें एक नसबन्दी सूत्र ही आया से अधिक मिला जो कि जनसाधारण तक पहुंच गया। वे यही कहते हैं कि हम काट कर डाल दिये। वे आम बात चाहते तो हमारे साथ इस तरह नहीं होता। उनसे हम तो एक ही बात कहते थे कि मैं कांग्रेस का मेम्बर जरूर था लेकिन कांग्रेस में होते हुए भी मुझे अपोजिशन का मेम्बर समझा जाता था। जो व्यवहार अपोजिशन पार्टी के मेम्बर के साथ होता था वही व्यवहार हमारे साथ होता था। इस वास्ते हम तो बच गये लेकिन जो दूसरी तरफ झुके हुये थे वे सब लपेट में आ गये। गुप्ता जी यहां बैठे नहीं हैं। मैंने जो बीस सूत्री प्रोग्राम का जिक्र किया था वह इस ढंग से किया था। वे मेरी बात को समझे नहीं। मैंने तो इतनी बात कही कि उसका इम्पैक्ट बहुत कम पाया। हरिजनों के प्लॉट्स के बारे में वे कहते हैं। केवल बीस फीसदी हरिजनों को प्लॉट्स दिये गये हैं जो उनकी मुहार में पड़ते थे बाकी को गांवों के दूसरी तरफ को दे दिये गये। अब कौन ऐसा हरिजन होगा जो अपने पुराने रिहायशी मकान को छोड़कर सौ गज के प्लॉट के लिए दूसरी तरफ जायेगा।

पंडित चिंरजी लाल जी यहां पर नहीं हैं। मैंने उनको दो-तीन गांवों की मिसालें दीं। वे कहने लगे कि इस वक्त मेरे पास यह महकमा नहीं है, मेरे पास शिक्षा का महकमा है।

उपाध्यक्ष महोदया, चौधरी माडू सिंह मलिक अब इस डिपार्टमेंट को संभाले हुये है। अगर उनके नौटिस में कोई बात लायी जाये तो वे इस और ध्यान देते है। लेकिन उस वक्त यह महकमा इनके पास नहीं था। पंडित चिंरजी लाल जी ने भी यह वायदा किया था कि हम यह कोर्ि । । करेगें कि उस पाने में हमें जो भी जमीन मिल पायेगी, हम उसे मोल लेकर उन लोगों को प्लाट देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं ह। मुझे पता है कि जिस जिस गांव के नाम में लिखवा आया था, उस गांव में वहीं पर प्लाट मिल रहें है, जोकि पिछली स्कीम के तहत पड़ते थे। न कोई जमीन खरीदी गयी और न उनको नई जगह पर प्लाट दिये गये। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं बीस सूत्री प्रोग्राम के बारे में। मैं देखता हूं कि कितनी बड़ी बड़ी स्कीमें होती हैं। सब चकाचौंध करने वाली चीजें होती है। इनका नतीजा क्या होता है? जनसाधारण को कितना फायदा होता है, यह देखने वाली बात है। आप सब जानते है कि जमींदार यह चाहता है कि उसके खेत में पानी आये। कितने ही आप उस को वायदे करें, जब तक उसके खेत में पानी नहीं पहुंचेगा, उसको यकीन नहीं आयेगा। वह तो यह चाहता है कि उसको वाकई लाभ मिले। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बीस सूत्री प्रोग्राम का इस इलैक् ान के दौरान ज्यादा लाभ नहीं हुआ। जो कुछ उनके साथ ज्यादातियां हुई थी, इसका बदला उन्होंने लिया। इसी वास्ते लोगों ने वोट नहीं दिया और अपना गुस्सा निकाल लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि कितनी बढिया से बढिया स्कीम क्यों न हो, जब तक उसका नतीजा बढिया न हो

, वह बेकार होकर रह जाती है। अब यह चीजें जो कही गयी थी यह तो खतम हो गयीं क्योंकि अब नयी हुकुमत आयी है। उस प्रोग्राम में कोई नुक्स नहीं है। अगर अब हुकुमत यह समझे कि वह तो प्रोग्राम उस गवर्नमेंट के साथ ही गया तो यह गवर्नमेंट के हित की बात नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री जो बीस सूत्री प्रोग्राम हमें देकर गयी हैं, हमारा सब का फर्ज है, उसको हम कामयाब बनायें क्योंकि वह जनहित के लिये है, किसी एक के हित के लिये नहीं बल्कि सबके हित के लिये है। वह प्रोग्राम नेान के नाम से था या प्रधानमंत्री के नाम से था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कुछ भाइयों ने उसका नाजायज फायदा उठाना चाहा, जिसकी वजह से लोग कुछ चिढ़ से गये वरना आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नेान की रहबर होती है। लोग उस प्रोग्राम को अब भी अपनाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह एक अच्छा कार्यक्रम है। अगर कोई आदमी इसकी कुखलिफत करें तो मैं यह समझता हूँ कि वह देान के खिलाफ है क्योंकि वह जनसाधारण के फायदे की चीज है। उसकी अगर कोई मुखालिफत करता है, चाहे वह किसी पार्टी से ताल्लूक रखता है तो यह जनता के हित की बात नहीं है बल्कि हमें तो सब को उसमें सहयोग देना चाहिये। पार्टी चाहे कोई भी हो आखिरकार हम लोगों के नुमायन्दे है। हम लोगों के हित के लिये यहां पर आये है। यह नहीं कि हम अपनी पार्टी का प्रोग्राम बनाकर चले। इसलिये हमें तो नेान के फायदे का प्रोग्राम लेना है। नेान के फायदे के लिये, नेान को आगे बढाने के लिये जो जन हित के

लिये हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें वह काम करना चाहिए। हमारे अन्दर यह भावना नहीं होनी चाहिये कि यहां फलां पार्टी का कार्यक्रम है इसलिये हम इसे नहीं अपनाते। हम तो जनता के नुमायन्दे हैं हमारा एक ही काम है और वह यह कि ऐसे कार्यक्रम को हम अपनाये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कह रहा था कि इस वक्त जो पिछले 5 सालों मे काम हुआ है, यह आपने भी महसूस किया होगा कि यह सारा का सारा काम एक ही इलाके में हुआ है। यह काम बैकवर्ड इलाके का नाम लेकर किया गया है जबकि दो तीन जिले ऐसे है जो इस एक जिले की निस्बत ज्यादा बैकवर्ड है। लेकिन आपको पता है वैकवर्डनैस का नाम लेकर एक ही इलाके मे काम हुआ है। जितना पैसा था उसका 50 प्रति ात से ज्यादा रूपया उस इलाके में खर्च किया गया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने पिछले दिनों भिवानी में जाकर खुद देखा कि कहीं लाल बत्ती और हरी बत्ती लगी हुई जो बड़े-बड़े आउन्ज होते है, जो भी बड़े-बड़े सिटीज होते है जहां पर गाडियां बहुत ज्यादा चलती हैं वहां पर ऐसी बत्तियां लगायी जाती है ताकि ऐक्सीडेंटस न हो जायें लेकिन वहां पर जहां पर ऊंट चलते हों लाल-हरी बत्तियां लगा देना कहां की भाभा की बात है। आप देखिये ऊंट वहां से निकलते है और वहां पर बत्तियां लाल-हरी लगा दी गई है। इन बत्तियों के लगाने का मुद्दा यह होता है इन बत्तियों के लगाने का मकसद यह होता है कि जहां पर र 1 आफ ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां पर ऐक्सीडेंटस को अवायड करने के लिये लगायी जाती है। र 1 को कन्ट्रोल करने के लिये यह बत्तियां

लगायी जाती है। यह नहीं कि जहां पर ऊंट निकलते हो जिनकी स्पीड कोई दो-तीन सौ मीन नहीं केवल दो-तीन मील की स्पीड हो, वहां पर यह बत्तियां लगा दी जायें। वहां जाकर आप सड़कें देखिये। वह तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। वहां पर इतनी सड़कें हैं कि कुछ पता ही नहीं। वहां पर लोगों के साथ कितनी कितनी ज्यादतियां हुईं, उसको जाकर देखो। हम जब भिवानी गये तो वहां के लोगों की जब हम ने जुलमेदास्तान सुनी तो हमें बहुत दुख हुआ। इसके बावजूद कि वहां पर हरियाणा का 50 प्रतिशत पैसा खर्च किया गया, उनकी दास्ताने गम सुनने वाली थी। उन लोगों के उपर जो जुल्म किये गये वह नहीं होने चाहियें थे। आखिरकार, ये मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों के नुमांयदे हैं। हमरार यह काम होना चाहिये कि हम उनकी दुख तकलीफ चाहे वह किसी भी किस्म की हो, वह दूर करें। हमें चाहिए कि हम उनके जख्मों पर फोहा लगायें। यह नहीं होना चाहिए कि ताकत के नौ में अकडे कि हमारे पास भाक्ति है और जो हमारे सामने बोलेगा उसको दबाकर रख देंगे और विकास के नाम पर हम यह सोचे कि बदला लेना है। किसी की कोई चीज हो, किसी की कोठी हो उसको खत्म कर दे। इस किस्म की बात भाभा नहीं देती। राज्यपाल महोदय ने कई बाते अभिभाषण में कहीं। मैं समझता हूं कि वह एक तस्वीर है कि आगे क्या होना है। जैसा कि दौलता साहब ने बताया कि अगली धुंधली है, वह तस्वीर साफ नहीं दिखाई देती। वह एक जुल्म की दास्तान दिखाई देती है।

श्री अमर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या कोई अनरेबल मेंबर बोलते हूये चेयर को डंडी दिखा सकता है?

Deputy Speaker: There is no question. It is wrong. This is no point of order.

श्री रामधारी गौड़: उपाध्यक्ष महोदया, आप तो वैसे ही पूजनीय है और सदन में आपके साथ पुराना संबंध है। श्री अमर सिंह जी तो बहुत बाद में आए है। पेन्सिल कोई लड़ाई के काम नहीं आ सकती। इस पेन्सिल से कानूनी लड़ाई तो लड़ी जा सकती है।

उपाध्यक्षा: आप अपनी स्पीच जारी रखें।

श्री रामधारी गौड़: उपाध्यक्ष महोदया, श्री अमर सिंह में तो पुरानी आदत है कि इनके दिमाग में छेडने की बात आ जाती है। मैं बता रहा था कि जो तस्वीर है वह धुंधली हैं। चण्डीगढ़, अबोहर और फाजिल्का का अहम सवाल है। हरियाणा में कहावत है कि सोते का काटड़ा और जागते की कट्टी। इसका मतलब है कि कोई आदमी अगर अपने हकूक के लिए आंख बंद करके बैठा रहे तो वह घाटे में रहता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, फाजिल्का और अबोहर के लोग हमारे भाई है। उनकी ख्वाहिश है कि वह हमारा अंग बने। उनका विकास भी नहीं हो रहा है और जानबूझ कर उस इलाके का विकास नहीं किया जा रहा है। क्योंकि उधर की सरकार को मालूम है कि हिन्दी बोलने वाले इलाके हरियाणा में जायेंगे इस लिये वहां का विकास कम हुआ है। उन लोगों की

बहुत इच्छा है कि हरियाणा के साथ मिलें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस तरफ से पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी मैक्सिमम कुर्बानी मांगेंगे हम वह देने के लिए तैयार हैं। वे लोग भी इधर आना चाहते हैं और सरकार की तरफ से भी हमें वह इलाका ऐवार्ड में मिला है। यह तो वह बात हुई जैसे किसी को सिविल कोर्ट से डिग्री मिल जाये और जिस चीज की डिग्री मिली है वह उसे हासिल न कर सके। यह तो उसकी कमजोरी है। फ़ैसला हमारे हक में था और वह लोग भी चाहते हैं तो फिर अड़चन कौन सी है। अड़चन यही है कि हम इस मामले में सीरियस नहीं हैं वरना किसी की हिम्मत नहीं कि वह इलाका हमें न मिले। आज साढ़े आठ साल हो गये हैं इतने दिनों में तो डिग्री मिल जाती है। जो डिग्री कोर्ट से मिलती है वह भी तीन-चार साल में खत्म हो जाती है इसको साढ़े आठ साल हो गये हैं। यह स्टेट का मामला है। इसको हासिल करने के लिए हम सब को मिलकर अपनी ताकत लगानी चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं गोहाना के बारे में कहना चाहता हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि वहां पर एक भूगर मिल लगनी चाहिए। भूगर मिल वहां के लिए जरूरी है। गोहाना का इलाका ऐसा है जहां गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है कि किसी और इलाके में इतना गन्ना नहीं होता। यमुना नगर में भी गोहाना की निस्बत कम गन्ना पैदा होता है और अब तो भाहबाद में भी मिल लगने वाली है। जब भी कोई स्कीम होती है तो गोहाना को छोड़ दिया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम

अपनी बात को यहीं ही कह सकते हैं। मैंने एक और दिन भी बताया था कि पांच साल में वहां कोई काम नहीं हुआ है।

चौधरी मेहर चन्द: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आन ए प्वाएंटा आफ आर्डर, मैं एक कलेरिफिके टन चाहता हूँ कि इन्होंने एक मोहमिल भाब्द श्री अमर सिंह के लिए इस्तेमाल किया है यह इनकी पुरानी आदत है। यह कौन सी आदत है ये हमको यह बता दें जिससे हम भी आगाह हो जाएं।

उपाध्यक्ष: यह प्वाएंटा आफ आर्डर नहीं है।

श्री रामधारी गौड़: आप तो बहुत देर से पहुंचे हैं। आदत का पता आपको नहीं है। जनता में कहने की बात नहीं है। सब बात सदन में कहने की नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदया, मैं कह रहा था कि गोहाना में मिल के लिए इतनी जोरदार मांग है लेकिन सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पिछले पांच साल से वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। मुझे याद है कि जब प्रोफ़ेसर भोर सिंह स्टेट मिनिस्टर होते थे तब उन्होंने सोनीपत में एलान किया था कि अब जो भुगर मिल लगेगी वह गोहाना में लगेगी और मुख्यमंत्री की तरफ से भी एलान हो गया। लेकिन अब जो दो मिलें लग रही हैं वह एक पलवल और दूसरी भाहबाद में लगेगी। गोहाना का नाम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, गोहाना में दो ही फसलें होती हैं एक गन्ना और दूसरी गेहूं। मिल सिर्फ गन्ने का ही लग सकता है गेहूं की तो मिल नहीं

लग सकती। गालिब को दह माह में तनखाह मिलती थी। एक दफा उसने जफर को लिखा कि लोगों की छह माही एक दफा होती है और मेरी दो छह माही होती है। आप सब लोगों की बात सुनें लेकिन गोहाना के लिए सबसे पहले एलान किया गया था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, गुप्ता जी भी पहुंच गये हैं। लोगों की मांग का ध्यान रखते हुये, इलाके की पैदावार का ध्यान रखते हुये अब छः माही वाली बात पर जा पहुंचे हैं। गोहाना से कुछ गन्ना पानीपत, कुछ सोनीपत और कुछ रोहतक मिलों में जाता है तो यहां तो गोहाने की छः माही तीन बार होती है। तो इस वास्ते इन सभी बातों का ध्यान रखते हुये सरकार को गोहाने के अन्दर एक भूगर मिल अब य लगानी चाहिये और यह जनता की पुरानी मांग है। उनका यह हक भी बनता है अतः सरकार को जनता की आवाज को अब य सुनना चाहिये। जनता को अब य उनका हम मिलना चाहिये। हम देखते हैं कि संतुलित विकास हुआ है पर कुछ इलाकों का विकास हो जाए और कुछ का न हो यह नहीं होना चाहिये। ऐसा न हो कि लोग अपने इलाकों की तरक्की के लिये चिल्लाते रहे और सरकार की तरफ से कोई ध्यान न दिया जाये तो किफर संतुलित लफ्ज बरायेनाम ही रह जायेगा। इन अलफाज के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्रीमती भारदा रानी):
माननीय उपाध्यक्ष महोदया, अभी गर्वनर ऐड्रैस पर डिसक्शन हो

रही है। यहां पर बहुत सी पोलिटिकल बातें कही गईं जोकि गवर्नर एड्रैस के समय में नहीं कहनी चाहिये थी। मैं तो थोड़ी सी बातें कहना चाहती हूं कि मेरे कुछ भाइयों ने अब से कुछ दिन पहले हाउस में कहा और अब भी कुछ कहा, खासकर उन्होंने एग्रीकलचर के बारे में कहा कि जमींदारों की तरफ पिछले 10 सालों में कोई ध्यान नहीं दिया गया और किसानों के लिये कुछ नहीं किया गया। कोई भी आदमी जो आंख खोलकर देख सकता है.....यह ठीक बात है कि अगर हम किसी को क्रिटीसाइल करने लगें किसी की बुराइयां निकालें लगें तो एक हजार बुराइयां निकल जाएंगी। अगर कोई आदमी अपनी ओर झांक कर देखे तो वहां पर निकलेगी लेकिन अपने अन्दर तो कोई झांक कर कम ही देखता है। सभी दूसरों की तरफ झांकते हैं चाहे वह कितनी ही अच्छाइयों का पुतला क्यों न हो। उसके अन्दर हजार नुक्स निकल आते हैं अपने अन्दर देखते हैं तो अपने अन्दर अच्छाइयां नजर अपने लगती हैं। इस बारे में मुझे एक कहानी याद आ गयी एक बार एक चित्रकार ने अपनी कला के सिर पर एक चित्र बनाकर टांग दिया और उसने उसके उपर लिख दिया कि कृपया इस के अन्दर नुक्स बताएं तो बहुत सारे नुक्स उस चित्र के बारे में लोगों ने निकाले। अगर उस चित्र को निकाले गये नुक्सों के मुताबिक देख जाए, माडीफाई किया जाये तो भायद उस चित्र की भाकल ही बदल कर दूसरी हो जाती इतने ज्यादा नुक्स उसके अन्दर निकाले गये। फिर दोबारा उसने पुतला बनाया उस पर भी उसने यह लिख दिया कि कृपया इस के नुक्सों को दूर करिये तो फिर कोई भी आदमी

नुक्स दूर नहीं कर सका तो कहीं बुराइयां निकालना, बुरा कहना बड़ा आसान है लेकिन अच्छा काम करना जिससे सचमुच लोगों को फायदा होता हो और वह भी हमारे जैसे दे 1 में जहां लोग अधिकारों की मांग करते हैं, मांगते हैं चाहते हैं लेकिन जब जरा सा अपना कर्तव्य पूरा करने की बात आती है, जरा सा अपनी ओर से कुछ देने की बात आती है तो चिल्लाने लगते हैं ओर दे 1 के अन्दर राज्यों के अन्दर पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ उसको कौन नहीं जानता है आज का कोई भी इतिहासकार अगर भविष्य के लिये इतिहास लिख कर छोड़ेगा तो इस युग की हरियाणा की और भारत की बातों को सुनहरी अक्षरों में लिखा जायेगा। कोई आदमी जो साच समझ सकता है, जो जानता है कि प्रगति कैसे होती है अगर वह उस युग को देखेगा तो वह भी यह बता सकेगा कि किस तरह से तरक्की का काम होता है किस तरह से काम किया जाता है और काम करने की क्या गति होनी चाहिये और वह गति हमारे जैसे दे 1 में किस प्रकार की घटनाओं से पैदा की जा सकती है। यह एक बहुत समझने और महसूस करने की बात है जैसे कि मैंने कहा कि बुराइयां निकालना बहुत आसान बात है अब कृषि की बात है तो जब हरियाणा बना तो सब जानते हैं कि एक लाख टन अनाज इस हरियाणा के अन्दर बाहर से आता था और आज 15-20 लाख टन अनाज हरियाणा के अन्दर से बाहर जाता है और भायद इस साल इससे भी ज्यादा बाहर जाएगा। उपाध्यक्ष महोदया मुझे याद है सन् 1968 का इलैक् 1न जब मैंने लड़ा तो मेरे अपने ही क्षेत्र में जहां पर कुछ नहरें पहले भी थी, और भी

कुछ सुविधाएं थीं मैं उसके दूसरे हिस्से में जी०टी० रोड से पश्चिमी भाग के हिस्से में जब गयी तो मुझे याद है कि वहां पर ऐसे टीबे थे जहां जीव तक नहीं जा सकते थे। एक तरफ रेतिले टीबे थे और एक तरफ अथाह भरा हुआ पानी था जो न जाने कितने सालों से भरा रहता था। एक बार थोड़ी सी बारिश हुई और वहां पर पानी भरा रहता था। अब हम उस इलाके में गये इस इलाके में टाइम में, और अब उन टीबों का नाम तक न था और पिछले साल इतनी बारिश हुई लेकिन जगह जगह बाढ़ आयी पर वहां पर एक बूंद तक पानी न था। तब पानी गौछी ड्रैन के जरिये बाहर आ गया था। सड़कों के जाल बिछे हुये थे, खेत, खेत के अन्दर बिजली के खम्भे थे और फसलें इतनी बढ़िया खडी थी कि भायद उस इलाके के लोगों ने ऐसी बढ़िया फसलें पहले कभी न देखी होगी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और कहूंगी कि परिवार नियोजन जो इस देश के लिये बहुत जरूरी है, हो सकता है कि इस देश के लोगों को अभी महसूस न हो लेकिन आज अगर दुनियां की गति के साथ हम चलना चाहें, अगर दुनियां की तरफ हम देखते हैं, बहुत से हमारे साथी यहां के और पार्लियामेन्ट के भी यह कहते हैं कि बाहर के देशों में लोगों को यह सुविधाएं हैं। उन्हें बेरोजगारी की पैन्शन मिलती है। बुढ़ापे की पैन्शन मिलती है। दूसरी चीजें मिलती हैं लेकिन दूसरे देशों के लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, यह बात उनमें से किसी ने भी नहीं देखी। दूसरे देशों के लोग कितने बच्चे पैदा करते हैं, कितना परिवार रखते हैं

किस तरह रहते हैं, अपने दूसरे कर्तव्यों का पालन किस तरह से करते हैं यह किसी ने भी नहीं देखा अगर उन देशों के साथ हमें चलना है तो क्या हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। आज स्वयं लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और जब सरकार की ओर से कुछ किया जाता है चाहे उसमें समझा बुझाकर कह लो चाहें जरा सी जोर जबरदस्ती कह लो जहां लोग अपने कर्तव्यों को समझें वहां पर जोर जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती? उपाध्यक्ष महोदया, आज लोग इस बात को न समझेंगे आज नहीं 10 साल के बाद, 20 साल के बाद 50 साल के बाद वह युग आयेगा जब लोगों को जोर जबरदस्ती से उनके कर्तव्यों को समझाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदया यह दूसरी बात है कि अभी इस बात के लिये युग जल्दी था और इतनी जबरदस्ती न होने पर भी लोगों ने बहुत तूल बांधा। हम जहां भी गये और परिवार नियोजन की बात हुई तो लोगों ने कहा कि यह तो बच्चों के भाग्य में है। बच्चे तो अपने भाग्य का लाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे यहां कृषि के अन्दर जो कान्ति हुई है खेत खेत के अन्दर, चप्पे-चप्पे के अन्दर बहुत भारी पैदावार हो रही है। हरे भरे खेत दिखायी दे रहे हैं। यह उनका परिणाम है कि उन्होंने समझा कि जो कुछ भी फायदा हो रहा है यह हमारे बच्चों के भाग्य से हो रहा है। क्या इसमें सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सड़कों का जो इतना जाल बिछाया गया है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जगह-जगह मैं, खेत-खेत में जितने ट्यूबवैल लगाये हैं, उनका कोई

कंट्रीब्यु इन नहीं है। बिजली के खम्भे लगे हुये है इनका कोई कंट्रीब्यु इन नहीं है। खाद का प्रबन्ध किया गया किसी ओर से किया गया, उसका कोई कंट्रीब्यु इन नहीं है। जगह-जगह पर किसानों को कहीं पर बीज की तकावियां, कहीं खद की तकावियां, कहीं पर ट्यूबवैल की तकावियां यह सब दिया गया है इन सब की कोई कंट्रीब्यु इन नहीं है। उपाध्यक्षमहोदया करने को तो बहुत कुछ किया गया है। अभी एक हमारे माननीय सदस्य का उनके ही सदस्य से कांट्राडिक्ट इन हो जाता है कि गुड़ के भाव निर्धारित नहीं हुये जब किसान के घर से मण्डी में आ गया तो भाव जो थे वह नीचे चले गये और जब किसान की ओर से निकल गया तो भाव एक दम ऊंचे चले गये यह बात अब से कुछ समय पहले नहीं थी। किसान के खेत ममें अक्वल बम्पर काप कभी होती नहीं। आज लोग कहते है कि यह किसान की मेहनत का नतीजा है। वह मेहनत उस समय कहां चली गई थी। (इस समय श्री उध्यक्ष पदासीन हुये)। तब क्या किसान मेहनत नहीं करता था? आज अगर किसान मेहनत करता है तो उसको उसकी मेहनत का पूरा सिला मिलाता है ओर उसकी पैदावार की कीमत उसे पूरी दी जाती है और पहले जब जब किसान के घर से वह फसल चली जाती थी तो दूगने, तिगुने और चौगुने भाव हो जाते थे। आज हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि 105 रूपये का भाव सरकार ने दिया और बाजार में 160 रूपये का भाव मिला। अध्यक्ष महोदय, 105 रूपये तो कम से कम कीमत किसान के अनाज की निर्धारित की गई है उसके बाद किसानों ने अनाज अगर बेचा है मुझे मालुम है कि 150

के भाव पर भी किसान का अनाज बिका है। अगर किसान से 150 रू0 के भाव से खरीदा जाता है या 105 रूपये की निर्धारित कीमत में खरीदा जाता है तो उसमें गोदाम का खर्चा देकर, खरीदने वाले का खर्चा देकर औरपैसे का ब्याज देकर अगर 160 रूपये के भाव में बेच दिया तो मैं नहीं समझती कोई ज्यादा है। यह उससे तो अच्छा है कि किसान खरीदने वालों से दोगुना या तीन गुना कीमत पर खरीदता था। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने तो और भी किया। भविष्य के लिये कितनी सोच करके योजनाएं बनाईं। कितनी नहरों का जाल बिछाया और सिंचाई की उठान योजनाएं बनाईं और इसी तरीके से कितने ही ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भविष्य के लिये बना कर छोड़े हैं और भविष्य की आशा के साथ पानी के भी समझौते किये हैं जिनके सालों से समझौते नहीं हो रहे थे। अध्यक्ष महोदय वे लोग जो यह कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है जमींदारों के लिये उन्होंने हरियाणा के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, अपनी तीत के लिये उन्होंने इस बात का सौदा कर लिया। इलैक्ट्रान के दिनों में जब अकाली दल के मैनिफैस्टों में यह बात आई थी तो क्या इन भाइयों में से एक भी सदस्य ऐसा था जो आज बोल रहे हैं कि किसी ने भी अकाली दल के उन मैनिफैस्टों की बात को कन्ट्राडिक्ट किया हो? क्या वह हरियाणा के भविष्य की खिलवाड़ नहीं थी? कहीं भी अखबारों में ऐसी कन्ट्राडिक्ट्रान नहीं आई.....

चौधरी भजन लाल: हमने खूब की है.....(विघन)

Mr. Speaker: Order please. No interruptions.

श्रीमती भारदा रानी: तो वे हरियाणा के जमींदारों के ज्यादा हितैशी हैं। इस तरह की बातें करके सीधे सादे लोगों को इन्हाने बहकाया है और बहुत सी बातें की है। अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ी हैरानी की बात है कि ये लोग गलत कितनी आसानी से बोल जाते हैं। यही गलत बोलने का तरीका इलैक्शन में अपनाते हैं। कहीं अवाह उड़ाना, कहीं और कुछ बात कहना जिस बात से कि वोट मिल सकें वही बात करना और भोले भाले, सीधे सादे लोग उस बहकावों से वोट लिये जाएं। हमारी पार्टी की जो स्कीमज हैं, जो प्रोग्रामज है वही रखे जाते हैं और उन्हीं को कह कर वोट मांगें जाते हैं और उन्हीं पर आज तक डटे हुये हैं तथा भविष्य में भी हमारी पार्टी डटी रहेगी। कोई भी गलत तरीका हम लोग इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने सिरसा की किसी घटना का जिक्र किया लेकिन हमें कहते हुये भार्मा आती है, हम लोग तो अध्यक्ष महोदय कहते नहीं। अभी मेरे हल्के के अन्दर जब इलैक्शन हो रहे थे एक जगह से भाषण देकर चली। वहां मेरा जो रास्ता था वह जनता पार्टी के दफ्तर के बराबर से था और वहां पर बहुत सारी इंटें और रोड़े इक्ठे किये हुये थे और बहुत से लोग उस जगह को घेर कर खड़े हुये थे लेकिन अच्छा हुआ कहते हैं कि भगवान जिसको बचाता है उसको मारने वाला कोई नहीं होता। मैं किसी वजह से उस जगह से बचकर निकल गई और कोई व्यक्ति मेरी गाड़ी में बैठ गया और मैं उसको उस कालोनी से दूसरी जगह

छोड़ने के लिये चली गई और हमारी जो और गाड़ियां थी वह आगे आ गई। उन्होंने मेरी गाड़ी समझ कर एक गाड़ी पर पथराव किया। उसमें मेरा लड़का बैठा था। उसने जब देखा कि यह क्या हो रहा है तो एक दम और गाड़ियां जो आगे निकल गई थी जल्दी से जाकर उनको बुलाकर लाया और अपने बड़े भाई को भी बुला कर लाया और उन्होंने कहा कि यहां पर हमें कुछ घपला लगता है। जब मैंने पूछा तो 25-30 आदमी हमारे वहां पर घेरा बनाकर खड़े हुये थे। मैं आई और रूकी मैंने पूछा तो कि क्या बात है तो उन्होंने बताया कि तरीके से इन लोगों का यह प्रोग्राम था, जल्दी से चलो। तो इस तरीके के हर जगह काम हुये है। तो इन्होंने क्या किया मेरे गांव के अन्दर पोलिंग के दिन बहुत से लोग ट्रकों में भर कर हथियार लेकर पहुंचे और अध्यक्ष महोदय, मैंने हालात को देख कर अपने आदमियों से कहा कि ये लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ भी नारेबाजी लगायें और कुछ भी भद्दे भाब्द इस्तेमाल करें आप लोगों ने बिलकुल प्रोवोक नहीं होना है और बिलकुल चुप लगाये रखना है क्योंकि ये लोग खुद वारदातें करके तुम्हारे गले डालना चाहते है। तो अध्यक्ष महोदय, यह इनका तरीका है। हमारे लोगों ने वैसे ही किया जैसे मैंने उनको समझाया था और उन लोगों ने मुंह से एक सांस भी नहीं निकाली और इधर ये जितने दंगे वहां कर सकते थे, जितनी नारे बाजियां कर सकते थे और जितनी पूअर बातें कर सकते थे वे सब इन्होंने की। यह इनका इलैव इन के टाइम में तरीका है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी जीते या हारे लेकिन हमें इस बात का फख्र है कि

कभी भी ऐसे गलत तरीके, ऐसी गलत बातें, ऐसी झुठी बातें और दे । द्रोहिता की बातें हमारी पार्टी ने न कभी इस्तेमाल की है और न कभी हमारी पार्टी इस्तेमाल करेगी। इन भावों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जयहिन्द।

चौधरी पीर चन्द(बरवाला, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है उसके लिये आपने मुझे टाइम दिया , मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यह अभिभाषण गुप्ता जी की सरकार ने बना कर दिया और राज्यपाल महोदय ने पढ़ा। इसके पहले पेज पर ही उन्होंने लिखा है कि गरीब और दुखी आदमियों को हमने जुट कर उठाया और उनकी माली हालत मजबूत करेंगे लेकिन हमारे बजट के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसकी चर्चा की गई हो। अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि हर समाज को ऊंचा उठाने के लिये साधनों की आव यकता होती है और उसके लिये इस सरकार ने बजट में कोई भी प्रोवीजन नहीं किया जिससे गरीब लोगों की माली हालत दुरूस्त हो सकती। इनका सारा टाइम सिर्फ नारे लगा कर ही खर्च हुआ है अमली रूप में इन्होंने कुछ नहीं किया है। इलैव न में भी ये बीस सूत्री कार्यक्रम की रट लगाते रहे। सन् 71 में भी पार्लियामेंट के अन्दर हमारी प्रधान मन्त्री ने गरीबों को इस बात का वि वास दिलाया था कि गरीबी हटायेंगे और समाजवाद लायेंगे और सदन में मन्त्री महोदय भी यही बात कहते हैं कि हम जो बात कहते हैं उस पर पूरे तौर से अमल करते

है लेकिन आज सन् 71 को बीते 6 साल हो चुके हैं गरीबों की हालत पहले से भी बदतर हैं । पहले कोई गरीब आदमी किसी न किसी तरह अपने कोई साधन जुटा लेता था लेकिन इस सरकार ने उनके वे साधन भी बन्द कर दिये । जैसे कर्जे के बारे में यहां बिल पास हुआ कि गरीबों के कर्जे माफ होंगे । लेकिन किये किसके जाएंगे? उसके किये जाएंगे जिनकी सालाना आमदनी 2400 रुपये से कम होगी । एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि एक मजदूर को सात रुपये की दिहाड़ी मिलनी चाहिये । सात रुपये रोज का मतलब 210 रुपये महीना अगर उसके परिवार के दो आदमी काम करने वाले हैं तो उनकी एक महीने की आमदनी 420 रुपये बनती है उसका परिवार काफी लंबा चौड़ा है जिससे कि उसका गुजारा चलना मुश्किल होता है लेकिन वह कर्जा माफ करने वाली कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि उसके परिवार के सारे सदस्यों की आमदनी 2400 रुपये से ज्यादा बन जाती है । पहले अगर वह किसी साहूकार से कुछ उधार ले लेता था अब उसका वहां पर भी विवास नहीं रहा । तो यह तो केवल कागजों में गरीबी दूर की गई है अमली रूप में कुछ नहीं हुआ है । फिर कहते हैं कि हरिजनों को जमीन दिलाएंगे यह तो हरिजनों की जमींदारों से लड़ाई करवाने वाली बात है । जैसे मैंने पहले कहा कि पहले अगर किसी हरिजन को कर्जे की आवश्यकता होती थी तो गांव में हर आदमी उनका विवास करता था लेकिन अब सरकार ने उनका विवास उठा दिया किसी भी हरिजन पर आज गांव का कोई भी आदमी विवास नहीं करता है । क्योंकि हमारी सरकार ने

ऐसे कानून बना दिये जिससे हम एक दूसरे से अलग हो गये है। इनकी हालत सुधारने के लिए या तो सरकार उनको जमीन दे या किसी किस्म की इंडस्ट्री फैक्ट्री लगवा कर दे या कोई साधन ऐसा हो जिससे ये ऊंचा उठ सकें। तीन ही साधन होते है जि से मुल्क की हालत अच्छी हो सकती हैं – जमीन, इंडस्ट्री और दस्तकारी के काम। दूसरा साधन यह भी हो सकता कि सरकार हरिजनों के लड़को को जो बी0ए0, एम0ए0 या मैट्रिक बेकार बैठे है उनको किसी न किसी जगह सैट किया जाये। मैं सब कमेटी का मेंम्बर हूं। जब डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आती है तो सरकार की तरफ से ताने कसे जाते है और कहते हैं कि हमने सब कुछ दे दिया है लेकिन जहां तक मुझे मालूम हैं, किसी डिपार्टमेंट में भी 30 प्रति शत रिजर्वे इन हरिजनों की पूरी नहीं हुई। किसी में 8 फीसदी है, किसी में 6फीसदी हैं। ऐजुके इन डिपार्टमेंट में हैडमास्टर्ज की 662 पोस्टें हैं, इन में भायद ही हरिजन 12 होंगे। किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी रिजर्वे इन पूरी नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जब हमारे सामने आई तो उसमें क्लास वन, क्लास टू तथा क्लास थ्री इन तीन कैटेगरीज के अन्दर तीसरी कैटेगरी में सिपाही से लेकर इन्स्पैक्टर तक आते है। जब हम सवाल करते है कि इन में सिपाही कितने है, इन्स्पैक्टर कितने है तो जवाब मिलता है 10 या 12 परसेंट। अगर सरकार ने हरिजनों को आबाद करना है तो इनके कोटे परूरे होने चाहिये। बोकर लड़के बहुत फिरते हैं हर किस्त के फिरते है, मैट्रिक फिरते है, बी0ए0 फिरते है लेकिन इनको प्रोत्साहन देनेवाली कोई बात नहीं

हैं अगर किसी लड़के को फिट करने का सवाल आ जाये तो कहते हैं "नाट सूटेबल" ।

स्पीकर साहब, जमीन के बारे में सरकार ने कहा कि हरिजनों के लिए जमीन सरप्लस में निकालेंगे, बजट में भी इसका जिक्र आया है, लेकिन आज तक उस जमीन का पता नहीं चला कि कौन सी जमीन निकली है। किसी को एक इंच भी जमीन नहीं दी गई। यह बात कहना कि जमीन देंगे, इसका नतीजा यह हुआ कि आज हरिजन और जमींदारों में गांव गांव में लड़ाईयां होती है। गांव में ऐसी हालत है कि जमींदार जमीन देने के लिए तैयार नहीं क्योंकि वह जानता है कि जो आदमी एक बार बैठ जाएगा वह काबूज हो जाएगा इसलिए देते ही नहीं। इसलिए इनकी माली हालत ठीक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां तक फैक्ट्रियों का सवाल है, किसी गांव के अन्दर किसी भी हरिजन आदमी की फैक्ट्री नहीं है। जहां तक लेबर का ताल्लुक है, हमारी सरकार ने मजदूर की दहाड़ी 7 रूपये मुकर्रर की हुई है लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. वाले उनको 4 रूपये या साढ़े तीन रूपये दहाड़ी एक औरत मजदूर को देते हैं। क्या वजह है औरत को 4 रूपये मिलते हैं ? स्पीकर साहब, हम चाहते हैं कि हरिजनों के लिए सरकार कुछ करे। हम इनके दिल से कैसे दूर हो गए। अब तक ये हमें लारे देते रहे, जो स्कीमें हमारे लिए बनीं वह कागज पर ही रहीं। इन्होंने कुछ नहीं किया।

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: अब तो जगजीवन राम करेंगे
(व्यवधान)

चौधरी पीर चन्द: हां, वे तो करेंगे। हमारे मुख्य मंत्री माजूद है, ये जो बात कहे, उस पर पूरा अमल होना चाहिए, यह नहीं कि अगर वे कोई बात कहे तो बाद में आधूर ही रह जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगली बात फैमिली प्लानिंग की है। यह तो हमारे मुख्य मंत्री जी की फाखदिली है कि उन्होंने काह कि हमारा दोश है, लेकिन जिस मंत्री महोदय का यह महकमा है और वह यह कहे कि हमारे नोटिस में कोई बात नहीं और न ही हमन ज्यादाती की, न किसी आफिसर ने ज्यादाती की तो बुरी बात है अगर किसी के साथ ज्यादाती की है तो उकस इलाज करें। ऐमरजेंसी के दौदान जो गलत काम हुए है, उस दोश को अपने गले से हटाकर कर्मचारियों के ऊपर लादना चाहते है जबकि यह कार्यवाही इन्होंने खु की है। हमने इसका इतराज किया था कि फैमिली प्लानिंग इस ढंग से नहीं होनी चाहिए। जब डी.सी. की अध्यक्षता में मीटिंग होती थी तो इस बात की चर्चा चलती थी। जए एसी.डी.एम. से पूछते थे कि उनके जिम्मे 500 केसिज थे, 200 क्यो हुए तो वे कहते थे कि पुलिस नहीं मिली। तहसीलदार से पूछते थे कि आपको 400 दिए थे, 300 कैसे रह गए तो वह बोलता था कि पुलिस की कमी है। यह बात जंचने वाली नहीं है कि इन्होंने ज्यादाती नहीं की। गुप्ता जी ने माना कि यह बात हमारे इलम में है और ठीक बात है।

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: और भी है कुछ कहने के लिए? हाथी के पांव में सबके पांव। जब गुप्ता जी ने कह दिया तो सबने कह दिया। (व्यवधान)

चौधरी पीर चन्द: हाथी का पैर यहां कहां टिकेगा, क्या यह हमें पता नहीं है। यह हालत फैमिली प्लानिंग की है। लोगों को काफ़ी ज्यादा परेशानी है और उसका नतीजा गवर्नमेंट के सामने हैं इसका इलैक्ट्रॉन पर बहुत बुरा असर हुआ है। एक फायदा यह हुआ कि आप लोगों ने ऐमरजेन्सी लगाई और इस ऐमरजेन्सी का दुरुपयोग किया गया है। अगर ऐमरजेन्सी की बात देना में न होती तो तुम्हें कोई खतरा नहीं था फिर भी लोगों ने अपनी कुसियों बचाने के लिए ऐमरजेन्सी का दुरुपयोग किया है। अगर किसी हलके का एम.एल.ए. चन्दा नहीं देता था तो उसको मीसा के तहत अन्धकार कर दिया। सरकार की यह नीति अच्छी नहीं है। मैं आप लोगों से यह कहने के लिए खडत्रा हुआ हूँ। कि आप लोगों ऐसे कदम न उठाए, आगे के लिए कहूंगा कि कोई गलीत काम न करे, हम आपके साथ हैं पानी के बारे में यहां चर्चा हुई और कहा कि पंजाब वालों ने मैनिफैस्टों में लिख दिया और हमने उसका समर्थन किया। सरकार आपकी है, आपको जनता में विश्वास देना चाहिए कि हम हर तरह हरियाणा के पानी पर लड़ेंगे जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक अपना हिस्सा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर हरियाणा के हित की कोई बात होगी तो हम इनके साथ हैं लेकिन

अगर ये किसी काम में कोताही करेंगे तो जनता इन्हें बख्शोगी नहीं। स्पीकर साहब, आज से दो साल पहले इस हाउस में फाजिल्का और अबोहर की बात आई थी। हमने उस समय इस सरकार से कहा था कि सैन्टर की सरकार कांग्रेस की है, पजाब की सरकार कभी कांग्रेस की है और हरियाणा की सरकार भी कांग्रेस की है इसलिए आपको फाजिल्का और अबोहर हरियाणा को लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यही नहीं, स्पीकर साहब, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी यहां गर्दन नीची करके बैठा करते थे। (विधन) लेकिन उसे बावजूद भी फाजिल्का और अबोहर नहीं लो पाए मुझे तो डर है कि कल को ये हमें दोश देगे और कहेंगे कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं लेने देती।

स्पीकर साहब, पंडित चिरंजी लाल जी कह रहे थे हमने बड़ी तरक्की की है। चौधरी अमर सिंह जी भी कह रहे थे कि हमने बहुत तरक्की की है। हम मातने है इनकी बड़ी तरक्की हुई है क्योंकि पहले ये यहां बैठा करते थे अब वहां जा बैठे। ये गए ही इ वि वास में कि मिनिस्टर बनूंगा। खैर, इसमें दो राय नहीं कि इनकी तरक्की हुई है और इन्होंने चन्दा इकट्ठा करके, अफसरों को डांट मार करके काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है। (विधन)

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, मैं पर्सनल ऐक्सपलेटन देना चाहता हूं। जो आनरेबल मैम्बर बोल रहे हैं वे जारा अपने गरेबान में झांक कर तो देखे। ये खुद भी ठेके मकान में रहते

हुए दूसरों पर पत्थर फेकर रहे है। (विधन) मैने कोई चन्दा इकट्ठा नही किया, यह बिल्कुल गलत बात है। (विधन)

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, श्री अमर सिंह जी जब यहां बैझा करते थे तो कहा करते थे गरीब आदमी तो हमे मा मारा जाता है। इनकों रोजगार नही मिलता। एक बार तो इन्होने यह भी कहा था कि एक हरिजन औरत ने अपनी चूड़ी तौड़ी और पीस कर बच्चों को खिलाई जिसकी वजह से सारा कुनबा मारा गया। आज कहते कि सब मालोंमाल हो गए। बड़ी हैरानी की बात है।

स्पीकर साहब, जहां तक प्लाटस का सम्बन्ध है, इसमें कोई दो राय नही कि प्लाटस मिले है लेकिन इसमें भी कोई राय नही कि इनसे कुछ गलतियों भी हुई है। कही तो प्लाटस खड्डे में दे दिए है, कही दूर दे दिए है, कही कुछ किया है और कही कुछ किया है। खैर मै इन बातों में न जाते हुए मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे प्लाट के प्लाट र रह जाएं, उन पर मकान भी बनने चाहिये और उन पर मकान तभी बनेगे जब पैसा होग। कही ऐसा न हो कि कुछ दिनों के बाद उन पर जमींदार अपने डंगर बांधने भुरू कर दे या उन्हें जमीन में भामिल कर ले। अगर इस काम को यह सरकार जल्दी से करेगी तो हो सकता है कि जनता इनके पिछले किए हुए जुल्मों को भूल जाए। यदिये ऐसा नही करेगे तो इनके पिछले पाप भी रहेगे और ये भी रहेगे।

स्पीकर साहब, आज फमिली प्लानिंग के आपरे ांज की बड़ी चर्चा हुई। क्वे चन अवर में भी यह बात आई और बाद में भी आई और हमारे मंत्री महोदय ने यह वि वास दिलाया कि जिन केसिज में नाजायत आपरे ांज हुए है, जिस ऐसे लोगों के आपरे ान हुए है जिनके बच्चे नहीं थे, उनकी वे पड़ताल करायेगे।

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं। ये लोग यह बात कहते तो है कि बिना बच्चे वालों के आपरे ान हुए है लेकिन जब हम इनसे लिखकर मांगते है तो लिखकर ये देते नहीं। आज तक एक भी केस की ि ाकायत लिख कर हमारे पास नहीं आई है (विधन)

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अब अपनी जगह लेता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रका ा गर्ग (थानेसर): स्पीकर साहब, मैं गवर्नर साहब के अभिभाषण पर बोलने से पहले थोड़ा सा कुछ और अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाईयों ने नसबंदी का मसला लेकर के अपनी तकरीर को इसी बात से भुरू किया और इसी बात पर जाकर के खत्म किय। यही मसला लेकर ये इलैव ान में गए। इसमें कोई भाक की बात नहीं कि जनता ने इनकों कामयादी दी और दिल्ली के अन्दर इनकी सरकार इनकी सरकार बनी। उस सरकार को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी और अपनी

सरकार की तरफ से पूरा सहयोग देने का और लेने का वचन दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी स्पीकर साहब मेरे भाईयों ने एक बात हाउस के सामने रखी कि चूंकि लोक सभा में जनता पार्टी के ज्यादा नुमांयदे चुनकर आए हैं इसलि असैम्बलीज के इलैक्शन भी कराए जायें चाहिए। इसके बारे में स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा अपने मैम्बर साहिबान से एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं। मैम्बर साहेबान को पता होगा कि सन् 1972 से पहले असैम्बली और लोक सभा के चुनाव इकट्ठे होते थे और उस वक्त यह देखने में आता था कि कुछेक भाई दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ते थे। कई बार ऐसा हाती थक वे लोकसभा की सीट तो जीत जाते थे लेकिन असैम्बली की हार जाते थे अझैर यदि असैम्बली की जीत जाते थे तो लोकसभा की हार जाते थे। लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि वे जीती हुई सीट से मुस्तफी हो जाते थे। यह तो लोगों का राय देने का अलग अलग तरीका है। वे लोक सभा की सीट का अलग महत्व समझते हैं और असैम्बली की सीट का अलग महत्व समझते हैं यह कह देना कि यहां से भाग जाओ, यह कोई अच्छा नहीं लगता आपने आज का वातावरण देखा। अगर ये भाई ताकत में हो और जो मेरे आदरणीय मैम्बर साहबान ने यहां विचार रखे हैं वे बड़े मगरूरपने से रखे हैं। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में यह कहना कि वे घमन्डी थे, उन्होंने जो कुछभी यहां किया वह मुख्य मंत्री की हैसियत से किया, उन्होंने हरियाणा की भलाई के लिए किया। चीफ मिनिस्टर हाते हुए किसी व्यक्ति की कोई बुराई भी हुई है तो वह दूसरी बात है मेरे नोटिस में तो ऐसी बात भी

नहीं है। आपने इनका रवैया देखा ही है कि कांग्रेस सरकार बहुमत में होते हुए ये दस पन्द्रह आदमी हमलवावर की तरह से सिर पर चढ़े आ रहे हैं। अगर यही इनका हाल रहा तो जब जनता के सामने जाओंगे तब आपको पता चलेगा। मेरे आदरणीय साथी दौलत साहब ने तो चीफ मिनिस्टर साहब को चैलेन्ज ही कर दिया कि जनता से एजीटे इन करायेगे और एजीटे इन में जनता का साथ देगे लेकिन मेरे वे दोस्त इसबात को न भूले कि जनता अब उनके बहकावले में नहीं आयेगी। वह तो एक दफा आ ली। अगर आप यह समझते हैं कि आपके बहाव में जनता आयेगी, वह अब आगे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं करेगी। इन्क है आप चन्द आर.एस.एस. के लड़कोंसे भारारत करा सकते हैं, वे करेगे। जैसा कि दौलता साहब ने यहां फरमाया क्योंकि दौलता साहब साफगोयी आदमी हैं वे एक उनको यह कहा गयाहो कि यह बात बहार नहीं कहनी लेकिन वे साफ दिल आदमी हैं, वे अपने मन में कोई बात नहीं रोक नहीं सकते, उन्होंने हाउस में चैलेन्ज कर दिया और उनका चैलेन्ज मन्जूर करते हैं। जनता ने इनको इस इलैक् इन में वोट दिये औ और लोक सभा में इनका बहुमत है। प्राइमिनिस्टर मोरार जी की हम इज्जत करते हैं, आदर करते हैं लेकिन जहां आप ये इल्जाम लगाते हैं कि इन्दिरा गांधी ने यह कर दिया वह कर दिया और इन्धिरा गांधी ने कानी ताक जो यहां होता था उसकी आवाज पहुंचती थी यह गलत बात है। अगर आप जैसे ही भाई मोरार जी के सहयोगी होंगे तो उनका भी कल्याण नहीं

हो सकते। आप जैसे भाई उनको म वरा देने वाल `हुए जो कि ऐसा सोचते है तो दे ा का क्या हाल होगा?

स्पीकर साहब मै आपकी वसायत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह का रैवैया मेरे दोस्तों ने अपनाया है यह अच्छा नहीं है। लोक सभी और असैम्बली इलैक् ान अलीग-अलग है। जब असैम्बली के इलैक् ान हुए होंगे तो उन्होने अपना असैम्बली का नुमाइन्दा चुना होगा और उसका वोट दिये होंगे। पीर चन्द जी भी हा सकते है और कोई दूसरा भी हार सकता है। लेकिन आप ऐसा घमण्ड करें यह उचित नहीं है। यह आपकी विरासत नहीं है। जो लोग विरासत समझते है वह गलत समझते है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो एड्रैस गवर्नर साहब ने पे ा किया है उसका मै स्वागत करता हूं लेकिन कुछ मेरे अपने हल्के की मांगे है उनके लिए मै अर्ज करना चाहता हूं। मै आ ा करता हूं कि सी.एम.साहब उनकी तरफ अव य ध्यान देगे।

लाडवा बस स्टैण्ड का मसला अभी चल रहा है। पता नहीं किस जगह पर है। वह कहां रूका हुआ है। मै ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से आपकी वसात से अर्ज करूंगा कि उसका जल्दी से जल्दी इन्तजाम किया जाये। दूसरी बात यह है कि वर्मा साहब की तरह मै भी होता तो मेरा भी काम हो जाता। ये पहले भी मजा

ले गये और जब भी मजा ले गये। बाहर भी रह गये, जेल में भी नहीं गये और लड़के को भी एच.सी.एस. करवा गये। (विधन)

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ये कहते हैं कि एच.सी.एस. की जो लिस्ट है वहा तो दिल्ली से अप्रूव हो कर आती है ओर एक तरफ कहते हैं कि छाती पर पैर रख कर आ गया। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौनसी बात सही है?

श्री ओम प्रकाश गर्ग: आदरणीय वर्मा जी अपना काम भी करवाते रहे और जेल में भी नहीं गये। राम लाल जी को जेल भिजवा दिया। चौधरी बसी लाल से भी उन्होंने काम लिया। चौधरी शिव राम वर्मा तो ठाडी और लम्बे थनों वाली भैंस का दूध पीत रहे। मुझ तो खुशी है कि वे दनिमन्द आदमी हैं। वे बच्चे भी रहे, लड़का भी एच.सी.एस. बनवा लिया। अब इन भाइयों को दिखाने के लिए कह दिया कि यह तो अपनी हिम्मत से आया है।

स्पीकर साहब, पहले लाडवा का पी.एब्ल्यू.डी. का सब डिवाजन थानेसर के साथ होता था लेकिन अब वह करनाल के साथ लगा दिया है। मेरी आपसे दरखास्त है कि अब सारे हल्के कुरुक्षेत्र के साथ है अब उसको भी करनाल की बजाए कुरुक्षेत्र के हस्पताल की बिल्डिंग इतनी भानदार है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता लेकिन उसमें जो स्टाफ लगा हुआ है उसमें अभी तक कोई बढ़ौतरी नहीं हुई। जितनी भानदार बिल्डिंग बनायी गई

है वैसा ही वहां पर स्टाफ भी भिजवाया जाये। लाडवा में सी.एम. साहब और सरदार हरपाल सिंह ने जो हस्पताल बनवाया है उसके लिए वहां की जनता धन्यवादी है। उन्होंने वहां एक्सरे और लब्रोटरी का भी प्रबन्ध किया है लेकिन एक्सरे खींचने के लिए हफ्ते में एक दिन के लिए एक आदमी आता है इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि उन दोनों चीजों के लिए आदमी दिया जाये। अगर दोनों चीजों के लिए आदमी नहीं दिया जायेगा तो वहां पर काम ठीक नहीं होगा।

मैंने लाडवा बस स्टैन्ड के बारें में अर्ज किया। कुरुक्षेत्र में जो बस स्टैन्ड के लिए जगह है वह बहुत थोड़ी है। उसे आसपास जो जगह उसको ले लिया जाये क्योंकि कुरुक्षेत्र ऐसी महत्वपूर्ण स्थान है जो हिन्दूस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्दर म अहूर है। वहां पर सूर्य ग्रहण के मेले के अवसर पर काफी स्थानों से लोग आते हैं। अब तो वहां पर जगह मिल सकती है। वहा आस पास जगह खाली पड़ी है, उसको बढ़ाना चाहेता वह बढ़ाया जा सकता है।

तीसरी रिक्वेस्ट मेरी पीपली बस स्टैन्ड के बारें में पीपली जी.टी. रोड़ पर है। वहां पर बस स्टैन्ड तो बना दिया लेकिन वह भी ता भौडो में यानी टीन के भौडों में है। खैर वहां भी पक्की बिल्डिंग बना दी जाये तो अच्छी बात होगी। लेकिन मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। कि वहां वर्क गाप होनी जरूरी है। पीपली एक सैन्ट्रल प्लेस है। अगर वहां वर्क गाप बन

जाये तो तो जी.टी. रोड बसे पास हो कर जी है वे ठीक हो सकती है। दूसरी मेरी अर्ज यह है कि लाडवा से दिल्ली के लिए सुबह साढ़े पांच बजे चण्डीगढ़ से इन्दरी और करनाल हो कर लाड़वा जानी चाहिए। लाडवा से अम्बाला के लिए भी चलनी चाहिए क्योंकि अम्बाला में कपड़े की बहुत अच्छी मार्किट है क्योंकि वहां पर हमारे बजाज काफी तादाद में कपड़ा लेने के लिए जतो है लेकिन उनको वापिस जाते वक्त दिक्कत होती है।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा इलाका जो नहरी इलाका कहलाता है वह ज्योतिसर क पास का कहलात है वहां के का तकारों को भी पानी मिलना चाहिएस।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9-30 A.M. tomorrow.

(18.30 बजे)

(The Sabha then *adjourned till 9-30 A.M. on Tuesday, the 29th March, 1977)